

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 11}

नई विल्लो, शरिवार, मार्च 17, 1984/फाल्गुन 27, 1905

No. 11

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 17, 1984/PHALGUNA 27, 1905

इस भाग में भिन्न एष्ठ संस्था दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रक्षा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग 11—क्षण्ड 3—उप-क्षण्ड (ii)

PART II-Section 3-Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) पारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किये गये साविधिक ग्रादेश त्रौर अधिसूचनाएं *fritutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 2 मार्च, 1981

मुचना

--नोटरीज नियम, 1956 के नियम 7 के अनुसरण में म , द्वारा यह गूचना दी जाती है कि श्री ग्रव्णानन्द मिश्रा, बीत अजरी मार्ग, कलकसा-700026 ने जन्त प्राधिकारी क.' क्रानयम 4 के अधीत एक आयेदन एन बात के लिए दिया है कि उंगे क्राना के कालीधाटकेंद्र में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुव क्राया जाए,

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के हैंप में तियुक्ति पर रिसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाणन के नौयह दिन के भीतर लिखिल रूप में मेरे पास भेजा आए।

> [संब 5(14)/82-न्याब] एस० गप्तु, सक्षम प्राधिकारी

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & CO. AFFAIRS
(Department of Legal Affairs)
New Delhi, the 2nd March, 1984
NOTICE

S.O. 785.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules,

1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Krishna Nand Misra, Advocate, 109/6, Hazra Road, Calcutta-700026 for appointment as a Notary to practise in Kalighat areas of Calcutta.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned with fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(44)/82-Judl.]

S. GOOPTU, Competent Authority

GISTERED NO. D. (D. N.)-73

(कम्पनी कार्य विभाग)

(कम्पनी विधि बोर्ड)

नई दिल्ली. 18 मार्च, 1984

1984 का अदिण संख्या 3

का० आ० 786.—नम्पनी विधि बोई (खण्ड पीट) नियम 1975 के नियम 2 (व) द्वारा प्रदत्त सनितयों का प्रयोग करते हुये कम्पनी विधि वोई ने श्री जे० एस० नेगी (केन्द्रीय कम्पनी विधि सेवा के ग्रेड 4 अधिकारी) को 8 विमम्बर, 1983 से कथित नियमों के सहैग्यों के निये,

अस्म व कहमीर, हरियाणा, द्विमानल प्रदेण, पंजाब, राजस्थान, प्रहाण, प्रदेण, व गए णासिन द्वार दिस्ता च नर्न्डागढ़ कर नर्न्डागढ़ के निर्देश के स्थानान्तरण पर, खण्ड पीठ अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है।

[फा॰ मंख्या 2/7/84-सी॰ एल॰ 5]

(Department of Company Affairs)-

(Company Law Board)

New Delhi, the 8th March, 1984

ORDER NO. 3 of 1984

S.O. 786.—In exercise of the powers conferred by Rule 2(f) of the Company Law Board (Bench) Rules. 75, the Company Law Board has appointed Shri Z. S. Negi. (a Grade IV Officer of the Central Company Law Service) as Bench Officer for the Northern Region comprising the States of Jammu & Kashmir, Haryana, Himachal Pradesh, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh and Union Territories of Delhi and Chandigarh for the purposes of the said Rules with effect from 8th December, 1983 vice Shri H S. Bhatta transferred.

[File No. 2/7[84-CL, V]

1984 का आदेश संख्या 4

का० आ० 787.—कम्पनी विधि बोर्ड, (खण्ड पीठ) नियम 1975 के नियम 2(च) द्वारा प्रदन्त शिक्तयों का प्रयोग करने हुये, कम्पनी विधि बोर्ड ने श्री एस० श्रीनिवासा गुप्ता (केन्द्रीय कम्पनी विधि सेचा के ग्रेड 4 अधिकारी) को 14 दिसम्बर 1983 से श्री आर० वैकंटारमण के त्याग पव देने से रिक्त स्थान पर कथित नियमों के उद्देण्यों के लिये आन्ध्र प्रदेण, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और संघ णामिन क्षेत्र पांडिचेरी और लक्षद्रीपों को समाबिष्ट करते हुये दक्षिण क्षेत्र के लिये खण्ड पीठ अधिकारी नियुक्त किया है।

[फा॰ सं॰ 2/7/84-सी॰एल॰ 5]
ए॰ एम॰ चक्रवर्ती, सचिव
क्रियनी विधि बोर्ड

ORDER NO. 4 OF 1984

S.O. 787.—In exercise of the powers conferred by Rule 2(f) of the Company Law Board (Bench) Rules, 1975, the Company Law Board has appointed Shri S. Sreenivasa Gupta (a Grade IV Officer of the Central Company Law Service) as Bench Officer for the Southern Region comprising of the States of Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka, Tamil Nadu and the Union Territories of Pondicherry and Lakshadeep Islands for the purposes of the said Rules with effect from 14th December, 1983 vice Shri R. Venkataraman resigned.

[File No. 2|7|84-C.L. V.]

A. M. CHAKRABORTI, Secy.

Company Law Board,

गृह मंत्रालय

वर्ड दिल्ला, 25 फरमरी, 1981 मुद्धिप व

का०आ० 788.--भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड (3) उपवाण्ड (ii) पृष्ठ 3122 पर प्रकाणित, भारत सरकार, गृह मंद्रालय की अधि-सूचना संख्या का०आ० 3044 दिनांक 21 जुलाई, 1983 में जहां कही भी 'वरिष्ठ' ग्रव्य आया हो, उसके स्थान पर 'अनिरियन' शब्द पहा जाए।

[स॰ 12011/11/83-एफ॰ 3] एक॰ एस॰ गात्रा, अवर मनिय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 25th Fobruary, 1984 CORRIGENDUM

S.O. 788.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. S.O. 3044 dated 21st July, 1983 published at page 3122 in Part II, Section (3). Sub-Section (ii) of Gazette of India dated 6th August, 1983 for the word "Senior" wherever it occurs, read "Additional"

[No. 12011/11/83-F. III] H. S. GABA, Under Secy.

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विनाग

नई दिल्ली, 3 मार्च, 1984

का॰आ॰ 789.--केन्द्रीय सरकार,पंशन अधिनियम, 1871 (1871 ॰ 23) की धारा 15 द्वारा प्रदन्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, बकाया संबाय (नामनिर्देशन) नियम, 1983 का और संशोधन कर् लिए निश्नलिखिन नियम बनाती है, अर्थाह्--

- (1) इन नियमी का संक्षिप्त नाम पेणन ककाया संद।
 निर्देशन) (संशोधन) नियम, 1984 है।
 - (2) ये राजपन्न मैं प्रकाशन की नारीख को प्रवृत्त
- 2. पंजन बकाया संवाय (नामनिर्देशन) नियम, म 5 के उपनियम (1) में, "छह माम" शब्दों के स्था; ।", जब्द रखें जाएंगे।

[मं॰ 2] प्रशन थानट/83 नि॰ J.] एस॰ आर॰ अहं र, उप सिषय

िहराण: वेंशन यकाया संकाय (नामनिर्देशन) नियम 1583 को० आ० 3478 मारी वा 10-9-1983 के अप में प्रकाशित किए गए थे।

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

New Delhi, the 3rd March. 1984

- S.O. 789.—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Pensions Act, 1871 (23 of 1871), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983, namely:—
- 1. (1) These rules may be called the Payment of Arrears of Pension (Nomination) (Amendment) Rules, 1984.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983, in Rule 5, in sub-rule (1), for the words "six months", the words "one year" shall be substituted.

JNo. 26(3)-Pension Unit/83-Vol. III

S. R. AHIR, Dy. Secy.

Note.—The Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983, were published as S.O. No. 3478 dated 10th September, 1983.

योजना आयोग

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 1984

कार प्रार 790 — योजना प्रायोग की विनांक 30 नवम्बर, 1983 की समसंक्ष्यक प्रधिसूचना के कम, में डार धार्टर एसर गुलाटी की प्रध्यक्षता में गठित निगमित कर से संबंधित प्रध्ययन दल की धवधि बार माह की धवधि के लिए प्रीर बढ़ायी जाती हैं।

> [संक्या ए-12034/7/83-प्रशासन-1] के० सी० प्रग्रवाल, निदेशक (प्रणासन)

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 6th February, 1984

S.O. 790.—In continuation of Planning Commission's Notification of even number dated 30th November, 1983, the term of the Study Group on Corporate Taxation in India constituted under the Chairmanship of Dr. I. S. Gulati is further extended for a period of four months.

. [No. A. 12034/7/83-Admn. I]

K. C. AGARWAL, Director (Administration)

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 1984

आय-कर

का० अ१० ७ १ १ . -- आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 को उपधारा (23ग) के खण्ड (iv) द्वारा प्रवत्न णिक्सयों ; का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्बारा, उक्त खण्ड के प्रयोजनायें, "मध्य प्रदेण महिला कल्याण समिति, भोषाल" को कर निर्धारण-वर्ष 1983-84 से 1985-86 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधि-सुचित करती है।

[#io 5595/फा० स० 197/142/82-आ॰ কা॰(fao-I)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 23rd January, 1984

INCOME-TAX

S.O. 791.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Madhya Pradesh Mahila Kalyan Samiti. Rhopal" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1983-84 to 1985-86

INO. 5595/F. No. 197/142/82-IT(AI)7

आय-कर

का॰आ॰ 792.--आयकर अधिनियम, 1961 (1961का नत) की धारा 10 की उपधारा (23म) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदन्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय भरकार,ए.हद्द्वारा उक्क आण्ड के प्रयोजनार्थ, दि० सी० वी० रामस्थामी अध्यर फाउण्डेणन" को कर निर्धारण ,वर्षे 1983-84 से 1985-86 के अन्तर्गत आने वाली अधिक के लिए अधिसचित करनी है।

[ন০ 5396/फा॰ ন০ 197/24/৪৪-आ॰कः।৹(নি০-1)]

INCOME-TAX

S.O. 792.—In exericse of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The C. P. Ramaswami Aiyar Foundation" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1983-84 to 1985-86.

[No. 5596/F. No. 197/24|83~IT(A]]

नई दिल्ती, 16 फरवरी, 1984

आय-कर

कारुआर 793.—आयकर अधिनयम 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23म) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदल्त मिक्नयों का प्रयोग करने हुए केखीय सरकार, एतद्इरा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ ''इण्डों-जर्मन सोगल सर्विस सोसाय्टी, नई विल्ली' को कर निर्धारण वर्ष 1983-84 में 1985-86 के अनगंत आने वाली अवधि के सिए अधिस्चिन करती है।

[मं० 5635/फा० मं० 197 /191/82-आ० क० (नि०-1)]

New Delhi, the 16th February, 1984

INCOME-TAX

S.O. 793.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-vection (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Indo-German Social Service Society, New Delhi" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1983-84 to 1985-86.

[No. 5635/F. No. 197;191]82-1T(A1)]

आय-कर

का॰ अा॰ 794.--आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (iv) द्वारा अवन्त शक्तियों जा प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार एनद्वारा "नेशनल कोनिसल कार को-आपलेटिय ट्रेनिग" को उक्त धारा के प्रयोगनार्थ कर- निर्धारण वर्ष 1982 83 मे 1981-85 के अनर्गन आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[मं॰ 5636/फा॰ मं॰ 197/175 /81-आ॰ क॰ (नि॰-!)]

INCOME-TAX

S.O. 794.—In exercise of the powers conterred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Incometax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "National Council for Co-operative Training" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1982-83 to 1984-85.

[No. 5636 (F. No. 197/175/81-JT(AI)]

आय-कर

का०आ० 795, --- आय-कर अधिनियम की घारा 10 की उपधारा (23ग) के ऋण्ड (iv) द्वारा प्रवत्न गिक्तियों की प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय सरकार एनव्हारा "जे० एन० टाटा इंडीमेट बस्बई" को उक्त धारा के प्रयोजनार्थ कर-मिर्धारण वर्ष 1984-85 में 1986-87 एक के अन्तर्गत जाने वार्ता अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[मं० 5638/फा० मं० 197 /132 /80-आ० क० (fao-J)]

INCOME-TAX

S.O. 795.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "J. N. Tata Endowment Bombay" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1984-85 to 1986-87.

[No. 5638/F. No. 197[132]80-F1(AD]

नई दिल्ली, 20 फरबरी, 1984

आय-कर

कां • आ • 796. — आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा राज की जपधारा (23ग) के खण्ड (iv) हारा प्रदन्त मिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतर्द्धारा उक्त खण्ड के प्रयोगनार्थ, "एसीसिएशन आफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अण्डस्टेकिंग्स, नई दिल्ली" को कर निर्धारण वर्ष 1983-84 से 1985-86 तक के अन्तर्गत आने वाली अवधि के "ए अधिमुचित करती है।

[रां० 5651/फा॰ सं॰ 197/62/83-आ॰ क॰ (नि॰-1)]

New Delhi, the 20th February, 1984

INCOME-TAX

S.O. 796.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Association of State Road Transport Undertakings, New Delhi" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1983-84 to 1985-86.

INO. 5651/F. No. 197/62/83-FF(A1)]

आय-कर

का॰आ॰ 797. -- आयकर अधिनियम, 1961 (1961 को 13) की बारा 10 की उपधारा (23म) के खण्ड (iV) हारा प्रदल्त मिन्तमों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतन्द्वारा "इक्यूमें निकल किश्चियन सैण्टर संगलीर" को उन्त धारा के प्रयोजनायं कर-निर्धारण वर्ष 1978-79 से 1984-85 तक के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसृचित करती है।

[सं॰ 5652/फा॰सं॰ 197/67/79-आ॰क॰(नि॰-l)]

INCOME-TAX

S.O. 797.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Ecumenical Christian Centre, Bangalore" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1978-79 to 1984-85.

[No. 5652]F. No. 197[67]79-[T(AI)]

आय-कर

का०आ० 798. — आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 433 की धारा 10 की उपधारा (234) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "सेंट म्लोमेफ स एउस्केशनल एण्ड मेडिकल रिलीफ सीलाईटी" की उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, कर-निर्धारण वर्ष 1982-83 से 1981-85 तक के अन्तर्गत आने वारी अवधि के चित्र सिंधिनित करती है।

[मं॰ 5653/फा॰ सं॰ 197/47/83 आ॰ क॰ नि॰-])]

INCOME-TAX

S.O. 798. In exercise of the powers conferred by cluase (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies St. Joseph's, Education and Medical Relief Society" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1982-83 to 1984-85.

[No. 5653]F. No. 197[47]83-IT(A1)]

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1981

आरा-कर

कारआर० १५९. — आयकर अधितियसं. 1961 (1961 को 43) की धारा 10 की उपधारा (23व) के खण्ड (iv) हारा प्रदेश मक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्शारा, उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "कमला नेहरू मेमोरियल हास्पिटल सोमाईटी, नई दिल्ली, को कर निर्धारण-वर्ष 1983-84 से 1985-86 तक के अंतर्गत आने वाली अविधि के लिए अधिसुचित करती हैं।

[स॰ 5659/फा॰ स॰ 197 /103 /83-आ॰ क॰ (नि॰-I)]

New Delhi, the 22nd February, 1984

INCOME-TAX

S.O. (799.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Kamala Nehru Memorial Hospital Society, New Delhi" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1983-84 to 1985-86.

[No. 5659]F. No. 197[103]83-[T(AL)]

आय-कर

कार आर 800. -- आगकर अधिनिधम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की अपधारा (23म) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदश्न पाक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय भरकार, एनद्द्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "इंडियन एसोसिएमन फार रिसर्च इन नेणनल इन्लाम एण्ड बैन्थ, नई दिल्ली" को कर निर्धारण-वर्ष 1982-83 में 1984-85 तक के अंतर्गत आने बाली अबधि के लिए अधिमूचिन करती है।

[গঁ০ 5660/फा॰ म॰ 197 /129 /৪৫-আওঁ ফা॰ नि०-**]**)]

INCOME-TAX

S.O. 800.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Indian Association for Research in National Income and Wealth, New Delhi" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1982-83 to 1984-85.

[No. 5660]F. No. 197[129]82-IT(A1)]

नई दिस्ली, 25 फरवरी, 1984

आय-कर

कार आरु 501. -- आयकर बिधिनियम, 1961 (1961 का 13) की धारा 80छ की उपधारा (2) (ख) द्वारा प्रदन्त जातितयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतदहारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "श्री क्ल्रेयमर मन्दिर, क्रास्पा (क्लांटक)" की सम्पूर्ण कर्नाटक राज्य में विद्यान सर्वेजित पूर्वा स्थल के था में अधिपूर्ण चन करती है।

[सं॰ 5663/फ़ा॰ सं॰ 176/79/82-आ॰ क॰ (नि॰-1)}

New Delhi, the 25th l'ebruary, 1984

INCOME-TAX

S.O. 801.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2)(b) of Section 80-G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notities "Sri Kundeshwara Temple, Kundapura (Karnataka)" to be a place of public worship of renown throughout the State of Karnataka.

[No. 5663 F. No. 176|79|82-IT(AI)] বুই বিশ্লী, 29 फरवरी, 1984

कार अहर 803. - - आपकर अधितियत, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपक्षारा (23म) के खण्ड (V) द्वारा प्रदल्त फॉक्तवों का प्रयास करते क्रुंग केन्द्रीय गरकार, एन्द्रारा, उपन खण्ड के प्रयोजनाये, "टीर बंहि एसर चेरिटीज" को कर निर्धारण वर्ष 1984-85 आर 1985-86 के अमरीत आने काली अवधि के लिए अधिमुख्ति करती है।

[म्० 5672/फा० सं० 197 / 5 /84-आ० क० (नि०-1)]

New Delhi, the 29th February, 1984

INCOME-TAX

S.O. 802.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifier T. V. S. Charities" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1984-85 and 1985-86.

[No. 5672|F. No. 197|5|84-UT(A1)]

आय-कर

कार गर 803. -- आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपवारा (234) के खण्ड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, के दीव सरकार, एनद्दारा, उनन खण्ड के प्रयोजनार्थ, "कलायस्टर्ड कारमल, मंगलोर" को कर निर्धारण वर्ष 1982-83 से 1984-85 "तक के अतर्गन जाने वाली अवधि के लिए अधिसुन्तित करती हैं।

[म॰ 5671/फा॰ स॰ 197/127/82-आ॰ क॰ (नि०-1)]

INCOME-TAX

S.O. 803.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Cloistered Carmal, Mangalore" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1982-83 to 1984-85.

[No. 5671/F. No., 197/127/82-IT(AI)]

आय-कर

का०आ० 80-3. ---आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23म) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदश्त फक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एत्ट्द्रारा, उक्त खण्ड के प्रयोगनार्थ, "दि भोणल यक्त एण्ड निसर्च सेंटर, अजमेर (राजस्थान)" को कर निर्धारण वर्ष 1982-83, 1983-84 तथा 1984-85 के अंतर्गत आने बाली अविध के लिए अधिमुचित ,करनी है।

[मं० 5669/फा० ग० 197/81/82 आ० क० (नि**०-I**)]

INCOME-TAX

S.O. 804.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The Social Work & Research Centre, Aimer (Rajasthan)" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1982-83, 1983-84 and 1984-85.

INo. 5669[F. No. 197[81]82-IT(A1)]

का अा 805. आयकर अधिनयम, 1961 (1961 का 4:) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (iv) द्वारा प्रकृत प्राप्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एत्यूद्वारा, उसत खण्ड के प्रयोजनार्थ, "इत्विध्त कीसल कार रिसर्च आन इन्टरनेणनल उकानामिक जिन्मन्स, तई दिन्ती" को कर निर्धारण-वर्ष 1983-81 में 1985-86 तक के अन्तर्गत आने यानी अथिश के लिए अधिसूचित करती है।

[सं० 5670/का० सं० 197/65/83~आ० क० (दिल-I)]

(INCOME-TAX)

S.O. 805.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Indian Council for Research on International Economic Relations, New Delhi" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1983-84 to 1985-86.

[No. 5670]F. No. 197[65]83-IT(A1)]

नर्र दिन्धी, 5 मार्च, 1984

आय-कर

नारुआर 806.—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23म) के खण्ड (iv) हारा प्रवस्त मन्त्रियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मरकार, एतद्द्वारा, उत्तन खण्ड के प्रयोजनार्थ, "इंडियन स्टेंडर्ड्स इंस्टिट्यूणन "को कर निर्धारण वर्ष 1982-83 से 1984-85 तक के अंतर्गत आने नाली अवधि के लिए अधिसुचित करती है।

[य॰ 5681/फा॰ सं॰ 197/27/83-आ॰ क॰ नि॰-1)]

New Delhi, the 5th March, 1984

INCOME-TAX

S.O. 806.-In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notities "Indian Standards Institution" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1982-83 to 1984-85.

INo. 5681[F. No. 197/27]83-IT(A1)]

आय-कर

कारधार 807.— धायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारी (23म) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदन्त गक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्त्रीय सरकार एनद्दारा, उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "कोचिन डाक लेबर बोर्ड " को कर निर्धारण वर्ष 1983-84 से 1985-86 तक के प्रतिरोध बारी धनिश्च करती है।

[सं० 5682 फा॰सं० 147/101/83- प्रा॰क (नि०-1)]

INCOME-TAX

S.O. 807.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Cochin Dock Labour Board" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1983-84 (c. 1985-86.

[No. 5682]F. No. 197[101]83-IT(AI)]

आय-कर

ना॰ ग्रा॰ 808.—शायशर ग्रिधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23म) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त एक्तियों का त्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ भायल को भाडिनेशन कमेटी भान पुल एकाउंटस :—

- (i) फेंट संरचार्ज पूल एकाउन्ट नं ।
- (ii) मी० एण्ड एफ० एडजस्टमेंट एकाउंट
- (iii) प्रष्टकट प्राप्तम एडजस्टमेट एकाउंट
- (iv) कूड आयम प्राइस इन्वेलाईजेशन एकाइटें को कर-निर्धारण वर्ष 1983-84 से 1988-89 तक के श्रंतर्गत श्राने वाली श्रविध के लिए श्रश्चिम्मविस करती है।

[सं० 5683/फा० सं० 197 / 141 / 83 श्रा० का० (नि०1)]

INCOME-TAX

S.O. 808,—In exercise of the powers conlerred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Oil Co-ordination Committee on Pool Accounts;—

- (i) Freight Surharge Pool Account No. 1.
- (ii) C&F Adjustment Account.
- (jii) Product Price Adjustment Account.
- (iv) Crude Oil Price Equalisation Account"

for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1983-84 to 1988-89.

INo. 5683[F. No. 197[141]83-IT(AI)]

आय-कर

का० आ० ८०१, — आयफर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23म) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदश्न शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एनद्द्वारा, उवन खण्ड के प्रयोजनायं, फैडरें अन आफ इण्डियन एक्सपोर्ट आर्मेनाईजिमन" को कर निर्धारण वर्ष 1983-84 में 1985-86 तक के अतर्गन आने वाली अविधि के लिए अधिसूचिन करसी है।

[#০ 5684 फা০ #০ 197/58/83-সা০ কা০ (বি০1)]

INCOME-TAX

S.O. 809.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Federation of Indian Export Organisations" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1983-84 to 1985-86.

INo. 5684[F. No. 197|58[63-IT(AI)]

आय-कर

का॰ था॰ 810. — आयक्षर प्रशितियम, 1961(1961का 43) की धारा 10 की उपधारा (23म) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्न शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एनक्झारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "वंगाल सोंगल सर्विम लीग, कलकता" को कर निर्धारण वर्ष 1981-82 से 1983-84 तक के अंतर्गन ग्राने वाली भवधि के लिए प्रधिस्चित करती है।

[सं० 3685/फाठ सं० 197/33 /80 प्रा० कठ (नि०I)]

INCOME-TAX

S.O. 810.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Bengal Social Service League, Calcutta" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1981-82 to 1983-84.

[No. 5685]F. No. 197[33[80-IT(A1)]

आय-कर

गा० श्रा० 811.—शायकर श्रश्चितियम. 1961 (1961 का 43) की श्रारा 10 की उपधारा (23म) के श्राण्ड (iv) द्वारा प्रवत्न मिनयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मरकार, एतद्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "श्रीखम भारतीय मध्ये महाविद्यालय मंडल, बम्बर्ड" को कर निर्धारण वर्ष 1981-82 से 1983--84 के संतर्गन श्राने बालो श्रवधि के लिए श्रीधमूं बित करती है।

[स॰ 5686/फा॰ स॰ 197 / 146/82- भ्रा॰क॰ (नि॰]]

INCOME-TAX

S.O. 811.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Akhul Bharatiya Gandharva Mahavidyalaya Mandal, Bombay" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1981-82 to 1983-84.

[No. 5686]F. No. 197[146]82-[T(AI)]

आय-कर

कारबार 812.— आयकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (1V) द्वारा प्रदल्त प्रक्तियों का प्रयोग करने हुए, केव्यंथ सरकार, एनद्द्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "सोसायटी धाफ वि हेम्पर्स धाफ मेरी, अस्वई" को कर निर्धारण वर्ष 1981-82 से 1984-85 तक के प्रतेगंत ग्राने वाली ध्रवधि के लिए प्रधिमूचित करती है।

[শ০ 5687/फা০ শৃত 197/242 /82 খ্যা০ জা০ (লি০I)]

INCOME-TAX

S.O. 812.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Society of the Helpers of Mary, Bombay" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1981-82 to 1984-85.

[5687/F. No 197/242/82-IT(A1)]

आय-कर

कार आर8 (३,---आय्थर श्रिष्टियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23म) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदेश्य णक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एनद्द्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, वीईल्ड लाईक एसोसिएशन श्राफ साउथ इण्डिया, बंगलीर को कर निर्धारण वर्ष 1983-81 से 1985-86 तक के भंतर्गत झाने वाली भविधि के लिए श्रिध्स्चित करती है।

[सं० 5688/फा॰ स॰ 197 / 185/82-ग्रा॰ क॰ (मि॰])] ग्रार॰ के॰ निवारी, ग्रावर सचित्र

INCOME-TAX

S.O. 813.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Wildlife Association of South India, Bangalore" for the

INo. 5609](F. No. 203][1]84-ITA.II]

purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1983-84 to 1985-86.

[No. 5688]F. No. 197[185]82-1T(A1)]

R. K. TEWARI, Under Secy.

मई विल्ली, ६ फरवरी, 1984

नाः:ा-कः

कार प्रार 81.1—इस कार्यालय की दिसाय 27-12-80 की प्रीध्यूचना ग्रंग 3779 (फार संर 203/284/80-प्रार कर (निर-II) के मिनसिने में, सर्बमाधारण की जानकारी के निग् एनद्दारा प्रिध्यूचिन किया जाता] के बिहित प्राधिकारी, प्रथांत विज्ञान और प्रीयोगिकी विभाग, नई दिलंगी ने निम्नलिखन संस्था की प्रायकर 1962 के नियम 6 के साथ पठिन प्रायकर प्रधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खड़ (ii) के प्रयोजनों के लिए ग्रन्थ प्राकृतिक मथा धनुप्रयुक्त विज्ञानों के क्षेत्र में "सम्था" प्रवर्ग के प्रधीन निम्नलिखन गर्नी पर ग्रनुमोदित किया है, प्रयांत :—

- यह कि किदवई मेमोरियल इंस्टीटयूट औफ श्रोंकॉलोजी, बंगलीर के लिए उसके क्वारा प्राप्त राणियों का पृथक लेखा रखेगा।
- 2. यह कि उक्त संस्था प्रपंत बैकातिक प्रतुमक्षात संबंधी कियाकलापी की बाधिक विवरणीं, बिहित प्राधिकारी की प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बंध में प्रति वर्ष 30 प्रपंत तक ऐसे प्रस्प में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए प्रधिकथित किया नाए घीर उसे सूचित किया नाए ।
- 3 यह िक उक्त सस्था प्रपती कुल प्राय तथा व्यय वर्षात हुए प्रपते संपरीक्षित वार्षिक लेखों को तथा प्रपती परिसंपत्तियां-छेन दारियां दर्शात हुए, तृलत-पल्ल की एक-एक प्रति, प्रसिवर्ष 30 ज्ञ तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेशों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संविधित धायकर प्रायक्त को भेजेगी।

संस्था

किदवर्ट मेमोरियल इंस्टीटयूट आफ झोकॉलोजी, बगलीर यह प्रक्षिसुचना 29-11-83 में 28-11-84 तक एक वर्ष की धर्वाध के लिए प्रभावी है।

[मंo 5609 (फाo मंo 203/11/84-आo कo निo-II)]

New Delhi, the 6th February, 1984 INCOME TAX

S.O. 814.—In continuation of this Office Notification No. 3779 (F. No. 203|284|80-ITA.II) dated 27-12-1980, it is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Science and Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" in the area of other natural and applied sciences subject to the following conditions:—

- (i) That the Kidwai Memorial Institute of Oncology, Bangalore will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said Institution will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.
- (iii) That the said Institution will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

INSTITUTION

KIDWAI MEMORIAL INSTITUTE OF ONCOLOGY, BANGALORE.

This notification is effective for a period of one year from 29-11-1983 to 28-11-1984.

[No. 5609 (F. No. 203/11/84/ITA-ID)]

नई दिल्ली, 17 फरवरी 1981

कार प्रारं 815.—सर्वेसाधारण की जानकारी के लिए एनद्द्वारा यह प्रक्षिस्चित किया जाता है कि सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नित्वित वैज्ञानिक प्रनुसद्धान कार्येक्रम को, प्रायकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर प्रधिन्यम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (2क) के प्रयोजनार्थ नीचे विनिद्धिष्ट प्रविध के लिए भन्मोदित किया हैं:—

अनुसंधान परियोजना का शीर्षक : इलेक्ट्रो क्षिपोजिशन श्राफ हाई पर्फार्मस लो कास्ट मैटीरियल्स फार सेपरेबल इले-नटानिक केनेस्टर्स।

प्रायोजको का नाम

- (1) मेमर्स गर्ग एसोसिएट्स (प्रा०) लिमि-टेंड, गांजियाबाद ।
- (2) मेमर्स मुकृति विद्युत उद्योग प्रा० लिमिटेक, गाजियाबाद ।

कार्यान्विध करने वाली संस्थान का

नाम 🕐 : भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलीर।

प्रारंभ करने की प्रस्तावित तारीखः । 1-3-1983 पूरा करने की प्रस्तावित तारीखः । मार्च, 1985

श्रनमानित व्यय

: (1) 1,50,000 क० (केयल एक लाख पंचास हजार रुपये)।

(2) 50,000 ४० (कॅबल पचाम हजार

म्पये) ।

2. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलीर, ब्रायकर मधिनियम, 1922 की धारा 10(2) (xiii) के श्रंतर्गत मनुमोदिन है तथा प्रायोजन घाधार पर परियोजना लेने की पात्र है।

[सं० 5643 (फा॰ मं॰ 203/2 /83-ग्रा॰ का॰ नि॰-H)]

New Delhi, the 17th February, 1984 INCOME-TAX

S.O. 815,-- It is hereby notified for general information that the following scientific research programme has been approved for the period specified below for the purposes of sub-section (2A) of the section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 by the Science are Department of Science & Technology, New Delhi :--

Title of research project

Electro Deposition of High Performance low cost materials for separable Electronic connectors.

Name of Sponsors

- (i) M/s. Garg Associates (P) Limited, Ghaziabad.
- (ii) M/s. Sukriti Vidyut Udyog Pvt., Limited, Ghaziabad.

Name of the implementing
Institute

Proposed date of starting

Proposed date of completion

If stimuted outlay

Proposed date of completion

If stimuted outlay

If Rs. 1,50,000/- (One lakh fifty thousand only)

If Rs. 50,000/- (Fifty thousand only)

2. Indian Institute of Science, Bangalore is approved under section 10(2) (xiii) of the Income-tax Act, 1922 and is eligible to take project on sponsorship basis.

[No. 5643(F. No. 203/205/83-ITA, 11)]

नई विल्ली, 23 फरवरीः 1981

प्राय-कर

का० आ० ४१६ — सर्वेसाधारण की जानकारी हेतु एतद्वारा अधिमूचित किया जाता है कि आयकर अधिनियम. 1922 की आरा 10 (2) (Xiii) के अन्तर्गत भारतीय मौसम विज्ञात विभाग, नई दिल्ली को भूतपूर्व विज्ञा विभाग की दिलांक 23-11-1918 की अधिमूजना संख्या 34 द्वारा सनत आधार पर दिया गया अनुभोदन; 14-9-1983 से वापिस लिया जाना है।

[सं० 5661 (फा॰ सं० 203/15/83-प्रा॰क॰ नि॰ II)] मदन गोपाल चंद गोयल, ग्रवर सचिव

New Delhi, the 23 February, 1984

INCOME TAX

S.O. 816.—It is hereby notified for general information that the approval granted on perpetual basis u/s. 10(2)(XIII) of the Income-tax Act, 1922, to Indian Meteorological Department, New Delhi vide late Finance Department's notification No. 34 dated 23-11-1946 is hereby withdrawn with effect from 14-9-1983.

[No. 5661 (F. No. 203/15/83-ITA, II)]

M. G. C. GOYAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1984

म्रादेण

म्टाम्प

का० श्रा० 817.—भारतीय स्टामा प्रिधिनियम, 1899 (1899 क 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदन्त शिक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय मरकार एतद्द्वारा उम शुक्क को माफ करती है जो महाराष्ट्र गृह एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण बम्बाई द्वारा केवल 1 करोड़, दस लाख रुपये कृत्य के ऋण प्रवों के रूप में जारी किए जाने बाले बंधपत्नों पर उसस प्रधिनियम के श्रंसर्गन प्रभाय हैं।

[सं० 15/84-स्टाम्प-फा० सं० 33/9/84-वि०क०]

New Delhi, the 22nd February, 1984

ORDER

STAMPS

S.O. 817.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the nature of debentures to the

value of rupees One crore ten lakhs only to be issued by the Maharashtra Housing and Area Development Authority Bombay are chargeable under the said Act.

[No. 15/84-Stamps, F. No. 33/9/84-ST]

नई दिल्ली, 29 करवरी, 1984

स्टास्प

का था । 818.— भारतीय स्टास्प श्रिधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदेश्त गिक्सियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, बित मंत्रालाय (राजस्व विभाग) की 19 नवस्वर, 1983 की अधिसूचना संख्या 34/83-स्टास्प फा० मं० 33/2/83-बि० क० (का० भ्रा० संख्या 4352) की श्रिधलंघन करने हुए केन्द्रीय सरकार स्टास्प शुल्क की गणना के प्रयोजनार्थ नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में, उसी के स्तंभ (2) में नवनुक्पी प्रथिदि में यिनिर्दिष्ट विदेशी मुद्रा की भारतीय गुड़ा में मम्परिवर्षित के लिए एतदवारा विनियमय की दर निर्धारित करती है।

मारणी

	· · · · · · ·
नम विदेशी मुद्रा	1005० क
म् ०	समतुरूप
	विदेशी मुद्रा
	की विनिमय
	की दर
1 2	3
- — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	179,5
2. श्रास्ट्रेलियत हासर	10.395
 बैलिजयन फ्रेंक 	520.5
 कनाडियन द्रालर 	11.695
5. डेनिश कानर	92.40
 डय्रणे मार्कः 	25.52
7. यच गिल्डर	228.70
 फ़ींच फ़ींक क 	78.05
 होग कॉग डालर 	73.10
10. इटालियन लीग	15561
11. जापानी येन	2176
12 मलेशियन डालर	21.96
13. नार्येजियन क्रोनर	72.25
14. पीड स्टलिंग	6.5090
1.5, स्वीडिंग कोनर	75.5
16. न्विस फ्रींक	20.45
17. धमरोकी ज्ञालर	9.450
18 सिंगपुर छालर	19.890

[सं० 17/84-स्टाम्प-फा०सं० 33/2/83-वि०क०]

भगवान दाम, भ्रमर सनिष

New Delhi, the 29th February, 1984

STAMPS

S.O. 818.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 20 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 34/83-Stamps F. No. 33/2/83-ST (No. S.O. 4352), 'dated the 19th November, 1983 the Central Government hereby prescribes in column (3) of the Table below, the rate of exchange for the conversion of the foreign currency specified in the corresponding entry in column (2) thereof into the currency of India for the purpose of calculating stamps duty.

TABLE

S. No.	Foreign Currency -	Rate of ex- change of foreign currency equi- valent to Rs. 100
(1)	(2)	(3)
1. Austrian	Schillings	179.5
2. Australian	Dollars	10.395
3. Belgian	Francs	520.5
4. Canadian	Dollars	11.695
5. Darish	Croners	92.40
6. Deutsche	Mai ks	25.52
7. Dutch	Guilders	28,70
8. French	Francs	78.05
9. Hong Kong	Dollars	73.10
10. Italian	Lire	15561
11. Japanese	Yen	2176
12. Malaysian	Dollar s	21.96
13. Norwegian	Kroners	72.25
14. Pound	Sterling	6.5090
15. Swedish	Kroners	75.5
16. Swiss	Francs	20.45
17. U.S.A.	Dollars	9.450
18. Singapore	Dollars	19.990

[No.17/84-Stamps.F. No.33/2/83-ST] BHAGWAN DAS, Under Secy.

गई दिन्ति, 24 फरवरी, 1984

ग्रायकर

का० आ० 819 :— आयकर प्रिष्ठित्यम, 1961 (1961 का 43) की धारा 194क की उपधारा (3) के खण्ड (iii) के उपखण्ड (च) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, एतवुद्वारा, आर्मी ग्रुप इंगोरेन्स फण्ड, नई दिल्ली के रूप मे ज्ञात सोसाइटी को उक्त, उप-खण्ड के प्रयोजनार्थ प्रिष्ठ-सुचिन करती है।

[फा॰ सं॰ 275/1/83-मायकर(ब)] बी॰ नागाराजन, उप-सचिव New Delhi, the 24th February, 1984

INCOME-TAX

S.O. 819.—In pursuance of sub-clause (f) of clause (ill) of sub-section (3) of section 194A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the society known as Army Group Insurance Fund, New Delhi for the purposes of the said sub-clause.

[F. No. 275/1/83-IT(B)] B. NAGARAJAN, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 1984

क्रायकर

का ब्या 820 :-- आयकर मिंधितयम, 1961 (1961 का 43) की घारा 2 के खण्ड (44) के उपखंड (3) के मनुमरण में भौर भारत सरकार के राजस्व विभाग की विनोक 30-5-80 की मिंधिसूचना संख्या 3448 (फा० सं० 398/1/80-मा० क०सं०क०) का मिंधिलंघन करने हुए, केन्द्रीय सरकार एनद्दारा श्री रणछोड़भाई एम० परमार को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपन्नित प्रधिकारी हैं, उनत मिंधिनयम के प्रन्तर्गत कर बसूली मिंधकारी की मान्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती हैं।

2. यह प्रधिसूचना, श्री रणछोड़भाई एम॰ परमार द्वारा कर वसूली प्रधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख से लागू होती।

[सं० 5664/फा० सं० 398/6/84-मा०क०(ब०)] की०ई० मलैकर्जण्डर, स्रवर सचिव

New Delhi, the 27th February, 1984 INCOME-TAX

S.O. 820.—In pursuance of sub-clause (iii) of Clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 3448 (F. No. 308/1/80-ITCC) dated 30-5-1980, the Central Government hereby authorises Shri Ranchhodbhai M. Parmar being a Gazetted Officer of the Central Government to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This notification shall come into force with effect from the date of Shri Ranchhodbhai M. Parmar takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 5664/F. No. 398/6/84-IT(B)]
B. E. ALEXANDER, Under Secy.

(ब्यय विभाग)

नई दिल्ली, 29 फरवरी, 1984

का०भा० 821.—केन्द्रीय सरकार, भविष्य निधि मधिनियम, 1925 (1925 का 19) की धारा 8 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्त्यों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश वैती है कि उक्त मधिनियम के उपबंध, राष्ट्रीय जन-विज्ञान संस्थान के कर्मचारियों के फायदों के लिए स्थापित भविष्य निधि को लागू होगे।

[सं॰ एफ॰, 4 (2)-ई V/83]

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 29th February, 1984

S.O. 821.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (2) of Section 8 of the Provident Fund Act. 1925 (19 of 1925), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act shall apply to the Provident

Fund established for the benefit of the employees of the National Institute of Hydrology.

[No. F. 4(2)-EV/83]

का० ग्रा० 822 — केन्द्रीय सरकार, भविष्य निश्चि श्रीधनियम, 1925 (1925 का 19) की धारा 8 की उपधारा (3) द्वारा प्रदरस गिक्तयों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखिस लोक संस्था का नाम उक्त श्रीधनियम की प्रमुसुषी में जोड़ती हैं, ग्रर्थान् :—

"राष्ट्रीय जनविज्ञान संस्थान।"।

, [सं० एफ० 4(2)-ईवी/83] के० रतन, उपसन्विष

S.O. 822.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (3) of Section 8 of the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925), the Central Government hereby adds to the Schedule to the said Act, the name of the following public institution, namely:—

National Institute of Hydrology.

[No. F. 4(2)-EV/83]

K. RATAN, Dy. Secv.

(प्राधिक कार्य विभाग)

(बैकिंग प्रभाग)

नई दिल्लो, 28 फरवरी, 1981

का॰ प्राष्टि 823—भारतीय ग्रीधोगिक विकास बैंक ग्रीधिनियम 1964 (1964 का 18) की धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उप खंड (2) के धनुमरण में केन्द्रीय मरकार एत्नद्वारा श्री एस॰ एस॰ नाडकर्णी, प्रध्यक्ष ग्रीर प्रबंध निदेशक, भारतीय ग्रीधोगिक अर्थ ग्रीर निवेश निगम लि॰, बंबर्ड को श्री एस॰ एस॰ मेहना के स्थान पर भारतीय ग्रीधोगिक विकास बैंक का निदेशक नामित करती है।

[संख्या एफ० 9/2/84-बी० भ्रो०-I (1)]

(Department of Economic Affairs)
(Banking Division)

New Delhi, the 28th February, 1984

S.O. 823.—In pursuance of sub-clause (ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 6 of the Industrial Development Bank of India Act, 1964 (18 of 1964), the Central Government hereby nominates Shrl S. S. Nadkarni, Chairman and Managing Director, Industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd., Bombay as the Director of the Industrial Development Bank of India vice Shri S. S. Mehta.

INo. F. 9/2/84-BO. I(1)1

का० आ० 824---भारतीय श्रौद्योगिक विकास बैंक श्रीधिनियम, 1964 (1964 का 18) की धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के उप खंड (2) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा श्री एम० जे० फेरवानी, अध्यक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, यस्वर्ष को श्री जी० एम० पटेल के स्थान पर भारतीय श्रौद्योगिक विकास बैंक का निदेशक नामित करती है।

[संख्या एफ॰ 9/2/84-बी॰ भी॰-I (2)]

च वा० मीरचन्वानी, उप सचित्र

S.O. 824.—In pursuance of sub-clause (ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 6 of the Industrial Development Bank of India Act, 1964 (18 of 1964), the Central Government hereby nominates Shri M. J. Pherwani. Chairman, Unit Trust of India, Bombay as the Director of the Industrial Development Bank of India vice Shri G. S. Patel.

[Nc. F. 9/2/84-BO. I(2)]

C. W. MIRCHANDANI, Dy. Secy.

नई दिस्सी, 3 शार्च, 1984

का० आ० 825.—राष्ट्रीय कृषि और प्रामीण विकास बैंक प्रधिन्यम 1981 (1981 का 61) को धारा 19 के खंड (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एसद्बारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा 14 मार्च से 16 मार्च, 1984 की श्रवधि के दौरान शनप्रतिशत मूल्य पर, 12 वर्ष की परिपक्षता प्रवधि के साथ जारी किये जाने वाले 35 करोड़ रुपये (पैतीस करोड़ रुपये केवल) के बांडों पर देय ब्याज की दर 8.25 (सथा घाठ प्रतिशत) तय करतीं है। बैंक को उक्त श्रिधमूचिन राशि से 10 प्रतिशत श्रिधक तक श्रिधदाम की राशि श्रपने पास रख लेने का श्रिधकार होगा।

[संख्या 10(12)/84-ए०सी०] ग्रमर सिंह, श्रवर मन्त्रिय

New Delhi, the 3rd March, 1984

S.O. 825.—In pursuance of clause (a) of section 19 of the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 (61 of 1981), the Central Government hereby fixes 8.25 per cent (eight and one fourth per cent) per annum as the rate of interest payable on the bonds of Rs. 35 crores (Rupees thirty five crores only) to be issued at Rs. 100.00 per cent during the period from 14th to 16th March, 1984 with right to retain subscriptions received upto 10 per cent in excess of notified amount with a maturity period of 12 years by the National Bank for Agriculture and Rural Development.

[No. 10(12)|84-AC]

AMAR SINGH, Under Secy.

(बीमा प्रभाग)

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1984

का० घा० 826.—जीवन बीमा निगम प्रिष्ठिनियम, 1956 (1956 का 31) की घारा 4 के द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार एनव्हारा श्री एस० जी० सुत्रमण्यम को, उनके द्वारा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के दिन से लेकर 12 जून, 1985 तक, भारतीय जीवन बीमा निगम के बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है।

[एक० मं ० 14(1) इंग्यो-V/84] जी ० एम० शतम्गम, स्रवर मचिव

(Insurance Division)
New Delhi, the 6th March, 1984

S.O. 826.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Life Insurance Corporation Act, 1956, (31 of 1956), the Central Government hereby appoints Shri S. G. Subrahmanyan as Member of the Board of Life Insurance Corporation of India from the day he takes over as Managing Director of the Corporation till the 12th June, 1985.

[File No. 14(1) Ins. V|84]

G. M. SHUNMUGAM, Under Secv.

विवेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 1984

कां अां अर्थ स्थान स्था

[मं॰ टी- 4330/2/84)] भपेन्त्र सिंह निष्ठर, ग्रवर संचिष

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 29th February, 1984

S.O. 827.—In pursuance of the clause (a) of Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby authorise Shri R. P. Bholla, Assistant in the Embassy of India, Doha to perform the duties of Consular Agent with immediate effect.

[No. T-4330/2/84] B. S. NIDDAR, Under Secy.

वाणिण्य मंत्रालय

(बस्त्र विभाग)

मई दिन्ली, 6 मार्च, 1984

का० आ० 828.— केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम 1948 (1948 का 61) की धारों 4 की उपधारा (3) हारा प्रवक्त गक्तियों का प्रयोग क्रते हुए केन्द्रीय संरकार वाणिज्य मंत्रात्य (बस्त्र विभाग) भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का० आ० 2234 दिनांक 24 अप्रैल 1982, अधिसूचना का० आ० संख्या 77 दिनांक 1-11-83 द्वारा यथा संशोधित में एनव्हारा निम्नलिखिन संशोधन करती हैं।

उन्त अधिसूचना में मद 30 और उससे सम्बन्धित प्रविष्ट के स्थान पर निम्निलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातु :--

"30 श्री ब्रह्म दल अधिनियम की धारा 4(3) (5) संयुक्त विकास आयुक्त (द्वयकरधा) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा वस्त्र विभाग मनोनीत । वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार

[फा॰ सं॰ 25012/11/82-सिल्क-जिल्बे-I] एस॰ के॰ सिश्र, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Textiles)

New Delhi, the 6th March, 1984

S.O. 828.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Central Silk Board Act, 1948 (6 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendments, in the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce (Department of Textiles) No. S.O. 2234, dated the 24th April, 1982, as amended by Notification S.C. No. 77 dated 1-1-83, namely:—

In the said notification, for item 30 and the entry relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

IF. No. 25012/11/82-SIIk Vol. IIS. K. MISRA, Addl. Secy.

नई विल्ली, 17 मार्च, 1984

कां था १० १० - केन्द्रीय सरकार, निर्मात (क्वालिटी नियंत्रण भौर निरीक्षण) मधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रवन्त शिक्त्यों का प्रयोग करने हुए, निर्मात निरीक्षण प्रभिकरण मृत्यु-व-सेवा निवृत्ति उपदान नियम, 1981 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :---

- 1. (1) इन नियमों का नाम निर्यात निरीक्षण भ्रामिकरण, मृत्यु-ब-सेवा निवृत्ति उपदान (संशोधन) नियम, 1984 है।
 - (2) ये राजपल में प्रकाशन की तारीख को प्रवत्त होंगे।
- 2. निर्यात निरीक्षण भ्रनिकरण मृत्यु-ब-सेवा निवृत्ति उपदान नियम, 1981 में, नियम 2 में :--
 - (1) उप-नियम (ज) के खण्ड (1) में, "पत्नी" शब्द के पश्चास् "या पिल्नयां जिनमें नलाकश्रुदा पत्नी या पिल्नयां भी सम्मिलित है " शब्द जोड़े जाऐंगे।
 - (2) उप-नियम (ज) के खण्ड (2) में "पति" शब्द के पश्चात् "तलाक शृदा पति भी सम्मिलित है" शब्द जोड़े जाऐंगे।
 - (3) उप-नियम (ज) के खण्ड (6) तथा (7) कोष्टक में होंगे तथा इन के सामने "उन व्यक्तियों के मामले में जिनका वैयक्तिक नियम दत्तक को अनुमति देता है, दत्तक माता-पिता सम्मिलित है" शब्द जोड़े जाऐगे।
 - (4) उप-नियम के खण्ड (ठ) में "ग्रमाधारण छुट्टी" गरूर के पण्डात् काष्ठक में "(चिकित्सा प्रमाण-पत्न पर स्वीकृत प्रमाधारण छुट्टी के प्रतिरिक्त)" शब्द जोड़े जाऐंगे, तथा उक्क उप-निश्रम में निम्मलिखित उपवंध जोंग्रा जाएगा;

"बगर्ते कि चिकित्सा प्रमाण-पन्न पर स्वीकृत असाधारण छुट्टी के अतिरिक्त असाधारण छुट्टी के मामले में, नियुक्ति प्राधिकारी, ऐसी छुट्टी देने के समय ऐसी छुट्टी की अवधि को अर्ह्यक सेवा में शामिल कर सकता है यदि ऐसी छुट्टी कर्मचा-रियों को प्रवत्त की गई है:---

- (i) नागरिको में होहुल्लड के कारण, उसकी ड्यूटी पर उपस्थित या पुनः उपस्थित होने की भ्रममर्थता के कारण या ,
- (ii) उच्च वैज्ञानिक तथा तकनीकी पाठ्यक्रम चालन के लिए। $^{\prime\prime}$
- 3. उक्त नियम के नियम 6 के उप-नियम (क) में, 30,000 -स्पयों के स्थान पर 36,000 - स्पयों रखं आएंगे।

[मं० 3(12) 76-ई०म्राई०एण्ड ई०पी०]

पाद टिप्पण : का॰ आ॰ 1608 तारीख 30-5-81 का॰ आ॰ 214 तारीख 12-6-82

New Delhi, the 17th March, 1984

S.O. 829.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export Inspection Agency Death-cum-Retirement Gratuity Rules, 1981, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the Export Inspection Agency Death-cum-Retirement Gratuity (Amendment) Rules, 1984.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- 2. In the Export Inspection Agency Death-Cum-Retirement Gratuity Rules, 1981, in Rule 2:-
 - (1) in clause (i) of sub-rule (h), after the word "wife" the words "or wives including judicially separated wife or wives" shall be added.
 - (2) in clause (ii) of sub-rule (h) after the word "husband" the words "including judicially separated husband" shall be added.
 - (3) Clause (vi) & (vii) of sub-rule (h) shall be bracketed and the words "including adoptive parents in the case of individuals whose personal law permits adoption" shall be added against these clauses.
 - (4) in clause (k) of the said rule, after the words "extraordinary leave", within brackets the words "(other
 than extra-ordinary leave granted on medical gertificate)" shall be added.

and the following proviso shall be added to the said sub-rule:

"Provided that in the case of extra-ordinary leave other than extra-ordinary leave granted on medical certificate the appointing authority may, at the time of granting such leave, allow the period of that leave to count as qualifying services if such leave is granted to the employees:—

- (i) due to his/her inability to join or rejoin on account of civil commotion, or
- (ii) for prosecuting higher scientific and technical studies."
- 3. In sub-rule (a) of Rule 6 of the said rule, the figure Rs. 36,000 may be sub-tituted for Rs. 30,000.

[No. 3(12)/76-EI&EP]

FOOT NOTE.-S.O. 1608 dt. 30-5-81.

S.O. 2141 dt. 12-6-82.

नई दिल्ली, 17 नार्च, 1984

का॰ ग्रा॰ 830.—केन्द्रीय संरकार, निर्मात (स्वालिटी नियंत्रण भौर निरीक्षण) मधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्मात निरीक्षण परिषद् मृत्यु सह सेवा निवृत्ति उपदान नियम, 1981 में भौर संशोधन करने के सिए निम्नलिखित नियम बनाती है, ग्रर्थात् :—

- 1.(1) इन नियमों का संकिप्त नाम निर्यात निरीक्षण परिषद् मृत्यु सह सेवा निवृत्ति उपवान (संशोधन) नियम, 1984 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. नियात निरीक्षण परिषद् मृत्यु सह सेवा निवत्ति उपवान नियम, 1981 के नियम 2 में :--
 - (1) उपनियम (ज) के खंड (1) में, "पत्नी" शब्द के पश्चात् "या पत्नियां जिसके मंतर्गत न्यायिकतः पृथक पत्नी या परिनयां भी हैं" शब्द जोड़े जाऐंगे।
 - (2) उपनिथम (ज) के खंड (2) में "पित" शब्द के पश्चात् "जिसके मंतर्गत न्यांयिकतः पृथक पित भी है" शब्द जोड़े जाऐंगे।
 - (3) उपनियम (ज) के खंड (6) तथा (7) कोष्ठक में होंगे तथा इनके सामने "उन व्यक्तियों की दशा में जिनकी स्वीय विधि दलक प्रनुकात करती है, दलक माता-पिता भी हैं," शब्द जोड़े जाएंगे।
 - (4) उपनियम के खंड (ठ) में "ग्रसाधारण छुट्टी" गब्द के पश्चात् कोष्ठक में "(चिकिरसा प्रमाण-पत्न पर स्वीकृत ग्रसाधारण

धुट्टी के श्रतिरिक्त)" शब्द जोड़े आऐंगे तथा उक्त उपनिशम में निम्मलिखित उपक्षंत्र जोड़ा जाएगा :

"परन्तु चिकित्सा प्रमाण-पक्ष पर स्त्रीकृत मसाधारण खुट्टी के मतिरिक्त मसाधारण खुट्टी की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी खुट्टी देने के समय ऐसी खुट्टी की भवधि को महंक सेवा में सम्मिलित कर सकता है यदि ऐसी खुट्टी कर्मकारियों को प्रदत्त की गयी है :---

- (i) नागरिकों में होहुल्लब के कारण, उसकी बयूटी पर उपस्थित या पून: उपस्थित होने को ध्रसमर्थता के कारण या
- (ii) उच्च वैज्ञानिक तथा तकनीकी पाठभक्रम चालन के लिए।"
- 3. उक्त नियम के नियम 6 के उप-नियम (क) में, 30,000/-रुपयों के स्थान पर 36,000 - रुपए रखे जाऐंगे।

[सं० 3(12) 76-ई०माई०एण्ड० ई०पी०]

पाद टिप्पण : का॰ भा॰ 1607 तारीख 30-5-81 का॰ भा॰ 2140 तारीख 12-6-82

New Delhi, the 17th March, 1984

- S.O. 830.—In exercise of powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export Inspection Council Death-cum-Retirement Gratuity Rules, 1981, namely:—
 - (1) These rules may be called the Export Inspection Council Death-cum-Retirement Gratuity (Amendment) Rules, 1984.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Export Inspection Council Death-cum-Retirement Gratuity Rules, 1981, in Rule 2:—
 - in clause (i) sub-rule (h), after the word "wife" the words "or wives including judicially separated wife or wives" shall added.
 - (2) In clause (ii) of sub-rule (h) after the word "husband" the words "including judicially separated husband" shall be added.
 - (3) Clause (vi) & (vii) of sub-rule (h) shall be bracketed and the words "including adoptive parents in the case of individuals whose personal law permits adoption" shall be added against these clauses.
 - (4) in clause (k) of the said rule, after the words "extra-ordinary leave", within brackets the words "(other than extra-ordinary leave granted on medical certificate)" shall be added, and the following proviso shall be added to the said sub-rule:

"Provided that in the case of extra-ordinary leave other than extra-ordinary leave granted on medical certificate the appointing authority may, at the time of granting such leave, allow the period of that leave to count as qualifying service if such leave is granted to the employees:—

- (i) due to his/her inability to joint or rejoin duty on account of Civil commotion; or
- (ii) for prosecuting higher scientific and technical studies."
- 3. in sub-rule (a) of Rule 6 of the said rule, the figure Rs. 36,000 may be substituted for Rs. 30,000.

[No. 3(12) /76-EI&EP]

FOOT NOTE.—S.O. 1607 dt. 30-5-81.

S.O. 2140 dt. 12-6-82,

• मुद्धिपत

का० ग्रा० 8:1.—निर्मात निरीक्षण ग्राभिकरण में मृत्यु-ब-सेषा निवृत्ति उपवान नियम, 1981 में भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की प्रविस्त्रक्ता का० प्रा० सं० 1607 तारीख 30 मई, 1981 के साथ भारत के राजपन्न भाग-II, खंड-3, उपखंड-(i) तारीख 30 मई, 1981 में प्रकाशित द्वर :

- 1. नियम 2 के उप-नियम (अ) में :
 - (क) खंड (iii) में "पूल" के स्थान पर 'पूलों" पढा जाएगा ।
- 2. नियम 12 में "उपाबंध 1 से iii।" के स्थान पर "उपाबंध i से ii" पढ़ा जाएगा।

[सं० 3(12)/76-ई०भाई० एण्ड ई०पी०]

CORRIGENDUM

- S.O. 831.—In the Export Inspection Agency Death-cum-Retirement Gratuity Rules, 1981 published with the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce, S.O. No. 1608 dated the 30th May, 1981 in the Gazette of India Part II, Section 3 Sub-Section (i) dated the 30th May 1981:
 - (1) In sub-rule (h) of rule 2:
 - (a) in clause (iii), for 'son' read "sons".
 - (b) in clause (ix) for 'or' read 'of'.
- · (2) In Rule 12 for "Annexure I to III" read "Annexure I to III".

[No. 3(12)/76-EI&EP]

मुद्धिपक्ष

का० आ० 832.—निर्मात निरीक्षण परिषय मृत्यु सह सेवा निवृत्ति उपदान नियम, 1981 में जो कि भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की धिस्चित्ता का० ग्रा० सं० 1607 तारीख 30 मई, 1981 के साथ भारत के राजपत्न, भाग-II, खंड-3, उपखंड-(i) तारीख 30 मई, 1981 में प्रकाशित हुए :

- 1 नियम 2 ने उपनियम (ख) में:
- (क) सीड (iii) में "पुल" के स्थान पर "पूर्लों" पक्षा जाएगा।
- 2. नियम 12 में "उपबंध i से iii" के स्थान पर "उपबन्ध i से ii" पढ़ा जाएगा ι

[सं॰ 3(12)/76-ई॰ प्राई॰ एण्ड ई॰पी॰] सी॰ की॰ क्करेती, संयुक्त निदंशक

CORRIGENDUM

- S.O. 832.—In the Export Inspection Council Death-cum-Retirement Gratuity Rules, 1981 published with the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce S.O. 1607 dated the 30th May, 1981 in the Gazette of India Part II Section 3 Sub-section (i) dated the 30th May, 1981:
 - (1) In sub-rule (h) of rule 2:
 - (a) in clause (iii), for 'son' read "sons".
 - (b) in clause (ix) for 'or' read 'of'.
- (2) In Rule 12 for "Annexure I to III" rend "Annexure I to II".

[No. 3(12) /76-EI&EPI

C. B. KUKRETI, Jt. Director

मुख्य निर्यक्रक आयात एवं निर्यात का कार्यालय आवेश

नई विल्ली, 26 दिसम्बर, 1983

का॰ भा॰ 833—सर्वे श्री कार्डम रीच वर्कशांप लिमिटेड, 43/40 गार्डन रीच, कलकरता-24 को रक्षा मंत्रालय के पक्ष संख्या एफ०सी०/ब्राई० ए म०पी०/पी० एच०-111/6/18686 विनांक 9-1-1974 में संजन्न सूची के धनुसार क्यू की मैम मेरिन डीजल इंजन के टर्बो चार्जर्स के लिए अपेकित संघटकों के घायात के लिए 2,50,000/- द० का घायात लाइसेंस संख्या 1/ए/1397912 विनांक 22-2-1974 प्रवान किया गया था।

- 2. सर्वाश्री गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड ने उपर्युक्त लाइसेंस की अनुलिपि (सीमा शुरूक नियंत्रण प्रति) के लिए इस झाझार पर झाबेदन किया है कि मूल सीमा शुरूक प्रति बिना किसी सीमा शुरूक प्रधिकारी के पास पंजीकृत कराए और बिल्कुल भी उपयोग में लाए बिना ही खो गई है। सर्वाश्री गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड, कलकरता इस बात से सहमत है और बचन देता है कि मूल धायात लाइसेंस के साद में मिल जाने पर उसे इस कार्यालय के दिकाई के लिए वापिस कर दिया आएगा।
- 3. प्रपने तर्क के समर्थन में सर्वश्री गार्डन रीच वर्कणाप लिमिटेड, कलकरता ने 1983-84 की प्रायात-निर्यात कियाविधि हैंडवुक के ध्रष्ट्रया 15 के पैरा 353 में वी शर्तों के प्रनुसार एक शपथ पन्न वाखिल किया है। प्रघोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि मूल प्रायात लाइसैस संख्या 1/ए/1397912 विनांक 22-2-1974 को गया है और प्रावेदन को प्रनुलिपि लाइसेंस (सीमा शुल्क नियंत्रण प्रति) जारी करने का निदेश देता है। लाइसेंस की मूल सीमा शुल्क प्रति एतवृहारा रव्द की गई मानी जाएगी।
- 4. प्रायात लाइसेंस की प्रनुलिपि (सीमा शुल्क नियंत्रण प्रति) अलग से जारी की जा रही है।

[(मि॰ सं॰ एन॰ **की॰/4**74/73-74/पी॰ एस॰ एस॰/बी)]

एस० एल० भागव, उप मुख्य नियंत्रक भायात एवं निर्यात

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

New Delhi, the 26th December, 1983

- S.O. 833.—M/s, Garden Reach Workshop Ltd., 43/40 Garden Reach, Calcutta-24 was granted an Import Licence No. 1/A/1397912 dated 22-2-1974 for Rs. 2,50,000 for import of Components required for the manufacture of turbo chargers for QV mam marine Diesel Engine as per list attached against Ministry of Defence Letter No. FC/IMP/PH-111/6/18686 dated 9-1-1974.
- 2. M|s. Garden Reach Workshop Ltd., have now requested for issue of Duplicate (Custom Control Copy) of the above licence on the ground that the original Custom Copy has been lost without being registered with the Custom Authority and Utilised infull. M|s. Garden Reach Workshop Ltd., Calcutta agrees and undertakes to return the Original Import Licence, if traced later on to this office, for record.
- 3. In support of their contenion, M/s. Garden Reach Workshop Ltd., Calcutta have filled an affidavit as required in terms of para 353 of Chapter XV of Hand Book of import-export procedures for 1983-84. The undersigned is satisfied that the Original import licence No. 1/A/1397912 dated 22-2-1974 has been lost and directs that duplicate licence (Custom Control Copy) may be issued to the applicant. The original Custom Copy of the licence is hereby treated as cancelled.
- 4. The duplicate (Custom Control Copy) of the importionnee is being issued separately.

IF. No. ND|474|73-74|PLS|B1

M. L. BHARGAVA, Dy. Chief Controller of Imports and Exports.

प्रावेश

नई विल्ली, 2 मार्च, 1984

का० भा० 834.—-मर्बश्री हितेक इंडस्ट्रीज (बिहार) प्राक्षेट लिमि-टेड, रांची को पुरामी मशीनरी के निर्यात के लिए निर्यात लाइसेंस सं० पी०/सी०जी०/2094574 दिनांक 26-11-83 प्रवान किया था।

- 2. सावेदक ने श्रव आमात लाइसेंस सं० पी०/सी० जी०/2094574 दिनांक 26-11-83 की सीमाशुल्क अयोजन प्रति भीर मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि प्रति के लिए इस आधार पर शावेदन किया है कि भूल प्रतियां बिना किसी सीमा-गुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराए भीर बिल्कुल भी उपयोग में लाए बिना ही जोरी हो गई है। प्रावेदक उपर्युक्त आयात लाइसेंस की मूल प्रतियों के बाद में मिल जाने पर उन्हें इस कार्यालय के रिकार्ड के लिए आपस करने को सहमत है भीर बचन देते है।
- 3. प्रवित तर्क के समर्थन में ग्रावेवक ने 1983-84 की प्रायात-निर्मात कियाविधि हैंड-मुक के पैरा-353 में मांगे गए के भनुसार एक णपथ-पत्न दाखिल किया है। प्रधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि भ्रायात लाइसेंस संव पी०/सी० जी०/2094574 दिनांक 26-11-83 की मूल सीमाणुल्क प्रयोजन प्रति और मुद्रा विनिसय नियंक्षण प्रति खो गई/कोरी हो गई है और निवेण देते हैं कि भ्रावेदक को उपर्युक्त लाइसेंस की सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति और मुद्रा विनिसय नियंक्रण प्रति की भ्रनुलिपि प्रति जारी की जाए। उपर्युक्त भ्रायात लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति भीर मुद्रा विनिसय नियंक्षण प्रति एतव्दारा रह की जाती है।
- 4. प्रायात लाइसेंस सं० पी०/भी० जी०/2094574 विनांक 26-11-83 की सीमा-शुल्क प्रयोजन/मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की घनुलिपि प्रितियां अलग से जारी को जा रही हैं।

[मिसिल सं० 637/1/83-84 सी०जी०-4/1096] पॉल बेक, उप-मुख्य नियंत्रक, श्रायात-निर्यात कृते मुख्य नियंत्रक, श्रायात-निर्यात

ORDER

New Delhi, the 2nd March, 1984

- S.O. 834.—M/s. Hitek Industries (Bihar) Pvt. Ltd., Ranchi have been granted import licence No. P|CG|2094574 dated 26-11-1983 for import of secondhand machinery.
- 2. The applicant has now requested for issue of duplicate copy of Customs Purpose and Exchange Control copies of licence No. P[CG]2094574 dated 26-11-1983 on the ground that the original copies have been stolen away without having been registered with any customs authorities and not utilized at all. The applicant agrees and undertakes to return the original copies of the above licence if traced later to this office for record.
- 3. In support of his contention the applicant has filed an affidavit as required in para 353 of the Hand Book of Import-Export Procedures 1983-84. The undersigned is satisfied that the original custom purpose copy and exchange control copy of import licence No. P|CG|2094574 dated 26-11-1983 have been lost/stolen and directs that duplicate copy of the customs purpose and exchange control copy of the above licence should be issued to the applicant. The original copies of the custom purposes and exchange control copy of the above import licence are hereby cancelled.
- 4. Duplicate copies of the customs purposes exchange control copies of the import licence No. P|CG|2094574 dated 26-11-1983 are being issued separately.

[File No. 637/1/83-84/CG IV/1096] PAUL BECK, Dy. Chief Controller of Imports & Exports.

for Chief Controller of Imports & Exports.

संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय भद्रास, 3 मार्च, 1984 भादेश संख्या 12/84 दिनांक 28-2-1684

का॰ प्रा॰ 835.—सर्वश्री सिल्ट्रानिक्स (इंडिया) लिमिटेड, होसर को एपर्य 1,86,900 तक प्रतिस्थापन फिल्टर्स, माडल एस-1 युवी स्टेरी-लाइजर्स का प्रतिस्थापन पुर्जे, माडल एसएल-10 ए युवी स्टेरीलाइजर्स का प्रतिस्थापन पुर्जे, गैस क्षोधक, माइसचर एनलाइजर्स भादि का भायात यू० के॰ तथा यू० एस० ए० से करने के लिए लाइसेंस संक्या पी/सीजी/2079078/ सी/एक्सएक्स/84/एम/82 विनांक 9-7-83 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेस की सीमाशुल्क प्रयोजनार्थ प्रति खो जाने के कारण उसके। अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए आखेदक ने आबेदन किया है उनसे यह भी कहा गया है कि उपर्युक्त लाइसेस, पंजीकृत सीमाशुल्क समाहर्ता, सीमाशुल्क सदन, एर कार्गो काम्पलेक्स, मद्रास-27 से की गयी है भीर लाइसेंस की उपयोग क्पये, 1,60,687.69 सक कर ली गयी है।

प्रावेदक ने अपने तर्क के समर्थन में एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। प्रघोहस्ताक्षरी इस बात से संतुष्ट है कि लाइसेंस संख्या पी/सीजी/2079078 दिनांक 9-7-82 की सीमाशुरक प्रयांजनार्थ प्रति की मूल प्रति खो दी गयी है और प्रादेश देता है कि उपर्युक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजनार्थ प्रति की अनुलिपि प्रति आवेदक को जारी किया जाये। सीमाशुल्क प्रति की मूल प्रति एतवृद्धारा रह किया जाता है।

रुपये 26,212.31 की सीमामुल्क प्रयोजनार्थ प्रति की प्रनुलिप प्रति संख्या की/246483 विनांक 21-2-84 ग्रलग जारी किया जाता है।

[संख्या : ग्राईटीसी/सीजी/शीजीटीडी/39/एएम 83,एयु-2]

(Office of the Jt. Chief Controller of Imports and Exports)

Madras, the 3rd March, 1984

ORDER NO. 12/84 Dt. 28/2/1984

S.O. 835.—M/s. Stroffics (India) Ltd., Hosur were granted a licence No. P|CG|2079078|C|XX|84|M/82 dated 9-7-1983 for Rs. 1,86,900 for the import of Replacement Filters. Replacement Parts for Model SI-1 UV Sterilizer, Replacement parts for Model SL-10 A UV Sterilizer, Gus Priciers, Moisture Analyser etc. from U.K. and USA. They have requested to issue a duplicate copy of Customs purpose copy of the above said licence which has been lost by them. Further it has been stated that the above licence has been registered with Collector of Customs (Customs House) Air Cargo Complex, Madras-27 and partly utilised for a value of Rs. 1,60,687.69.

In support of their contention the applicant has filled an affidavit, the undersigned is satisfied that the original C.P., copy of the licence No. P|CG|2079078 dated 9.7-1982 has been lost and directs that a duplicate copy of the said C.P. copy of the licence should issue to them. The original C.P. Copy of the licence is hereby cancelled.

A duplicate C.P. copy of licence No. D/246483 dated 21-2-1984 for Rs. 26,212,31 has been issued separately.

[No. ITC|CG|DGTD|39|AM.83|AU.II]

मादेश संख्या 11/84 दिनांक 4-2-84

का० धा० 836.— मर्वेश्वी कट्ट्योम्मन द्विंसपोर्ट कार्पिणन लिमि-टेड, सिरनेलर्षेली की, रुपये 5,00,000 तक डेनमार्क से एक ए एमसी (डेनमार्क) भाडल सी-4 सिलेंडर बोरिंग मणीन, एक एएमसी (डेनमार्क) माइल एच-250 सिलेंडर लैनर होनिंग मशीन धीर एक एएमसी (डेनमार्क) भाडल सीधारबी 150 सीधीएन राड बोरिंग मणीन का भाषात करने के लिए लाइमेंन संख्या पी/मीजी/2079353 दिनांक 3-3-1983 जारी किया गया था। लाइनेंमधारी से उपर्युक्त लाइसेंन की सीमाणुल्क प्रयोजनार्थ प्रति की प्रमुलिपि प्रति जारी करने के लिए इंसलिए प्रावेदन किया गया है कि उपर्युक्त लाइसेंस कियी भी नीमाणुल्क प्राधिकारी से पंजीकृत करवाये बिना और बिल्कुल उपयोग में लाये बिना खो दी गयी है।

प्रावेदक ने प्रपने तर्क के समर्थन में एक ग्रापथ-पन्न दाखिल किया है। प्रधोहस्ताक्षरी इस बात से संदुष्ट है कि लाइसेंस संख्या पी/मीजी/2079353 दिनांक 3-3-1983 की सीमाणुल्क प्रयोजनार्थ प्रति की मूल प्रति खो दी गयी है और प्रादेश देता है कि प्रावेदक को उपर्युक्त लाइसेंस की सीमाणुल्क प्रयोजनार्थ प्रति की प्रनुलिपि प्रति जारी किया जाय। लाइसेंस की सीमाणुल्क प्रयोजनार्थ प्रति की मूल प्रति एतबुदारा रह किया जाता है।

रुपये 5,00,000 के सीमाशुल्क प्रयोजनार्थ प्रति की प्रमुलिपि प्रति संख्या डी/2464830 दिनांक 3-2-1984 मलग जारी किया जाता है।

> [संख्या : ब्राईटीसी/सीजी/एयू/गैर-बौद्योगिक/31/एएम 83/एयु 2] सार्वीरफोरनास्डज, मुख्य नियंत्रुक

ORDER NO.: 11/84 Dated 4-2-84

S.O. 836.—M/s. Kattabomman Transport Corporation Ltd., Tirunelveli were granted a licence No. P/CG/2079353 dated 3-3-1983 for Rs. 5,00,000 for the import of one AMC (Denmark) Model C-4 Cylinder Boring Machine; One AMC (Denmark) Model H-250 Cylinder Liner Honing Machine and One AMC (Denmark) Model CRB 150 Con. Rod Boring Machine from Denmark. They were requested to issue a duplicate copy of Customs purposes copy of the above said licence which has been lost by them. Further it has been stated by them that the licence has not been registered with any Customs Authorities and utilised at all.

In support of their contention the applicant has filed an affidavit, the undersigned is satisfied that the original C.P. Copy of the licence No. P|CG|2079353 dated 3-3-1983 has been lost and directs that duplicate copy of the said C.P. Copy of licence should be issued to them. The original C.P. Copy of the licence is hereby cancelled.

A duplicate Customs Purposes Copy of licence No. D/2464830 dated 3-2-1984 for Rs, 5,00,000 has been issued separately.

[F. No. ITC/CG/AU|N. Indl.|31|AM 83|AU. II]
C. G. FERNANDEZ, Dv. Secv.

कर्जा मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 29 फरवरी, 1984

कां आ, 837—थतः भारत सरकार की प्रधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न प्रमुसूची में निर्दिष्ट किया गया है और पेट्रोलियम और खिनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखेण्ड (1) के अन्तर्गन प्रकाशित किया गयाहै, गुजरात राज्य में उक्त विनिर्दिष्ट भूमि में ध्यम्न स्थल मं मोटवान होडर से अंकलेश्वर सीटी एफ तक पेट्रोलियम परियहन के लिए भूमि में अपयोग के अधिकार प्रजिन किये गये हैं।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपयुक्त नियम के खण्ड-7 के उपखण्ड (1) की धारा (i) में विनिर्दिष्ट कार्य दिनांक 31-10-81 में समाप्त कर दिया है।

भतः भव भेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) नियम, 1963 के उपनियम-4 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी एतद्द्वारा उक्त तथि को कार्य समाप्ति की तिथि अधिसुचित करते हैं।

धनुसूची

मोटनान हीडर में ग्रकलेण्यर सी० टी० एफ० तक पाइप लाइन कार्य समाप्ति

मंत्रालय का नाम	· —— गांव	का ्मा ०	—— — — भारत के राज	- कार्य समाप्ति
	सं०	पक्त में प्रकामन की तिथि	की तिथि	
ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग)	मेलया	2761	2-7-83	31-10-81

[सं० ओ०-12016/58/82-प्रोइ0]

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 29th February, 1984

S. O. 837.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum & Minetals Pipeline (Acquisition of Right of user in land) Act 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d/s Motwan Header to ANK CTF in Gujarat State.

And Whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of subsection (1) of section 7 of the said Act on 31-10-81.

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notified the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of Pipeline From D.S. Motwan Header to ANK CTF

Name of Ministry	Village	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of opera- tion
Ministry of Energy (Deptt, of Petroleum)	Telwa	2761	2-7-83	31-10-81

[No. O-12016/58/82-Pro d.]

का० आ० 838 :—यतः भारत सरकार की ध्रिधसूचना के द्वारा नैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में निर्विष्ट किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) घ्रधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के धन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य में उक्त विनिर्विष्ट भूमि में व्याचन स्थल सं० एस० डी० एल० से एस० डी० एन० तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए धूमि उपयोग के अधिकार अजित किये गये हैं।

तेल एवं प्राकृतिक गैस घायोग ने उपयुक्त नियम के खण्ड 7 के उप-खण्ड (1) की धारा (i) में विनिर्दिष्ट कार्य दिनांक 23-11-82 से समाप्त कर दिया है।

भतः भव पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के भ्रधिकार का भ्रर्जन) नियम, 1963 के नियम-4 के भन्तर्गत सक्तम प्राधिकारी एतक्यारा . उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि भ्रधिसूचित करते हैं।

ग्रनुसूची					
एम औं एल से	ाएस डी एन	तक पा	इपलाइन कार्य	्रिममाप्ति	
मंत्रालय का नाम	गांव	का०ग्रा० स०	भारत के राजपक्ष में प्रकाशन की तिथि		
ऊर्जा मंत्रालय, (पेट्रोलियम विभाग)	्पारडी इंड्रीस	2372	28-5-83	23-11-82	

[सं ओ०-12016/52/82-प्रोप्ट०]

S.O. 838—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipeline (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. SDL to SDN in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 7 of the said Act on 23-11-82.

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE
Termination of Pipelinc from D.S. SDL to SDN

Name of Ministry Vi	llage	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of opera- tion
Ministry of Energy, Deptt. of Petroleum		2372	28-5-83	23-11-82

[No. O-12016/52/82-Prod.]

का० भा० 839:— यतः भारत सरकार की मिम्सूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है और पेट्रोलियम और अनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के भिन्नकार का अर्जन) मिध-नियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य में उक्त विनिर्दिष्ट भूमि में व्यथन स्थल संक एसक एनक एक जेक से एसक एनक एक मोक तक पेट्रोलियम परिवहन के लिए भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जित किये गये हैं।

े तेल एवं प्राकृतिक गैंस मायोग ने उपयुक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्ड (1) की धारा (i) में विनिर्विष्ट कार्य विनाक 12-11-82 से समाप्त कर विया है।

भतः भव पेट्रोलियम पाइपलाइन (मूमि के उपयोग के भिष्ठकार का भर्जन) नियम, 1963 के नियम 4 के भ्रम्तर्गत सक्षम प्राधिकारी एनद्द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि भिष्ठसुनित करते हैं।

मनुसूची

मंभ्रालय का नाम	गांव	का ंधा ० सं०	भारत के राजपन्न में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति तिथि
ऊर्जा मंत्रालय, (पेट्रोलियम विभाग)	कसलपूरा	3692	1-10-83	12-11-82

[सं 12016/51/82-प्रोपः]

S.O. 839.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipeline (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. SNAJ to SNAO in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 7 of the said Act on 12-11-82.

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE
Termination of Pipeline from D.S. SNAJ to SNAO

Name of Ministry Villa	ge S. N	O. o.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Ministry of Energy, Deptt. of Petroleum	Kasal Pura	3692	1-10-83	12-11-82

[No. 12016/51/82-Prod.]

का० प्रा०840 :—यतः भारत सरकार की प्रधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न प्रमुस्थी में विनिर्दिष्ट किया गया है और पेट्रोलियम और खिनज पाइप लाइन (मूमि के उपयोग के प्रधिकार का प्रजेम) प्रधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के प्रकार्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य में उक्त विनिर्दिष्ट भूमि में व्यवन स्थल संक्ष्म टी० बी० से मोटवान-1 तक पेट्रोलियम परिवहन के लिए भूमि में उपयोग के प्रधिकार प्रजित किए गये हैं।

तेल एवं प्राक्वतिक गैस मायोग ने उपयुक्त नियम के खण्ड 7 के उप-खण्ड (1) की धार्र (i) में विनिर्विष्ट कार्य दिनांक 14-6-83 से समाप्त कर दिया है।

श्रतः श्रवः पेट्रोलियम पाइप लाइन (भूमि के उपयोग के प्रधिकार का श्रजंन) नियम, 1963 के नियम 4 के श्रन्तर्गत सक्षम श्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त तिथि का कार्य समाप्ति को तिथि श्रधिसुचित करते हैं।

मनुसून। एम० टी० बी० से मोटवान-1 तक पाइपलाइन कार्य समाप्ति

मैंझालय का नाम	गांब	का ०मा० सं०	भारत के राजपत्न में प्रकाशन की तिथि	कार्यसमाप्ति कीतिथि
ऊर्जा मंझालय, (पेट्रोलियम विभाग)	मोटवान	3691	1-10-83	14-6-83

सिं० O-12016/42/83-प्रोड०]

ह/०-अप ठनीय

गुजरात के लिए नियमान्तर्गत सक्षम प्राधिकारी

S.O. 840—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of section 6 of the Peticleum & Mirerals Pipeline (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the

schadule appended thereto for the transport of petroleum from
d.s. MTB to Motwan-1 in Gujarat State.

And Whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of subsection (1) of section 7 of the said Act on 14-6-83.

Now Therefore under Rate 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of Pipeline from D.S. MTB to Motwan-1.

Name of Ministry	Village	S.O.No.		Date of termination of operation
Ministry of Energy, Deptt. of Petroleum		3691	1-10-83	14-6-83

[No. O-12016/42/83-Prod.]

Sd/-Illegible

Competent Authority under the Act for Gujarat

नई दिल्ली, 29 फरबरी, 1984

का॰, भा॰ 841:---यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह मावश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा-बरेली से अगरीशपूर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा अकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

भौर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईमों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एसद्वाबद्ध भनुसूची में वर्णित भूमि में खपयोग का भ्रधिकार मजित करना आवश्यक हैं ;

बतः बन्न पेट्रोलियम भीर सनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के मधिकार का मर्जन) भिधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का मधिकार भजित करने का प्रपता भाषय एतवृद्धारा घोषित किया है :

बसर्ते कि उक्त भूमि में हितबद कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राक्षीप सक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस ब्रायोग, निर्माण घीर देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस प्रधिमूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा;

भीर ऐसा ग्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्विष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

हजीरा-भरेली से अगवीशपूर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए ।

राज्यः गुज्रात	जिला : मूरत	त	तालुका : मागरोल		
गांव '	सर्वे नं०	हेक्टेयर	भार	सेन्टीयर	
1	2	3	4	5	
कोसंबा	889	0	30	70	
	892	0	19	68	
	89 १/पी	0	67	20	
	901	0	43	00	
	900	0	37	41	
	899	0	18	41 00	
	923	0	36	00	
	कार्ट द्रैक	0	04	08	

1,	-2	3	4	5
	840	0	59	89
	839	0	47	55
	838	0	15	18
	837	0	25	29
	कोटार	0	09	11
	745	0	14	16
	800	0	37	43
	801	0	08	09
	799	0	03	04
	798	0	47	55
	793	0	41	48
	794	0	27	31
	421	0	07	08
	420	0	27	31
	कोटार]∫	0	04	05
	422	0	41	48
	419	0	26	30
	418	0	21	25
	424	0	03	04
	425	O,	27	31
	331/1	0	13	18
	332	0	42	99
	2 2 9/पी	0	47	55
	229	0	47	55
	357	0	33	39
	358	0	03	04
	220	0	19	22
	221	0	22	26
	219	. 0 .	03	04
	223	0	05	06
	218	. 0	55	64
	209	0	46	54
	210	0	22	26
	206	0	13	15
	205	0	59	69
	200/भी	. 0	60	70
	कोकार	0	17	20
	[सं॰ प	ल, 120	16/3/89	-মাহ৹]
	rA. ≥.	ज्यान्योग (का	. 1 200 11	किस्तारी

पी० के० राजगोपालन, डैस्क प्रधिकारी

New Delhi, the 29th February, 1984

S.O. 841.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission:

And wheras it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user herein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009.)

714	THE GAZE	TIE OF INL)[A : M	ARCH 17	1984/PHALGUI	NA 4/, 1903	[1 AK.		3()1
And every per	rson making such a her he wishes to be	n objection at	hall also	o state / legal	1	2	3	4	5
ractitioner.		-		-		218	0	55	64
						209	0	46	54
	SCHEDULE	3				210	0	22	26
	SCHEDOLL	•				206	0	13	15
Pipeline	From Hajira—B	areilly to Jag	dishpur			205	0	59	69
State : Gujarat	Dist : Surat	Talı	ıka: Ma	ingrol		200/P	0	. 60	70
Village	Survey No.	Hectare Are	Cet	ntiare		K:otar	0	17	20
Kosamba	889	0	30	70					- 1
	892	Ō	19	68			[No. L-	12016/3/84	-Proa.
	891/P	ŏ	67	20					
	901	ŏ	43	00					
	900	ŏ `	37	41		मर्प विल्ली, 6	मार्च, 1984		
	899	ő	18	00		17 17 11) 0	, 2002		
	923	0	36	00	_	5.5	_ •	_ ^	
	Cart Track	o	04	08		8 4 2यतः केन्द्रीय		-	-
	840	ŏ	59	89	है कि लोकहित	में यह आवश्यक है कि	असम प्रदेश में	डिक्यूगढ़ जिल्	वान्तर्गत
	839	Ö	47	55	डिगबोई से तिन	त्सुकिया तक पेट्रोलिय	भ के परिवहन के	हे लिये पा	,पल दिन
	838	ő	15	18		कार्पोरेशन (आसाम अ			
	837	Ö	25	29		Antikan (Mizan	11441 1441417	Bride Lindle	* ***
	Kotar	0	09	11	चाहिये ।				
	745	0							
	800	=	14 37	16	और यतः य	यह प्रतीत होता है कि	ऐसी लाइनों को	विछाने के	प्रयोज
	801	0		43		क अनुसूची में पणित			
	79 9	0	08	09			dia a stata	the Allected	\ - 11 -1
	79 3 798	0	03	04 55	करना आ व ण्यक	. रहे ।			
	793	0	47	55					
		0	41	48	alitare over a	पेट्रोलियम और खनिय	e offenseites /s	ਹਿੰਦ ਹੈ ਤਹਾਂ	केस है
	794	• 0,	27	31					
	421 420	0	07	08		र्जन) अधिनियम, 19			
	Kotar	0	27	31	की उपधारा (।	1) द्वारा प्रदक्त शक्तियो	का प्रयोग करने	हुए केन्द्रीय	सरका
	422	0	04	05	ने उसमें उपय	ोग का अधिकार अर्जिल	त करने का अप	मा आशयंप	तवृद्धार
	419	0	41	48	घोषित किया है	t i			
	418	0	26	30		•			
	424	0	21	25					
•	425	0	03	04	ब्रागर्ने कि	उक्त भूमि में हितबद	लोई स्थकित प्राप	था कि की जी	चे प्राच्या
	331/1	0	27	31		के लिए लिखित आक्षे			
	331/1	0	. 15	. 18					
	229/P	0	42	99		(कर्मचारी-सेवायें), इ			
		0	47	- 55	(आसाम आयरू	न डिवीजन) डिगझोई-	-786171, को	इस अधिसूक	वसा क
	229 357	0	47	55		विनों के भीतर कर स		•	
	357 358	0	33	39			· - • ·		
	220	0	03	04					
	221	0	19	22	.a. a	आक्षेप करने वाला ह	er sufar feft		
	219	0	22	26	-		•		
		0	03	04		वह यह चाहता है		वाइ व्यक्ति	गत ह
<u></u>	223	0	05	06	्या किसी विक	धि व्यवसायी की मार्फ	त ।		

अनुसूची

डिब्रूगढ जिलान्तर्गत इंडियन आयल कारपोरेशन (आसाम आयल डिबीजन) डिबोई के न्यूटेंक फार्म से इंडियन आयल कारपोरेशन (आसाम आयल डिबीजन) के तिनमुक्तिया टर्मिनल डिपो तक पैट्रोलियम उत्पाद⊶-परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाना(सरकारी जमीन)।

कम रैवेन्थ्राम रिक्रमा	मीजा	वाग मंठ	क्षेत्रफल बी० क० सू०	क्रीफियत
ा. विगवोई टाउन	माभूम	448	0-1-0	सड़क की बगल की जमीन
2 बरबिस गांव नं० 2	11	144	006	रास्ता
 धरिबल गांव नं ० 3 	"	485	0-0-12	नाला
		451	0-0-0	"
		452	0-1-8	37
		310	0-0-8	रास्ता

कम रेवेन्यू ग्राम सं॰	मीजा	दाग नं०	क्षेत्रफल बी० अ० लू०	′ कैफियत
4. आउगुड़ी गांव पार्ट 4	टिपलिंग	454	0-2-8	बंजर जमीत
		480	0-0-13	रास्ता
 अपर मानोरोनी 	2)	116	0-2-12	संजर जमीन
 मामोरोनी पार्ट 2 	"	904	00-16	सड़क की सुरक्षित आरमीन
		675	0 → 0 → 4	रस्ता
 मामोरोनी पार्ट 1 	71	420	0-0-05	रास्ता
		414	0-0-8	11
		443	0-0-I2	J)
		394	0-2-12	n
		476	0-0-2	वंजर जमीन
3. आउग्रही पार्ट 1	ı)	1	8-0-11	n
		15	1-0-13	,,
		3	0-4-16	n
		637	1-1-6	मुरक्षित जमीन
		638	0-2-1	टिंगरई नवी
9. 1916/17/ का बब्स्यू० एस०	i r	18	0-2-11	मुरक्षित जमीन
ए० न० 33	<u>:</u>	40	0-0-10	20 फुट सुरिकात जमीन
इटाखुलो सी.इ		22	0-0-8	20 फुट ,, ,,
गार्जेन		23	0-0-9	20 फुट सुरक्षित जमीन
		4	0-0-9	रास्ता
		27	0-0-9	20 फुट सुरक्षित जमीन
o- रबरवाड़ी गांव	n	141	0-0-8	रास्ता
		94	0-0-12	सङ्क की बगल की जभीन
		96	0-0-8	रान्ता
		95	0-0-3	सुरक्षित अमीन
1 टिंगरई हवेदा मं० 1	10	111	0-0-3	सुर्कात जमीन
		110	0-0-4	रास्ता
		. 109	0-0-6	सुरक्षित जमीन
		117	0-0-10	रास्ता
		98	0-0-13	सुरक्षित जमीन
		97	0-0-8	रास्ता
		56	0-0-13	सुरक्षित जमीन
		47	0-0-13	11
		45	0-0-13	1)
		46	0-0-8	रास्ता
 टेंगापानी चाय बागान 	12	73	0-2-2	सुरक्षित जमीन
 हवेदा नं० 2 	,,	436	4-4-9	चरागाह
		79	0-0-3	बंजर जमीम
		482	00-11	p
		102	0-0-4	रास्ता
		28	0-1-15	रास्ता
		11	0-0-12	मोसा
4- लाहोरी शंगाली गांव	तिमसुकिया	161	0-1-18	टिंगरई नदी
- 		369	0-2-18	बंअर जमीन
		362	0-0-5	बंजर जमीन
		117	0-0-6	रास्ता
		98	0-0-7	n .
		132	0-1-5	अंजर अमीन
. इ. साहोरी नेपाली गांव	11	236	0-0-15	नाला
•		206	6-2-9	चरागाह
। ६. पश्चरी जन	i.	232	5-2-8	चरागाह
	D	-04	U = U	1 2.1.10

क्रमसं० रैवैन्यूपाम	मोजा	दोग में	क्षीफफल बी०केल सू	केफियत
17. पटिया पठार नं० 2	तिनसु किया	15	0-0-10	रास्ता
	,,	14	0-0-13	सङ्ककी बनल की अमीन
। 8 पटिया पठार नं 1 ाँ		ż	0-4-6	रेलवे मुरक्षित जमीन
19 तिनसुकिया टाउँन	71	405	8-3-11	रेलवे सुरक्षित जमीन
		502	0-1-5	रास्ता
		4588	0-2-10	रेलवे सुरक्षित जमीन
		4587	0-0-9	रेलवे लाइन
		4586/	0-2-12	रेलवे सुरक्षित जमीन
		3051	0-0-5	रास्ता
		3752	0-0-5	रास्ता
		कुल क्षेत्रफल	45-0-3	

[सं॰ O-12016/4/84-प्रीड॰] पी॰के॰ राजा गोंपालन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 6th March, 1984

S.O. 842.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that a Petroleum Product Pipeline from the New Tank Farm of Indian Oil Corporation Limited (Assam Oil Division) situated in Digboi Town to the Tinsukia Terminal Depot of Indian Oil Corporation Limited (Assam Oil Division) in Tinsukia Town, within the Dibrugarh District be laid by Indian Oil Corporation Limited (Assam Oil Division).

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire the Right of User in the Land described in the Schedule annexed hereto.

Now, in exercise of powers conferred by Sub-section 1 of Section 3 of the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (Act 50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the said pipeline on the land, mentioned in the Schedule hereto, to the Competent Authority, namely Shri Jugal Chandra Borah, Manager (Employee Servaices), IOC Ltd., (AOD), Digboi-786171 in writing.

And every person making such objection shall also state specifically whather he/she wishes to be heard in person or by legal practitioner.

(SCHEDULE)

Laying of Petroleum Product Pipeline from New Tank Farm of Indian Oil Corporation Limited (Assam Oil Division) at DIGBOI to Tinsukia Terminal Depot of Indian Oil Corporation Limited (Assam Oil Division) at TINSUKIA within Dibrugarh District. (Govt. Land)

Sl. No. Revenue Villago	Mouza	Dag No.	Area B-K-L	Remarks
1. Djgboi Town	Makum	448	0-1-0	Road side reserved land.
2. No. 2 Borbil	-do-	144	0-0-6	Path
3. No. 3 Borbil	-do-	485 451 452 310	0-0-12 0-0-0 0-1-8 0-0-8	Stream " " Path
4. Ouguri Part IV	Típlin g	454 480	0-2-8 0-0-13	Waste land Path
5. Opar Mamoroni	-do-	116	0-2-12	Waste land
6. Mamoroni Part II	≁do-	904 675	0-0-16 0-0-4	Road Reservation Path
7. Mamoroni Part I	-do-	420	0-0-5	Path
		414	0-0-8	Path
		443	0-0-12	Path
		394	0-2-12	Path
		476	0-0-2	Waste land

Sl. No. Revenue Village	Mouza	Dag No.	Area B-K-L	Remarks
8. Ouguri Part I	Tipling	1	5-0-11	Waste land
• •		. 15	1-0-13	Waste land
		3	0-4-16	Waste land
		637	1-1-6	Reserved land
		638	0-2-1	Tingrai river
WLA No. 33 of 1916/17 Itakhuli Seed	Tipling	18	0-2-11	Reserved land
Garden		40	0-0-10	20/ reservation
•		22	0-0-8	20/ reservation
		23	0-0-9	20/ reservation,
		4	0-0-9	Road
	•	27	0-0-9	20/ reservation
. Rabarbari Gaon	Tipling	141	0'-0-8	Path
		94	0-0-12	Road side reserved land
		96	0-0-8	Ro id
		95	0-0-3	Road side reserved land
. Tingrai Haveda No. 1	Tipling	111	0-0-3	-do-
-		110	0-0-4	Road
		109	0-0-6	Road side reserved land
		117	0-0-10	Path
		98	0-0-13	Road side reserved land
		97	0-0-8	Road
		56	0-0-13	Road side reserved land
		47	0-0-13	-do-
		45	0-0-13	-do-
		46	0-0-8	Road
2. Tengapani T. E	Tipling	73	0-2-2	Reserved land
3. No. 2 Haveda	Tipling	436	4-4-9	Grazing reserve
		79	0-0-3	Waste land
		482	0-0-11	Waste land
		102	0-0-4	Path
		28	0-0-15	Path
		11	0-0-12	Stream
4. Lahori Bongali Gaon	Tinsukia	161	0-1-18	Tingral river
		369	0-2-18	Waste land
	Y	362	0-0-5	Waste land
		117	0-0-6	Path
		98	0-0-7	Path
		132	0-1-5	Waste land
5. Lahori Nepali Gaon	-do-	236	0+0-15	Stream
		206	6-2-9	Grazing reserved
6. Pakharijan	-do-	232	5-2-8 0-1-10	-do-
		214		Path
7. No. 2 Patia Pathar	-do-	15	0-0-10	Road
		14	0-0-13	Road side reserved land
8. No. 1 Patia Pathar	-do-	2.	0-4 - 6	Rly, reserved land
9. Tinsukia Town	-do-	405	8-3-11	Rly. reserved land
- 		502	0-1-5	Road
		4588	0-2-10	Rly, reserved land
		458 7	~ 0~0~ 9	N.F. Rly. line.
		4586	0-2-12	Rly. reserved land
		3051	0-0-5	Road
		3752	0-0-5	Road
		Total Area:	45-0-3	

नई दिल्ली, 3 मार्च, 1984

का० ग्रा० 843—पेट्रोलियम ग्रीर खितज पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के ग्रिवकार का ग्रिविग्रहण) श्रिवित्यम, 1962 (1962 को 50) के श्रारा 2 के खण्ड (क) के ग्रतुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नीचे शी गई ग्रनुसूची के कालम 1 में उल्लिखित प्राधिकारियों को, इस श्रिवियम के श्रन्तगंत उक्त ग्रनुसूची के कालम (3) की तदनुष्पी प्रविद्धि उल्लिखित क्रिपुरा राज्य की सीमाओं के भीतर सक्षम प्राधिकारियों का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

प्राधिकारी	पता	अन्नाधिकार - —
1. भूमि श्रष्टिग्रहण कलक्टर ≀	पश्चिम तिपुरा बाकखान अगरतल्ला पिन- 799001	-
2. भूमि प्रधिग्रण कलकटर	दक्षिण न्निपुरा डान- खाना श्रार० के० पुर० जिला दक्षिण न्निपुरा पिन-799120:	•
3. भूमि श्रक्षिप्रहण कलकटर	उत्तर त्रिपुरा डाक- द्याना केलागहर पिन- 799277	

[संख्या श्री- 11011/3/83 - उत्पादन] बिनय अंसल, निदेशक

New Delhi, the 3rd March, 1984

S. O. 843:— In pursuance of clause (a) of section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby authorises the authorities mentioned in column (1) of the Schedule below to perform the functions of the Competent Authorities under the said Act within the limits of the State of Tripura mentioned in the corresponding entries in column (3) of the said Schedule:

SCHEDULE

Authority	Address	Territorial Jurisdi		
(1)	(2)	(3)		
1. Land Acquisition Collector	West Tripura, P.O. Agartala, Pin: 799001.	West Tripura District Tripura State.		
2. Land Acquisition Collector	South Tripura, P.O. R.K. Pur, Distt: South Tripura Pin: 799120	South Tripura, District, Tripura Stato.		
3. Land Acquisition Collector	North Tripura, P.O. Kailashahar, Pin: 799 277.	North Tripura District, Tripura State		

[No. O-11011/3/83—Prod.] VINAY BANSAL, Director

(कोयला विभाग) नई विल्ली, 1 मार्च, 1984

का॰ आ॰ 844 — केन्द्रीय सरकार ने, कीयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन, भारत के राजपन्न, भाग 2, खांड 3, उपखंड (ii) तारीख 1 अगस्त, 1981 में प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं॰ का॰ आ॰ 2087, तारीख 16 जुलाई, 1981 द्वारा इससे संस्मन अनुमूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 960.00 एकड़ (लगभग) या 388.50 हैक्टर (लगभग) माप की सूमि की बाबत कीयले का पूर्वेक्षण करने के अपने अभिय की सूचना दी थी;

और, उक्त भूमि की बाबत उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना नहीं दी गई थी,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रक्त शिवतयों का प्रयोग करते हुए 1 अगस्त, 1983 से प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की और अवधि को ऐसी अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसके भीतर केन्द्रीय सरकार उक्त भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना बेती है।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली मूमि में हितबद्ध सभी व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट नक्को खार्ट और अन्य दस्तावेजें राजस्व अधिकारी सेन्द्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, दरभंगा हाउस, रांची (विहार) को इस अधिसूचना के राजस्व में प्रकाशन की तारीख से 90 दिन के भीतर परिवक्त करेंगे।

अनुसूची सुगिया खण्ड (पण्डिमी बोकारो कोयला क्षेत्र)

कम सं० भ्राम	थाना	ंधामा संख्यांक	जिला	क्षेत्र	टिप्प- णियां
1. सुगिया	मोबु	177	ह्जारींबाग	960.00	भाग

कुल क्षेत्रफल : 960.00 एकड्रृ (लगभग) . या 388.50 हैनटर (लगभग)

सीमा वर्णनः

- क-ख रेखा नाले की भागतः मध्य रेखा के साथ-साथ जाती है (जो कर्मा और मुगिया ग्रामों की भागतः सम्मिलित सीमा और बुराखप और सुगिया ग्रामों की सम्मिलित सीमा है) और बिल्हु "ख" पर मिलती है।
- ख-ग रेखा बामोदर नदी की मध्य रेखा के साथ जाती है (जो सुगिया और कैथा, सुगिया और गोबरदाहा, सुगिया और हाहुआ ग्रामों की सम्मिलित सीमा तथा सुगिया और लौधमा ग्रामों की भागत: सम्मिलित सीमा है) और बिन्दु "ग" पर मिलती है।

ग-घ

- इ-च रेखाएं दामोदर नदी से होकर सुनिया प्राम से होकर जाती हैं (जो सुनिया कोयला खान की पट्टाधृत सीमा के साथ सिम्मिश्लत सीमा है) और बिन्दु "च" पर मिलती है।
- ा-छ रेखा दामोदर नदी की भागतः मध्य रेखा के साय-साथ जाती है (जो लोधमा और सुगिया प्राप्तों की भागतः सम्मिलित सीमा है) और बिन्दु "छ" पर मिलती है।
- छ-ज़े रेखा, नाले की भागतः मध्य रेखा के साथ जाती है (जो सुनिया और बार्की बुन्डी ग्रामों की भागतः सस्मिलिस सीमा है) और बिन्दु "ज" पर मिलती है।

117

ज-क रेखा सुगिया ग्राम से होकर जाती है और आरम्भिक बिन्दु 'क'
पर भिसती है।

टिल्पण :1रेखानिज्ञ सं० 42/81-ता० 13-4-81 (जिसमें पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित भूमि वर्षित की गई है) सेन्द्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, दरभंगा हाउस, रांची (बिहार) और कोयला नियंत्रक, 1, काउ-सिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में देखा जा सकता है।

[स॰ 19/20/81-सी०एल०]

समय सिंह, अवर सचित्र

(Department of Coal) New Delhi, the 1st March, 1984

S.O. 844.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 2087 dated the 16th July, 1981 under subsection (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii) dated the 1st August, 1981, the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in Iands measuring 960.00 acres (approximately) or 388.50 hectares (approximately) in the locality specified in the Schedule appended hereto;

And whereas in respect of the said lands, no notice under sub-section (1) of section 7 of the said Act has been given;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby specifies a further period of one year commencing from the 1st August, 1983, as the period within which the Central Government may give notice of its intention to acquire the said lands or any rights in or over such lands;

All persons interested in the lands covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred to in sub-section (7) of section 13, of the said Act to the Revenue Officer, Central Coalfields Ltd., Darbhanga House, Ranchi (Bihar) within 90 days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

Sugia Block
(West Bokaro Coalfield)

Scrial Numb	_	Thana I	Thana Yumbo		Arca	Rer	narks
1,	Sugia	Mandu	177	Hazariba	sgh 9	50,00	Part
,- 	To	tal Area	960,	00 acres	(appro	xima*	oly)
	01	•	388,5	0 hectar	es (apr	roxin	ately)

Boundary description :--

- A-B. line passes along the part central line of Nala (which forms part common boundary of villages Karma and Sugia) and common boundary of village Burakhap and Sugia) and meets at point 'B'.
- B-C. line passes along the part central line of Damodar River (which forms common boundary of villages Sugia and Kaitha, Sugia and Gobardaha, Sugia and Hahun and part common boundary of villages Sugia and Lodhma) and meets at point 'C'.
- C.D.E.F. lines pass through Damedar River, through village Sugia (which forms common boundary with

- the lease hold boundary of Sugia Colliery) and meets at point 'F'.
- F-G. the passes along the part central line of Damodar River (which forms part common boundary of villages Lodhma and Sunia) and meets at point 'G'.
- G-H. line passes along part central line of Nala (which forms part common boundary of villages Sugia and Bakri Dundi) and meets at point 'H',
- H-A. line passes through village Sugia and meets at starting point 'A'.

NOTE.—1 Drawing No. 42/84 dated 13-4-81 (showing Land notified for prospecting) can be seen at the office of the Central Coalfields Ltd., Darbhanga House, Ranchi (Bihar) and the Coal Controller 1, Council House Street, Calcutta.

[No. 19/20/81-CL]

का० ग्रा० 845.--कीयला धारी क्षेत्र (ग्रधिग्रहण भौर विकास) भिधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 19 द्वारा प्रदेश सक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के भृतपूर्व इस्पात, खान ग्रीर ईंधन मंतालय (खान ग्रीर इंधन विभाग) के सा० का० नि० सं० 1933 दिनांक 10 जून, 1957, सा० का० नि० सं० 158 दिनांक 2 जनवरी, 1958, सा॰ ग्रा॰ सं॰ 2434 दिनांक 26 सितम्बर, 1960 श्रीर भृतपूर्व इस्पान और खान मंत्रालय (खान ग्रीर धात विभाग) के सा० ग्रा० सं० 2837 विनोक 11 धगस्त, 1964, सा० धा० सं० 3501 विसांक 4 नवस्त्रर, 1965 श्रीर आदेश सं० सी 2-1(27)/57 दिनांक 15 जुलाई, 1957, सं॰ सी 2-1(6)/58 दिनांक 12 मार्च, 1958, सं॰ सी 2-1(5)/ 59 विनांक 23 जुलाई, 1959, सं० सी-2-1(1)/64 दिनांक 6 मर्ड, 1964 और सी 2-1(1)/64 दिनांक 2 नवम्बर, 1965 की अधि-सचनात्रों का श्रधिकमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतदुहारा यह निदेश करती है कि उक्त प्रधिनियम की इस प्रधिसूचना के साथ संलग्न ग्रनुसूची के कालम 2 में निर्विष्ट धाराओं के अधीन प्रयुक्त सभी शक्तियों (या किसी एक गक्ति) प्रथवा निष्पावित सभी कर्मव्यों (या किसी एक कर्त्तव्य) का प्रयोग या निष्पादन उन व्यक्तियों द्वारा भी किया जाएंगा जो उक्त प्रनुसूची के कालम 4 की तदनुरूपी प्रविष्टि के सामने निर्विष्ट किए गए हैं;

किंतु प्रावधान यह है कि उक्त ध्रिधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के प्रधीन गिष्तयों और कर्संज्यों का प्रयोग और निष्पादन केन्द्रीय सरकार के पूर्व धनुभोदन पर ही किया जाएगा जबकि राजस्व प्रमुख, धपर प्रमुख (राजस्व), उपप्रमुख (राजस्व) धौर सहायक-प्रमुख (राजस्व) द्वारा उक्त प्रधिनियम की धारा 21 के ध्रधीन गिष्तियों भौर कर्संज्यों का प्रयोग और निष्पादन ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी गती, यदि कोई हो, के भ्रेनगैत किया जाएगा जो सेंट्रल कोल्फील्ड्स लिंक, रांची के प्रवंध निवेशक और/अथवा निवेशकों द्वारा लिखित रूप में धादेश करके विनिर्विष्ट और निर्वेशित की गई हों।

मनुसूची

	911	
क्रम अधिनियम सं० की घारी		जिन व्यक्तियों को शक्तियां प्रत्या- यित की गई हैं उनके पदनाम धीर कार्यालय के पते
1 2	3	4
1. 14(1)	मुष्रावजा निर्धारित कर की पद्यति	ने प्रबंध निवेशक, सेंट्रल कोलफील्ड्स सि०, रांची निदेशक ,,

1	2	3 .	4	1	2	3 4
·		रा	जस्य प्रमुख, प्रबंध निदेशक			(राजस्व) प्रबंध निदेशक,
		ৰ্মা	तरिक्त प्रमुखः संदूल कोलफील्डस			उप प्रमुख सेंदूल कोलफील् इ स
			(राजस्व) लि० रोची			(राजस्व) ,, स्नि०, राची
			उप प्रमुख			सहायक प्रमुख
			(राजस्व) 🕟 🔐			(राजस्व) ,, ,,
			महायक प्रमुख ,,			कोयला नियंत्रक 1, काउंसिल
			(राजस्व) ", ",			हाउस स्ट्रीट,
2.	14(4)	मुग्रावजे के संबंध में	प्रअंध निवेशक ।			कलकता
4.	**(*)	न्यायाधिकरण के समक्ष	िनेपाक			उप-कोयला
		वित्ररण-पद्म	Train nile			नियंत्रक 🥠 🕠
		विवादन (स	राजस्य-अनुस्कातः स्रतिरिक्त प्रमुख			
			(20 222)			[सं॰ 19/54/83-सी॰ एन०]
			(राजस्य <i>) ,, ,,</i> उप-प्रमु च			समृय्सिह्, भवर संचिव
			(areas			
			(राजस्य) ,, ,, सहायक प्रमुख			
			(100mm)			f the powers conferred by section
				ment) Ac	t, 1957 (20 of 1	Areas (Acquisition and Develop- 1957), and in supersession of the
3.	16	म्यायाधिकरण के फैसले	प्रबंध निवेशक,, ,,	Notification	ms of the Govern	ment of India in the late Ministry
		षर स्याज का भुगतान	निदेशक, ,, ,,	S.R.O. No), 1933 dated the	(Department of Mines and Fuel) 10th June, 1957, S.R.O. No. 158
			राजस्य प्रभुखः ,, ,,			58, S.O. No. 2434 dated the 26th
			मतिरिक्स प्रमुख			Late Ministry of Steel and Mines and Metals) S.O. No. 2837 dated
			(राजस्व) ,, ,,	the 11th A	August, 1964, S.O.	No. 3501 dated the 4th Novem-
			उप- प्रमुख			lo, C-2-1(27)/57 dated the 15th /58 dated the 12th March, 1958,
			(राजस्व) " "	No. C2-1((5)/59 dated the	23rd July, 1959, No.C-2-1(1)/64
			महायक प्रमुख			and C-2-1(1)/64 dated the 2nd atral Government hereby directs
			(राजस्य) ,, ,,	that all or	r any of powers	or duties which may be exercised
4.	17	मुघावजे का भुगतान	3 7			Government under such of sections wified in column 2 of the Schedule
_		•	िक्रेसक	hereto ani	nexed shall be ex	xercised or discharged also by the
			TENTE LITE		ecified against in aid Schedule:	the corresponding entry in column
			राजस्य मनुष्य ,, धतिरिक्त प्रमुख			
			(राजस्व) ,, ,,	B 11		
			उप प्रमुख			ise and discharge of powers and 1) of section 14 of the said Act
			(राजस्व) ,, ,,			revious approval of the Central
			सहायक प्रमुख		•	exercise and discharge of powers
			(राजस्व) ,, ,,			1 of the said Act by the Chief of (Revenue), Deputy Chief (Re-
	0.1	सूचना प्राप्त कराने की	प्रबंध निवेशक ,, ,,			ief (Revenue) shall be in such
5.	21	भूषना प्राप्त करान का शक्ति	Er)mer			uch conditions, if any, as may be
		बा। बहुर		specified a	and directed by o	rder, in writing, by the Managing
			राजस्व प्रमुखः,, ,, श्रतिरिक्तं प्रमुखः			ctors of the Central Coal Fields
			भावायस्य मनुष	Limited, I	Ranchi.	•

SCHEDULE

SI. No.	Section of the Ac		Designation and off	icial address of the perso	ons delegate	ed with powers
	2	3		4	·	
 I	14(1).	method of determining compensation	Managing Director,	Central Coalfields Ltd.,	Ranchi,	
	* 11-7 -		Directors.	**	**	
			Chief of Revenue,	59	**	
			Additional Chief			
			(Revenue),	78	7)	
			Deputy Chief			
			(Revenue),	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	
			Assistant Chief			
			(Revenue),	**	,,	

1 2	3	4	5	6
$2.14(\overline{4})$	Statement before the Tribunal regarding	Managing Directors,	Central C	Coalfields Limited, Ranchi.
	compensation.	Directors,	,,	21
		Chief of Revenue,	19	13
		Additional Chief	,,	"
•		(Revenue).		"
		Deputy Chief	,,	"
		(Revenue),	,.	<i>"</i>
		Assistant Chief	,,	11
		(Revenue),	•	,,
3. 16	Payment of interest on award of the	Managing Director,	"	**
	Tribunal	Directors,	13	***
		Chief of Revenue,	**	**
		Additional Chief	**	11
		(Revenue),		
		Deputy Chief	1,	**
		(Rovenue),		
		Assistant Chief	**	**
		(Revenue),		
4. 17	Payment of Compensation	Managing Director,	**	"
		Diriectors,	11	**
		Chief of Revenue,	,,	**
		Additional Chief	**	**
		(Rovenue),		
		Deputy Chief	**	"
		(Revenue),		
		Assistant Chief	,,	"
		(Revenue),		
5, 21	Power to obtain information	Managing Director,	1,	19
		Directors,	**	**
		Chief of Revenue,	,,	11
		Additional Chief	"	**
		(Rovenue),		
		Deputy Chief (Revenue)	nue), " "	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
		Assistant Chief	79	
		(Revenue),		
		Coal Controller	1,	Council House Street, Calcutta.
		Deputy Coal Controller	**	***

[No. 19/54/83-CL]

नई दिल्ली, 3 मार्च 1984

का० आ० 846.—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (ग्रजंन घौर विकास) प्रधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) के प्रधीन, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की धाक्षिसूचना सं० 2843 दिनांक 15 जुलाई, 1982 द्वारा उस प्रधिसूचना—जो:भारत के राजपन्न, भाग 2 खंड 3 उपखंड (ii) दिनांक 7 प्रगस्त, 1982 में प्रकाणित की गई थी—से सलग्न ध्रमुसूची में विनिर्विष्ट परिक्षेत्र की 349.00 एकड़ (लगभग) या 141.23 हेक्टेयर (लगभग) भूमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के प्रपत्ने ध्रावय की भूचना दी थी;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त भूमि में कोयला श्रमिप्राप्य हैं;

श्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रीक्षियम की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे संनग्न श्रनुसूची में वर्णित 349.00 एकड़ (लगभग) या 111.23 हेक्ट्यर (लगभग) माप की भूमि का श्रजैन करने के प्रपते श्राक्षय की सूचना देती है।

टिप्पण 1: इस मधिसूचना के मधीन म्राने वाले रेखांक का निरीक्षण, उपायुक्त, गिरीक्रीह (बिहार)के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1515 GI/83-- 4 काउंमिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में ब्रथवा मेंट्रल कोलफील्ड्म लि० (राजस्य अनुभाग) वरमंगा हाउम, रांची (बिहार) के कार्यालय में किया जा सकता है।

टिप्पण-2: कोयला धारक क्षेत्र (प्रजेन और विकस) मिश्रनियम, 1957-(1957 का 20) की धारा 8 के उपबंधों की मीर स्थान ग्राकुष्ट किया जाता है जिसमें निम्नलिखन उपबंधित है---

"8(1) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में जिसकी बाबत धाराः 7 के अधीन प्रधिमूचना जारी की गई है, हितबढ़ है, प्रधिसूचना के जारी किए जाते के तीम दिन के भीतर संपूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर किन्हीं प्रधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में प्रापत्ति कर मकेगा।

स्पष्टीकरण :

इस धारा के भ्रयान्तर्गत यह भ्रापत्ति नहीं मानी जाएगी की कोई व्यक्ति किमी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं श्वनन संक्रियाएं करना चाहता है भौर ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी भन्य व्यक्ति के द्वारा नहीं की जानी चाहिए।

(2) उपधारा (1) के प्रधीन प्रत्येक ग्रापत्ति सक्षमा प्राधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी ग्रीर सक्षम प्राधिकारी ग्राप्तिकर्ता को स्वयं सुने जाने का या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का श्रवसर देगा और ऐसी सभी आपित्यों को सुनने के पण्चात् और ऐसी प्रतिस्थित जांच, यदि कोई है, करने के पण्चात् जो वह भावस्यक समझता है वह या तो धारा 7 की उपधारा (1) के भधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न दुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आपित्यों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्रवाई के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबब समक्षा जाएगा जो प्रतिकर में हित का दावा करने का हकतार होता यदि भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर प्रधि-कार इस ध्रधिनियम के ध्रधीन प्रजिस कर लिए जाते।"

टिप्पण-3 केन्द्रीय सरकार ने, कोयला नियंत्रक, 1, कार्जिसल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता को उकत प्रधिनियम के श्रधीन सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है।

> अनुसूर्घा गुंजरबीह क्लाक विस्तार (पूर्वी बोकारो कॉयला क्षेत्र) विहार

रेखाचित्र सं० राजस्व/14/83 दिनोक 30-5-1983

(जिसमें म्रजित की जाने वाली भूमि दिशित की गई) सभी मधिकार

ऋ० ग्राम सं	याना	थाना सं	o जिला	क्षेत्र	टिप्प- णियां
1. माकोली	नवाडीह (अरमो)	69	 गिरीडीह्	52,25	भाग
2. गुंजरडीह	नवा डी ह (बेरमो)	72	गिरीक्वीह	230.25	भाग
3. चपरी	नवासीह् (वेरमो)	73	गि री डी ह	66,50	भाग
	 कल क्षेष	349.00	एकड (लग	म ग)	

कुल क्षेम्न 34.9,00 एकड़ (लगभग) या 14.1.23 हेम्टर (लगभग)

ग्राम माकोली में प्रजित की जाने वाले प्लाटों की संख्या 1(भाग) ग्राम गुंजरडीह में प्रजित की जाने वाले प्लाटों की संख्या 212(भाग) ग्राम जपरी में प्रजित की जाने वाले प्लाटों की संख्या : 1440(भाग)

र्¦ावर्णन

्र-ख रेखा ग्राम चपरी में प्लाट सं० 763,764,767 शौर 766 से होकर जाती है शौर बिष् ''ख'' पर मिलती है।

ख-ग-ध- रेखाएं ग्राम चपरी में प्लाट सै० 1440 में से माकोली ड-च ग्राम में प्लाट सं०-1 ग्रीर गुंजरडीह ग्राम में प्लाट सं 212 से होकर जाती है (ओ कोयला ग्रिधिनयम की धारा 9) (1) के प्रधीन ग्रीजित गुंजरडीह की सम्मिलित सीमा है ग्रीर थिंदु "च" पर मिलती है।

च-छ-ज रेश्वाएं ग्राम गुजरडीह से होकर जाती है और बिंदु ''ज' पर मिलासी है।

ज-झ रेखा ग्राम गुंजरहीह के प्लाट सं० 160,155 की पूर्वी सीमा प्लाट सं० 158 की पूर्वी भीर विभागी सीमा प्लाट सं० 153 भीर 152 की दक्षिणी सीमा प्लाट सं० 155, प्लाट सं० 91,78 की पूर्वी सीमा प्लाट सं० 77,78, प्लाट सं० 76 की उसरी सीमा पूर्वी भीर दक्षिणी मीमा, प्लाट सं० 80 की भागतः पूर्वी भीर विकाणी सीमा, प्लाट सं० 71,72 73 की पूर्वी सीमा, प्लाट सं० 71,72 73 की पूर्वी सीमा, प्लाट सं० 74 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ और भागतः दक्षिणी सीमा प्लाट सं० 212 और प्लाट सं० 75 की भागतः पूर्वी सीमा से होकर जानी है भीर बिदु "स" पर मिलती है।

झ ज-ट-ठ- रेखाएं ग्राम गुंजरडीह श्रीर माकोली, चपरी श्रीर माकोली ड की भागकः सम्मिलित सीमा के साथ साथ जाती है श्रीर बिंदु "उ" पर मिलती है।

इ-ढ़ रेखा निमरी नदी के भागन : दांग्रे किनारे के माथ-साथ जाती है श्रीर बिंदू "ढ़" पर मिलती है।

ढ़-क रेखा ग्राम चपरी के प्लाट मं० 1440 से होकर जाती है शौर श्रारंशिक बिद् ''क' पर मिलनी है।

> [सं० 19/39/83-सी० एल०] समय सिंह, भवर सिंव

New Delhi, the 2nd March, 1984

S.O. 846.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal), No. S.O. 2843 dated the 15th July, 1982, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (il), dated the 7th August, 1982, under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act. 1957 (20 of 1957), the Central Government gave noitee of its intention to prospect for coal in 349.00 acres (approximately) or 141.23 hectares (approximately) of the lands in the locality specified in the Schedule appended to that notification;

And whereas the Central Government is satisfied that coal is obtainable in the said lands;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the said lands measuring 349.00 acres (approximately) or 141.23 hectares (approximately) described in the Schedule appended hereto;

- Note 1: The plan of the area covered by this notification may be inspected in the Office of the Deputy Commissioner, Girklih (Bihar) or in the Office of the Coal Controller, I. Council House Street, Calcutta-1 or in the Office of the Central Coalfields Limited (Revenue Section), Darbhanga House, Ranchi (Bihar).
- Note 2. Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act. 1957. (20 of 1957), which provides as follows:—
- 8(1) Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued may, within thirty days of the issue of the Notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any rights in or over such land.
- Explanation: It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operations should not be undertaken by the Central Government or by any other person.
- (2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing, and the competent authority shall give the objector and opportunity of being heard either in person or by a

legal practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary, either make a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of section 7 or of rights in or over such land, or make different reports in respect of different parcels of such land or of right in or over such land to the Central Government, containing his recommendations on the objections, together with the record of the proceedings held by him, for the decision of that Government.

(3) For the purposes of this section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim on interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act".

Note 3: The Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta, has been appointed by the Central Government as the competent authority under the Act.

SCHEDULE Gunjardih Block Extn. (East Bokaro Coalfield) (Bihar)

Drg. No. Rev/17/83 Dated: 30-5-83

(Showing lands to be acquired)

All Rights:

H-I

Serial Village Number	Thana	Thana Numbe	District	Area	Re- marks
1. Makoli	Nawadih (Bermo)	69	Giridih	52.25	Part
 Gunjardih Chapti 	"	72 73	Giridih Giridih	230.25 66.50	Part Part

Total area: 349.00 Acres (Approximately)

or 141.23 Hectares (Approximately)

Plot number to be acquired in village Makoli: 1 (Part). Plot number to be acquired in village Gunjardih: 212 (Part). Plot number to be acquired in village Chapri: 1440 (Part). Boundary description:—

A—B line passes along eastern boundary of plot numbers 763, 764, 767 and 766 in village Chapri and meets at point 'B'.

B-C-D-E-F lines pass through plot number 1440 in village Chapri, through plot number 1 in avillage Makoli then through plot number 212 in village Gunjardih (which forms common boundary of Gunjardih block acquired u/s 9(1) of the said Act and meet at point 'F'.

F-G-H lines pass through plot number 212 in village Gunjardih and meet at point 'H'.

line passes along eastern boundary of plot numbers 160, 155, eastern and southern boundary of plot number 158, southern boundary of plot number 153, eastern and southern boundary to plot number 155, eastern and southern boundary of plot number 154, southern boundary of plot numbers 153 and 152 southern boundary of plot numbers 155, eastern boundary of plot numbers 91, 78, eastern and southern boundary of plot numbers 77, Northern boundary Eastern & Southern boundary of 76, part eastern and southern boundary

of plot number 80, eastern boundary of plot numbers 71,72,73, eastern boundary and part southern boundary of plot number 74, through plot number 218 and part eastern boundary of plot number 75 in village Gunjardih and meets at point 'I'.

I-J-K-L-M lines pass along the part common boundary of villages Gunjardih and Makoli, Chapri and Makoli and meet at point 'M'.

M—N line passes along the part right bank of
Tisti Nadi in village Chapri and meet at
point 'N'.

line passes through plot number 1440 in village Chapri and meets at Starting point 'A'.

[No. 19/39/83—CL] SAMAY SINGH, Under Secy.

(বিহুদ বিমান)

नई (बल्ली, 1 मार्च, 1984

काव आव 847.—केन्द्रीय सरकार, पजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 80 की उपधारा (5) के अनुसरण में, ब्याम परियोजना यूनिट-1 और यूनिट-2 के निम्निखित संघटकों की, जिनके सम्बन्ध में निर्माण पूरा हो गया है, उक्त अधिनियम की धारा 80 की उपधारा (6) के नाथ पठित धारा 79 के अधीन गठित भाखड़ा क्यास प्रबन्ध बोर्ड की 1 मार्च, 1984 से आन्तरित करती है, अर्थात:—

यनिट-1

- (क) अनुसरन संकर्म सहित जस प्रणाली सुरंगपी-3
- (ख) स्टेप-अप ब्यवस्थाओं के साथ देहर विद्युत संयंत्र में प्रतिष्ठापित पांचवां और छठा 165 मेगाबाट हाइड्रो-जेनरेटर नथा सिविल सर्कम और सहबद्ध उपरकर, सहायक उपस्तर, लिक लाइनें और 400/22/132 के० बी० स्विच यार्ड ।
- (ग) क्याम सतलुज लिक परियोजना के सभी-शेष अनुस्तन संकर्म जिसमें गड़ के और अन्य सेवा सुविधाएं सम्मिलित है।
- (घ) सभी भूकम्प-लेखों केन्द्र, निस्मारण स्थल, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान संबंधी प्रयोगशालाएं तथा बैतार केन्द्र ।
- (ङ) पंडोह, बग्गी, गुस्दरनगर और सलापड़ में परियोजना काली-निया जिसमें कालोनियों से संबंधित सभी क्मारतें भीर सेवा मुजिधाएं सम्मिलित हैं।
- (भ) जग्गर और कांगों में हैलीपैड।

यूनिट-2

- (क) अनुलग्न संकर्म सहित जल प्रणाली सूरंग पी-3
- (ख) स्टेप अप व्यवस्थाओं के साथ तलवाड़ा में पांग विद्युत संगंक में प्रतिष्ठापित पांचवा और छठा 60 मेगावाट हाइड्रो-जेनरटर तथा सिविल संकर्म और सहबद्ध उपस्कर, सहायक उपस्कर, लिंक लाइनें और 220 के० वी० स्विचयार्ड विस्तार-के।
- (ग) 220 कं० बी० पोंग जलन्धर लाइन 4 सर्किट।
- (घ) ज्यास बांध के शेष सभी अनुलग्न संवामं जिसमें सङ्कों तथाअन्य सेवा मुनिधाएं सिम्मिलित हैं।
- (ङ) सलवाड़ा और संसारपुर में परियोजना कालोनियां जिसमें कालोनियों से संबंधित सभी इमारतें और सेवा सुविधाएँ सम्मिलित है।

सामान्य

यूनिट-1 और यूनिट-2 के अन्तर्गत व्यास परियोजना के भागक्ष्य ऐसे सभी अन्य संपूरित संघटक जिनका ऊपर विनिर्विष्ट रूप मे वर्णन नहीं किया गया है।

> [मं० 21/14/76 जिल्द अंडी(की ए.ण्ड वी)] मन्ना गोपालन, मंयुक्त सचिव

(Department of Power)

New Delhi, the 1st March, 1984

S.O. 847.—In pursuance of sub-section (5) of section 80 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby transfers, with effect from 1st March, 1984, the following components of the Beas Project—Unit I and Unit II in relation to which the construction has been completed, to the Bhakra Beas Management Board constituted under section 79, read with sub-section (6) of section 80 of the said Act, namely:—

Unit---I

- (a) Penstock tunnel P-3 alongwith appurtenant works.
- (b) Fifth and Sixth 165 MW Hydro-generators installed at Dehar Power Plant with step up arrangements alongwith civil works and allied equipment, auxiliary equipment, link Lines and 400/220/132 KV Switch Yards.
- (c) All remaining appurtenant works of B.S.L. Project including roads and other service facilities.
- (d) All Seismograph Stations discharge sites meteorological, hydrological laboratories alongwith wireless stations.
- (c) Project Colonies at Pandoh, Baggi, Sundernagar and Slapper including all buildings and service facilities relating to colonies.
- (f) Helipads at Jagger and Kango.

Unit-II

- (a) Penstock tunnel P-3 alongwith appurtenant works.
- (b) Fifth and Sixth 60 MW Hydrogenerators installed at Pong Power Plant at Talwara with step up arrangements alongwith Civil works and allied equipment, auxiliary equipment, link lines and 220 KV switch yards extension bays.
- (c) 220 KV Pong Jullundur line IV Circuit.
- (d) All remaining appurtenant works of Beas Damincluding roads and others service facilities.
- (c) Project colonies at Talwara and Sansarpur including all buildings and service facilities relating to the colonies.

General

All other completed components forming a part of the Beas Project under Units I and II not specifically stated above.

[21/14/76-Vol. III/D(B&B)] SARALA GOPALAN, Jt. Secy.

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (नागरिक पूर्ति विभाग) नई दिल्ली, 17 मार्च, 1984

का॰ आ॰ 848. केन्द्रीय संस्कार, अग्निम संविद्या (विनिक्षमम) अधिनियम 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के ग्राह्मान सेन्ट्रल इंडिया कर्माणयल एक्सचेंज लि०, खालियर द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए किये गय आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा वरना व्याप्तार के हिन में और लोकहित में भी होगा, एतद्द्वारा उकत अधिनियम की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए उकत एक्सचेंज को गुड़ की अग्रिम संविदाओं के वारे में 18 मार्च, 1984 से 17 मार्च, 1987 तक (जिसमें ये दोनों दिन शामिल हैं) की तीन वर्ष की अनिरिक्त काला-विध के लिए मान्यता प्रदान करती है।

2. एतद्द्वारा प्रदक्त मान्यता इस णर्त के अध्याधीत है कि उक्त एक्सचेंज ऐसे निदेणों का अनुपालन करेगा जो बायदा बाजार जायोग द्वारा समय-समय पर दिये जाएं।

> [मिसिल मं० 12(1)-आई०टी०/84] के० एस० बाजवा, उप सचिव

MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

New Delhi, the 17th March, 1984

S.O. 848.—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition, made under section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by the Central India Commercial Exchange Ltd., Gwalior, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 6 of the said Act, recognition to the said Exchange for a further period of three years from 18th March, 1984 to 17th March, 1987 (both days inclusive) in respect of forward contracts in gur.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Exchange shall comply with such directions as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12(1)-IT/84]

K. S. BAIWA, Dy. Secy.

पर्यटन और नागर विमानन मंद्रालय

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1984

का० भा०. 849:—सरकारी स्थान (ग्रप्राधिकृत भिष्ठभोगियों की वेदखली) भिष्ठित्तम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदक्ष गिक्तयों का प्रयोग करते हुए भीर पर्यटन खाथा नागर विमानन मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा जारी भिष्ठिसूचना सं० एस० भो० 3126 दिनांक 30 सितम्बर, 1981 के श्रांशिक झालोधन में, केन्द्रीय सरकार एतत्ह्वारा नीचे दी गई सारणी के कालम (1) में उल्लिखन भिष्ठकारी को सरकार के राजपित अधिकारी के रैंक के अराबर का भिष्ठकारी नियुक्त करती है जो उक्त यिधनियम के भयोजपार्थ संपदा भिष्ठकारी होंगे जो कि उक्त रारणी के कालम (2) में तत्स्थानी प्रविद्धि में विनिर्विष्ट सरकारी स्थानों के बारे में भपने कार्यक्षेत्र की स्थानीय मीमाओं के अंतर्गत रहते हुए प्रवत्त गिक्तयों का प्रयोग करेंगे भीर उक्त प्रधिनियम द्वारा भथवा उसके अंतर्गत संपत्ता अधिकारी के लिए प्रधिरोपन करेंगों का निष्पादन करेंगे।

	मारणी
र्प्राधकारी का नाम	सरकारी स्थान की श्रेणी स्रोर कार्यक्षेत्र की स्थानीय सीमाए
1	2
महा प्रबंधक (संपदा)	भारत पर्यटन विकास निगम लिमि-
होटल प्रभाग,	टेड ने श्र थवा उनके द्वारा पट्टे
भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	पर लिए गए सभी परिसर जो
जीवन विहार, 3 संसद भार्ग,	विल्ली ग्रौर चण्डीगढ़ के संघ
नई दिल्ली-110001	शासित क्षेत्रों श्रीर जम्मृ तथा
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	कण्मीर, हरियाणा, पंजाब
	हिमाचल प्रदेश, उन्तर प्रदेश,
	मध्य प्रदेश ग्रीर राजस्थान के
	राज्यों में प्रवस्थित हो ।

[बि॰ यु॰ 11015/6/78-पं एसयू (टी)] णाबी लाल चंध्यदानिदेशक

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION New Delhi, the 20th February 1984

S.O. 849.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) and in partial modification of the notification No. S.O. 3126 dated 30th September, 1981, issued by the Government of India in the Ministry of Tourism and Civil Aviation, the Central Government hereby appoint the officer mentioned in column (1) of the Table below, being an officer equivalent to the rank of gazetted officer of the Government to be Estate Officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on Estate Officer by or under the said Act, within the Iceal limits of the jurisdiction in respect of Public Premises specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

Designation of the Officer	Categories of Public Premises and local limits of the juris- diction
(1)	(2)
General Manager (Estates), Hotels Division, India Tourism Development Corporation Limited, Jeevan Vihar, 3-Parliament Street, New Delhi-110001.	All premises belonging to or taken on lease by India Tourism Development Corporation Limited and situated in the Union Territories of Delhi and Chandigarh and the States of Jammu and Kashmir, Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Rajasthan.

[No U-11015/6/78-PSU(T) S. L. CHOPRA, Director

स्चना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 फरबरी, 1984

का॰ भा॰ 850. -- चलचित्र ग्रधिनियम, 1952 की धारा 5(1) भीर चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 के नियम 8 के उप-नियम (1) भीर (2) के साथ पठित नियम 7 के उप नियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करने हुए,केन्द्रीयसरकार एसदृद्वारा निस्तनिश्चित

व्यक्तियों को प्रगले भादेण तक, फिल्म प्रमाणन बोर्ड से परामर्भ करने के बाद, उक्त बोर्ड के क्रिवेन्द्रम मलाह कार पैनल का सबस्य नियुक्त करती

- श्री राजकृष्णन्
- 2. डा० एन० ए० करीम
- श्री पी० के० बालकृष्णन
- 4. श्री **ज**म्पनम **पै**को
- डा० जार्ज ग्रोनावकूर सुक्रान
- श्री पेरूमचदायन श्रीध रण
- श्री विजयकृष्णन
- श्री कल्लीक्काड् रामचन्द्रन
- 9. प्रो० के० बी० हरीबासन
- 10. श्रीमती राजेश्वरी मेनन
- श्री दी० राजन पंडवल
- 12 डा०एम जी० पिली
- 13. श्रीमती मुगथा कुमारी

[फाइल मंख्या 811/4/83-एफ(सी)] कें। एसः वेंकटरामन, ग्रवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING New Delhi, the 27th February, 1984

S.O. 850.—In exercise of the powers conferred by section 5 (1) of the Cinematograph Act, 1952 and sub-rule (3) of rule 7 read with sub-rules (1) and (2) of rule 8 of the Cinematograph (Certification) Rules 1983, the Central Government hereby appoints the following persons after consultation with the Board of Film Certification, as members of the Advisory Panel of the said Board at Tribandrum with immediate effect until further orders:-

- 1. Shri Rajakrishnan
- Dr. N. A. Karim
 Shri P. K. Balakrishnan 4. Shri Chemmanam Chacko
- 5. Dr. George Onakkoor Sudarsana
- 6. Shri Perumbadayan Sreedharan
- Shri Vijayakrishan
- Shri Kallikkadu Ramachandran
- Prof. K. V. Haridasan 10. Smt. Rājeswari Menon
- 11. Shri T. Rajan Poduval 12. Dr. M. G. Pllai
- 13. Smt. Sugatha Kumari

[File No. 811/4/83-F(C)]

K. S. VFNKATARAMAN, Under Secy.

क्षम तथा पुनर्वास संत्रालय

((श्रम विभाग)

आदेश

नई दिल्लों, 6 फरवरी, 1984

का०आ० 851.--केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद अनुसूची में विनिर्विष्ट विषय के बारे में संयुक्त प्रबन्धक (प तन प्रचालन), भारतीय खाद्य निगम, मद्रास से सहबद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान हैं,

और केन्द्रीय सरकार जनम विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है,

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनिसम, (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त समितयो का प्रयोग करते हुए, एक औद्योंगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी थी टी० अरु सराज होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त वियाद को उक्त अधिकरण का न्यायमिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या संयुक्त प्रबन्धक (पत्तन प्रचालन), भारतीय **खाद्य** निगम, चेन्नाई हाउम, मद्रास-600001, हमिलनाडु की नीचे दी गई सूची के अनुसार 64 यैक्युटर कर्मकारों को 25-11-1981 से सामान्य एवं नियमित रोजगार देने से इन्कार करने की कार्यवाही मैच, उचित और न्यायपूर्ण है? यदि नहीं, सो संबंधित कर्मकार किस अनुसोष के हकदार हैं?"

कमंकारों की सूची

- 1. अरतोर रोस्मित
- 2. एस० श्री निवासन
- 3. एम०टी० उम्मेर
- 4. ए०के० रविम्द्रन
- 5. आर्थः कानन
- अतरवाम्मव रघनाथन
- 7. सी०के० चाको
- एम०सी० जोसेफ
- सी०एस० मैध्या
- 10. आर॰ मुद्रामानी
- 11. के बी अस्तिमान
- 12. ए० इष्टयाम
- 13. कें ० णित्रनन्दन
- 14. टी० गणपति
- एच० निनासामी
- 16. एन० रिधनाम
- 17. एस० न्रहीन
- 18. एम० मणिकमा
- 19. के० घेलुधन नायर
- 20. आर्० मृख्यान
- 21. कें अक्षाप्पन
- 22. के० श्रीधरण पिलाई
- 23. ओं जन्मतावाम
- 24. जे० चेलेयाह
- 25. के०जे० गंनारधनन पिलाई
- 26. के उसोभनि
- 27. पी० इवगार
- 28. कें ब्लो॰ कम्बानाथन
- 29. मुथु इरकप्पन
- 30. के संथान्म
- 31. के॰ रामाधन्त्रन
- 32. पी॰ मलाई चामी
- 33. के॰जे॰ साइरिल
- 34. पी० रवि
- **35. के**० शंकर
- 36. ए० करण
- 37. ए० मणि
- 38. एम० राधाकृष्णन
- 39. बी० गोपालकृष्णन
- 40. सी० कुमार
- 41. एम० सैयव मोहम्भद
- 42. के० एन० गोपालकृष्णन
- 43. एन० इजुमलाई
- 44. पी० धनाकोडी
- 45. एन० बालारमन
- 46. के० मनारधनन पिलाई
- 47. पी० इंगुमलाई
- 48. जी० गेगेनदरन

- 49. एम० सुन्दरम
- 50. एस**ः जन**भाणी
- 51. रामचन्द्रन
- 52. ए०टी जमकाशन
- 53. आर**० सुन्दर**म
- 54. के**० अमुलदा**स
- 55. आर**०** मुरूगन
- 56. एन० नागाप्पन
- 57. के० एम० बशीर
- 58. पी**०एम० अहमद**
- 59. एस० देवन
- पी० शतमुखम
- 61. पी० बलान
- 62. थी० गणेशन
- 63. एन० थिकमलाई
- 64. जीव्टीव मुनुस्यामी

MINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION (Department of Labour)

ORDER

New Delhi, the 6th February, 1984

S.O. 851.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Joint Manager (Port Operations), Food Corpn. of India, Madras and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T. Arulraj shall be the Presiding Officer, with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether refusal by the Joint Manager (Port Operations), Food Corporation of India, Chennal House, Madras-600 001 Tamil Nadu to provide normal and regular jobs to sixty four vacuator workers. Listed below w.e.f. 25-11-1981, is legal, proper and justified? If not, to what relief are the workmen concerned entitled?"

LIST OF WORKERS

- 1. Aurtor Rossitte

- Aurtor Rossitte
 S. Srinivasan
 S. T. Ummer
 A. K. Ravindran
 R. Kannan
 R.M. Raghunathan
 C. K. Chacko
 M.C. Joseph
 C. S. Mathew

- 9. C. S. Mathew
- 10. R. Subramani
- 11, K.B. Sulaiman
- 12. A. Irudayam 13. K. Sivanandan
- 14. T. Genapathy 15. N. Chinnasami 16. N. Rathinam 17. S. Noorudeen

- M. Manichma
 K. Velayudhan Nair
- 20. R. Murugayyan
- Pillai
- 21. K. Adappan22. K. Sreedharan23. O. Brahmadas
- 24. J. Chellaiah
- 25. K. J. Genardhanan Pillal 26. K. Soman
- 27. P. Edgar

- 28. K.O. Chandanathan
- Muthu Iruoppan
- 30. K. Santhanam
- 31. K. Ramachandran 32. P. Malai Chamy
- 33. K. J. Cyril 34. P. Ravi 35. K. Sankar

- 36. A. Karnan 37. A. Mani
- 38. M. Radhakrishnan
- V. Gopalakrishnan
 C. Kumar
- 41. M. Saidu Mohamed
- 42. K.N. Gopalakrishnan
- 43. N. Ezhumalai
- 44. P. Dhanakodi
- 45. N. Balaraman 46. K. Genardhanan Pillal
- 47. P. Ezhumalai
- 48. G. Gegendran 49. M. Sundarm
- 50. S. Chakrapani
- 51. Ramachandran
- A. T. Prakasam
 R Sundaram

- K. Amul Das
 R. Murugan
- N. Nagappan
 K.M. Basheer
- 58. P. M. Ahamed 59. S. Deva
- 60. P. Shanmugham
- 61. P. Balan
- 62. V. Genasan
- 63. N. Thirumalai 64. G. T. Munusamy

[No. L-42011 (22)/82-D. II (B)/D. IV (B)]

New Delhi, the 28th February, 1984

S.O. 852.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act. 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of J. K. Ropeways of Messry Eastern Coalfields Limited, and their workmen, which was received by the Central Government on the 24th February, 1984.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CALCUTTA

Reference No. 60 of 1983

PARTIES:

Employers in relation to the management of J. K. Ropeways of Eastern Coalfields Ltd.,

AND

Their Workmen.

PRESENT:

Mr. Justice M. P. Singh, -- Presiding Officer.

APPEARANCES:

On behalf of Employers .--- Mr. G. N. Singh, Deputy Personnel Manager,

On behalf of Workmen .--- Absent.

STATE: West Bengal.

INDUSTRY : Coal.

AWARD

By Order No. L-19011(5)|83-D.IV(B) dated 6|20-12-1983, the Government of India, Ministry of Labour and Rehabilitation, Department of Labour, referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:

"Whether the action of the management of J. K. Ropeways of Eastern Coalfields Ltd., Post Office Kajoragram, District Budrwan (WB) in not upgrading the 14 heavy vehicle drivers listed below and placing

them in Cat. VI or its equivalent grade i.e. Tech. C as per NCWA-II w.e.f. 11-12-82, or as the case may be, from 20-12-1982, is justified? If not, to what relief they are entitled?"

LIST OF THE DRIVERS

Sl. No. Name

Sh.

- 1. Sankar Singh
- 2. Shyamlal Singh
- Jagadish Thakur
- Rampujau Shaw Bijoy Bouri
- Beldeo Mahato Bhola Mandal
- 8. Ashoka Mukherice
- 9. Kanai Gope
- 10 Kartick Farfaria 11. Kalipada Bouri
- 12. Jangla Majhi
- 13. Jagadish Singh
- 14. Hari Ram.
- 2. The memorandum of settlement was filed by the parties concerned before this Tribunal on 9-2-1984. The settlement is put up-to-day before me for recording the same. Both sides pray that an award be passed in terms of the settlement as embodied in the compromise petition dated 8-2-1984. I have perused the terms of settlement. The settlement is fair and proper. I accept it and pass award in terms thereof. The compromise petition is made a part of this award. The reference is thus disposed of in terms of the settlement dated 8-2-1984. The compromise petition shall form part of this award and marked as annexure "A".

This is my award,

Dated, Calcutta,

The 14th February, 1984,

M. P. SINGH, Presiding Officer,

[No. L-19011(5)/83-D. IV(B)]

ANNEXURE 'A'

BEFORE THE HON'BLE PRESIDING OFFICER, CEN-TRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL, CALCUTTA Reference No. 60 of 1983

PARTIES:

Employers in relation to the Management of J. K. Ropeways of Eastern Coalfields Ltd.

AND

Their workmen.

The employers beg to state that :--

- 1. The dispute has already been mutually settled and the eligible persons have been promoted in due Categories/ Grade.
- 2. In this regard already a Bipartite settlement with the C.M.S.I. (CITU) Union who had raised the dispute, has been made on 6-5-1983 and the memorandum of settlement under I.D. (Central) Rules 1956 has been forwarded to Asstt. Labour Commissioner (C), Ranigani, Regional Labour Commissioner (C), Asansol, Chief Labour Commissioner (C), New Delhi, and Chief Secretary Govi. of India, New Delhi, Ministry of Labour for registration of such settlement.

In the above circumstances we pray that there is no dispute at present and award may kindly be given accordingly.

Sd/-For & on behalf of

the workmen.

(T. DEV, Asstt. Secy, CMSI (CITU))

Sd/-

For & on behalf of Employer.

G. N. SINGH, Dy. P. M. Office of G.M. (S&K) J. K. ROPEWAYS

New Delhi, the 29th Febtuary, 1984

S.O. 853.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Catcutta in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Chinakuri Colliery of M/s. Eastern Coalfields Ltd., and their workmen, which was received by the Central Government on the 24th February, 1984.

CENTRAL GOVFRNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CALCUTTA

Reference No. 52 of 1982

PARTIES:

Emloyers in relation to the management of Chinakuri Colliery of M/s. E.C.L.

AND

Their Workmen.

PRFSENT:

Mr. Justice M. P. Singh .- Presiding Officer.

APPEARANCES:

On behalf of Employers,...Mr. B. N. Lala, Advocate.

On behalf of Workmen.-Absent.

STATE: West Bengal.

INDUSTRY : Coal.

AWARD

By Order No. L-19012(61)/82-D. IV(8) dated 22 July, 1982, the Government of India, Ministry of Labour, referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:

"Whether the action of the Agent, Chinakuri Colliery, Messrs Eastern Coalfields Limited, Post Office Sunderchak District Burdwan in not regularising S/Shri Kamal Singh and 19 others (as per list) and not fixing proper wages with annual increment with arrears arising out of it as time-rated workmen since November 78 is justified? If not, to what relief the workmen are entitled?

LIST OF WORKMEN

я	Category	Designation
1. Kamal Singh	Pi co-rate	Driller
2. Darson Maha'a	-do	Tyndal
Gokul Bourri	-do-	Tram mer
4. Rama too Pa พาก	-10+ -	Driller
 Haru Shaw 	-10-	-do-
6. Den Nandan Prasa	l - l>-	Pump Khalasi
Ramdhani Nunis	-(1-4	Dresser
8.: Baleswar, Gope	-1>-	Tyndal-cum Dfiller!
Lakhan Paswan	-d >-	Tyndal
10. Sukhdeo Bhuiya	-dn- ·	Explasive carrier
11. Birv Tudu	-d./-	Driller-cum- Dresser
12. Sukhu Hembram	-d:-	-de-
13. Manjula Mucma	-45-	Explosive carrier
14. Joylal Nunia	-ci· -	Tyndal
15. Sitaram Paswan	de-	Trammer
Dwarika Jaday	-do+	Driller -
17. Baburem Bhuiya	-d :-	Driller-eum. Dresser
18. Madan Bhari	-do-	-do-
19. Idlu Bəuri	-do-	Explosive carrier
20. Nanka Das	-dc-	-do-

2. When the case is taken up for hearing, Mr. B. N. Lala, the learned advocate appearing for the management submits that the union seems to be no longer interested in the case since the issue referred to this Tribunal for adjudication has already been settled by the management with another union. It appears that the union has not yet filed its written statement nor has taken any step for filing the same.

3. In view of above, a "no dispute award" is passed in the case.

This is my award. Dated. Calcutta. The 14th February, 1984.

M. P. SINGH, Presiding Officer [No. L-19012/61/82-D. IV(B)] C. D. BHARDWAI, Desk Officer

New Delhi, the 29th February, 1984

S.O. 854.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Life Insurance Corporation of India, Calcutta and their workmen, which was received by the Central Government on the 23rd February, 1984.

CENTRAL GOVERNMEN'I INDUSTRIAL TRIBUNAL. CALCUTTA

Reference No. 18 of 1982

PARTIES:

Employers in relation to the management of Life Insurance Corporation of India:

AND

Their Workmen.

PRESENT:

Mr. Justice M. P. Singh, Presiding Officer.

APPEARANCES:

On behalf of Employers—Mr. S. Sarkar, Advocate, with Mr. H. C. Paul, Asstt. Secretary (Law), and Mr. P. K. Sen Gupta, an officer of the L.I.C.

On behalf of Workmen—Mr. Sukumar Mukherjee, with Mr. Nepal Ghosh, Joint Secretary of the Union.

STATE; West Bengal.

INDUSTRY: Insurance.

AWARD

By Order No. L-17012/18/81-D.IV(A), dated 20th May, 1982, the Government of India, Ministry of Labour, referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:

"Whether the actions of the management of Life Insurance Corporation of India, Divisional Office; Calcutta in (i) imposing the punishment of censure, (ii) recovering the alleged, loss: of Rs. 1800. (iii) transferring from Cash Department to Accounts Department with effect from 20-5-77 and (iv) deferring the stagnation increment for one year with effect from 5-6-79 in relation to Shri Niranian Biswas. Cashier are justified? If not, to what relief(s) is the workman concerned entitled?".

2. The memorandum of settlement was filed by the parties before this Tribunal on 9-2-1984. The settlement is put uptoday before me for recording the same. Both sides pray that an award be passed in terms of the settlement as embodied in the compromise petition dated 8-2-1984. I have perused the terms of settlement. The settlement is fair and proper. I accept it and pass award in terms of the settlement dated 8-2-1984. The compromise petition shall form part of this award and marked as annexure "A"

This is my Award.

Dated, Calcutta,

The 14th February, 1984.

M. P. SINGH, Presiding Officer
 INO. I-17012/18/81-D.TV(AN
 S. S. PRASHFR, Desk Officer

ANNEXURE 'A'

BEFORE THE LEARNED CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, WEST BENGAL

In the matter of:

Reference No. 18 of 1982

AND .

In the matter of:

Sri Niranjan Biswas.

Versus

The Life Insurance Corporation of India.

The humble joint petition of the parties abovenamed. Most Respectfully Sheweth:--

- 1. That this Honble Tribunal was pleased to observe as to whether the pending dispute could be settled by the parties amicably out of the Court.
- 2. Thereafter the parties have matually arrived at a Memoradum of Settlement out of the courts to their satisfactions. The original copy of the Settlement is filed herewith.
 - It is therefore, prayed that this Hon'ble Tribunal may be graciously pleased to be pass an Award in terms of the Memorandum of Settlement and pass any other order or orders deem fit and proper.

For this act of kindness your petitioners shall ever pray.

MEMORANDUM OF SETTLEMENT

parties to the Settlement:

(1) Life Insurance Corporation of India of 16, Chittaranjan Avenue, Calcutta-700072.

Represented by:---

1. Mr. H. C. Paul, Asstt.Secretary (Law)

(2) Life Insurance Corporation Employees Association (Calcutta Division), Andhra Insurance Buildings, 12, Chowringhee Square, Calcutta-700069.

Represented by: (1) Sri Nepal Ghosh, It Secy.

2. Sri Niranjan Biswas

Short Recital: That during the pendency of the reference No. 19 of 1982 berfore this Learned Tribunal and after the departmental enquiry finding Sri Niranjan Biswas quilty of the charges levelled against him by a charge sheet dated 23-5-1977 was held by the Tribunal as vitiated and void by an order dt. 3-6-1983, the Learned Tribunal was pleased to observe that whether any mutual settlement is possible between the parties particularly keeping in veiw that the concerned employee will be retired from 1st March. 1984. Thereafter, following bipartie discussion and approval of the Central Office at Bombay the dispute is amicably settled on the following terms and conditions.

TERMS OF SETTLEMENT

- 1. The concerned employee Sri Niranjan Biswas will be paid a consolidated sum of Rs. 5,000 in full and final settlement of the claim of disputes arising out of the reference No. 18 of 1982.
- 2. The aforesaid sum of Rs. 5,000 will be paid on or before the date of retirement by the Management and following such payment the pending dispute shall be deemed as resolved and that Sri Niranjan Biswas or the Union shall not make any further claim or demands following such payment as above. The Management also agrees that the charges which were brought against Sri Niranjan Biswas resulting in the aforesaid reference shall be deemed as withdrawn.
- 3. An award shall be made in answer to the issue on the terms as aforesaid.

The parties put their signature on this 8th Day of February, 1984.

Lie Insurance Corporation of India By HARISH CHANDRA PANT, Constituted Attorney Signature for the 1st Party Life Insurance Corporation of India.

> NEPAL GHOSH, Jt. Secy. Signature for the 2nd Party Sri Niranjan Biswas.

WITNESSES:

- 1. Prakash Kumar Sengupta,
- 2. Sukumar Mukherjea.

1515 GI/83-5

मई फिल्ली, 27 फरवरी, 1984

का०आ० 355.—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाते पर कि लोकहित में ऐसा करना अवेक्षित था औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के द्वाण्ड (ह) के उपल्पण्ड (IV) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के अस मंत्रालय की अधिसूचना मंद्रया का०आ० 3833 नारीख 19 सितम्बर, 1983 दारा जिक खनत उद्योग को उद्या अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 19 नितम्बर, 1983 से छः माम की कालावधि के सिए सीक उपयोगी सेवा धोषिन किया था।

भौर केन्द्रीय सरकार की रांग है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छ: मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है,

अनः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदस्त मिलत्यों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार उनत अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 19 मार्च,1984 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उन्योगी सेवा धोषित करनी है।

[सं॰ एस-11017/4/81-ही-(1ए)(i)]

New Delhi, the 27th February, 1984

S.O. 855.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so requires had, in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 3833 dated the 19th September, 1983; the Zinc Mining Industry to be a public utility service for a period of six months, from the 19th September, 1983;

And, whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purpose of the said Act, for a further period of six months from the 19th March, 1984.

[No. S-11017/4/81-81-D.I(A)(i)]

कां अं। 876. किनीय सरकार ने यह ममाधान हो जाने पर कि लोकहिश में ऐसा करना अवेशित था औदीिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ह) के उपखण्ड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में भारत परकार के अम मंत्रानत की अधितूचना संख्या कां अंश 3834 तारीख 19-गिनस्बर, 1983 द्वारा सीसा खनन उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 24 सिनस्बर, 1983 से छा मास की कालावधि के लिए लोक उन्योगी सेवा घोषित किया था।

और केन्द्रीय सनकार की राय है कि लोकहिन में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बंट्राया जाना अपेक्षित है,

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की द्वारा 2 के खण्ड () की उम्बण्ड (vi) की परलुक द्वारा प्रदरत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधि-नियन के प्रयोजनों के लिए, 24 मार्च, 1984 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी भेगा घीषित करती है।

> [मंख्या एत-11017/4/81-दी-1(ए)(ii)] एस०एच०एस० अध्यद, अवर सचिव

S.O. 856.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so requires had, in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S. O. No. 3834 dated the 19th September, 1983, the

Lead Mining Industry to be a public utility service for a period of six months, from the 24th September, 1983.

And, whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purpose of the said Act, for a further period of six months from the 24th March, 1984.

[No. S-11017/4/81-D. I (A) (ii)] S. H. S. IYER, Under Secv.

नई दिल्ली, 9 विसम्बर, 1983

भादेश

का० मा० 857.—केन्द्रीय भरकार की यह राम है कि इसमें उपाबद्ध मनुसूची में विनिद्धित्व विषय के बारे में महाप्रबन्धक, परिचम रेस, बम्बई से सम्बद्ध एक ब्रौधोगिक विवाद नियीजकों भीर उनके कर्मकारों के बीध विद्यमान है,

ग्रौर केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयम के लिए निर्वेशित करना बांछनीय समझती हैं;

मतः केन्द्रीय सरकार, ध्रीधीरियक विवाद घष्टिनियम, 1947 (1947 का 14) की बारा 7-क घीर धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (ध) द्वारा प्रवत्त मन्त्रियों का प्रयोग करते हुए, एक ध्रीद्योगिक चित्रकरण गठित करती है जिसके पीठासीन प्रधिकारी भ्री जी० एस० वरोत होंगे, जिनका मुख्यालय भ्रहमवाबाद में होगा भ्रीर उक्त विवाद को उक्त ध्रिक्र करण को स्थानिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

भ्रम् सूची

"क्या बम्बई स्थित पश्चिम रेल के सहा प्रबंधक द्वारा श्री जिलेन्द्र सिंह सेटी, जानीटर, पश्चिम रेल, होलीडे होम, माउन्ट श्राबू, की सेवाएं कोई सूचना या प्रतिकर विए बगैर 18-9-81 से समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोध का हकदार है?"

[सं॰ एल-41011/37/82-जी-2(मी)]

New Delhi, the 9th December, 1983.

ORDER

S.O. 857.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the General Manager, Western Railway, Bombay and their workmen in respect of the matter specified in the schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, ir exerise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri G. S. Barot shall be the Presiding Officer with headquarters at Ahmedabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of General Manager, Western Railway, Bombay in terminating the services of Shri litendra Singh Sethi, Janitor Western Railway Holiday Home, Mt. Abu with effect from 18-9-81 without any notice or compensation is justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

[No. L41011/37/82/D.II(B)]

- घादेण

का० प्रां 858.—केन्द्रीय सरकार की वह राय है कि इससे उपाबत प्रमुखी में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में खादी भीर प्रामीधोग प्रायोग, बस्वई के प्रबंधतंत्र से संबंधित एक भीबोगिक विवाद नियोजकों के कर्मकारों के बीच विद्यमान है,

ग्रौर केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्वेशित करना वास्त्रनीय समझती है,

मतः, केन्द्रीय सरकार, भौधोगिक विवाद धिवियम, 1947 (1947 का 14) की घारा 7-क भीर घारा 10 की उपघारा (i) के खंब (घ) द्वारा प्रदश्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक भौधोगिक धिवकरण गठिन करती है जिसके पीठासीन धिवकरण की महेन्द्र भूषण शर्मा होंगे, जिनका मुख्यालय जयपुर में होगा भौर उक्त विवाद को उक्त प्रधिकरण की त्यायनिर्णयन के लिए निर्वेणित करती है।

मनसुची

"क्या खादी ग्रामोधोग घायोग, बीकानेर द्वारा श्री कें एएनं कोशो, उच्च श्रेणी लिपिक को महायक निदेशक [साधारण प्रशासन, प्रशिक्षण एचं बीठ टीठ-यूठ एंसठ एठ) के पद के लिए चयन बोर्ड के समझ जून 1981 के दौरान साक्षात्कार का धवसर देने से इन्कार करने की कार्यवाही न्यायोचित है? यदि नहीं तो, श्री जोशी किंग ग्रमुतीय के हकदार है?

[एल • 42012/8/83-डी-2(बी)]

ORDER

S.O. 858.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Khadi and Village Industries Commission, Bombay and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri Mahendra Bhushan Sharma shall be the Presiding Officer, with headquarters at Jaipur and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of Khadi & Village Industries Commission, Bikaner in denying an oportunity of interview to Shri K. L. Joshi, U.D.C. for the post of Assistant Director (Gen. Admn/Training/HBT-USA) before the selection Board during June, 1981 is justified? If not, to what relief is Shri Joshi entitled?"

[No. I.-42012/8/83-D II(B)]

आवेश

का० आ० 859.—केस्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में मंडल इन्जीनियर और मंडल कार्मिक अधिकारी उत्तर रेल, बीकानेर के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध एक श्रीकोरिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान हैं;

भौर केन्द्रीय सरकार उदत विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना बांछनीय समझनी है;

भनः, केन्द्रीय सरकार श्रीशोगिक दिवाद भ्रधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क भौर भ्रारा 10 की उपधारा (i) के खंड (क) हारा प्रवस्त नकियों का प्रयोग करते हुए एक भौशोगिक म्रधिकरण

गठित करंती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री महेन्द्र भूष्ण शर्मा होंगे, जिनका मुख्यालय जयपुर में होगा भौर उक्त विवाद को उक्त श्रधिकरण को न्यायतिर्णयन के लिए निर्वेशिक्ष करती है।

अनुनुचं:

"स्या उस्तर रेल के प्रवधंक द्वारा ध्रपने मंडल इंजीनियर और मंडल कार्मिक मधिकारी, बीकानेर के सम्बन्ध में 32 कर्मकारों जिनका क्यौरा उपावंध में दिया गया है, श्रौद्योगिक विवाद प्रधिनियम, 1947 की धारा 25-च 25-छ धौर श्रौद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम, 1957 के नियम 77का उल्लंधन करते हुए सेवाएं समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोजित हैं? यदि नहीं, तो ये कर्मकार किस धन्तोष के हकदार हैं ?"

िम सं० कर्मकारकानाम 	मेवा समाप्त करने की तारी
 श्री देवेंद्र कुमार 	8-12-1961
2. श्री राघेश्याम	15-9-1981
3. श्री राय राम	25-1-1980
4. श्री मंगल राम	15-7-1980
 श्री सूरज राम 	19-7-1980
6. श्री भ्रासू राम	30-11-1979
7. श्री अनूप सिंह	27-7-1980
 श्री कुरद राम 	29-9-1981
 श्री सनवना 	29-9-1981
0 श्री कुरद राम	29-9-1981
1. श्री गोपाल क्रुप्ण	29-9-1981
2. श्री परमेश्वर	25-9-1981
 श्री शिशुपाल सिंह 	25-9-1981
4. श्री मवन लाल	1-1-1981
5. श्री पुराराम	29-9-1981
6. श्रीलक्षमन	12-6-1980
7. श्रीफतेहसिंह	29-9-1980
8. श्रीभागीरथ	1-8-1980
श्री रावतराम	29-9-1981
0. श्री एयाम राम	29-9-1981
1. श्री झानबार	29-9-1981
2. श्री चीथूराम	18-11-1980
3. श्री देवी सिंह	29-9-1981
4. श्री रामे ग् वर	4-2-1981
25. श्री मोहन सिंह्	29-9-1981
6. श्री राम कुमार	11-10-1981
7. श्री प्रेमा राम	22-12-1976
8.श्रीरूप राम	22-8-1977
 श्री हरि राम 	7-5-1974
0. श्री मोहम्मद भ्रमी	1-7-1981
1. श्री गौरी मंकर	15-9-1981
2. श्री मानकचंव	15-9-1981

[सं एल-41012/20/83-ही 2 (बी)]

ORDER

S.O. 859. -Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Divisional Engineer and Divisional Personnel Officer, Northern Railway, Bikaner and their workmen in respect of the matter specified in the schedule hereto annexed:

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri Mahendra Bhushan Sharma shall be the Presiding Officer, with headquarters at Jaipur and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

, SCHEDULE

"Whether the action of the management of Northern Railway in relation to their DEN & DPO, Bikaner in terminating the services of the 32 workmen whose details are given in the annexure in violation of sections 25F, 25G, of the I.D. Act, 1947 and Rule 77 of the I.D. (Central) Rules, 1957 is justified? If not, to what relief are these concerned workmen entitled?"

ANNEXURE

Sl. Name of the workman	Date of termination
No.	
1. Shri Davendra Kumar	8-12-1981
2. Shri Radheyshyam	15-9-1981
3. Shri Rauoram	25-1-1980
4. Shri Manglaram	15-7-1980
5. Shri Surjaram	19-7-1980
6. Shri Aasuram	30-11-1979
7. Shri Anupsingh	27-7-1980
8. Shri Kurdaram	29-9-1981
9. Shri Sanwata	29-9-1981
10. Shri Kurdaram	29-9-1981
11. Shri Gopal Krishna	29-9-1981
12. Shri Parmeshwar	25-9-1981
13. Shri Shishupal Singh	25-9-1981
14. Shri Madanlal	1-1-1981
15. Shri Puraram	29-9-1981
16. Shri Laxman	12-6-1980
17. Shri Fatehsingh	29-9-1981
18. Shri Bhagirath	1-8-1980
19. Shri Rawataram	29-9-1981
20. Shri Shyamram	29-9-1981
21. Shri Jhanbar	29-9-1981
22. Shri Chauthuram	18-11-1980
23. Shri Devisingh	29-9-1981
24. Shri Rameshwar	4-2-1981
25. Shri Mohansingh	29-9-1981
26. Shri Ram Kumar	11-10-1981
27. Shri Pema Ram	22-12-1976
28. Shri Rooparam	28-8-1977
29. Shri Hariram	7-5-1974
30. Shri Mohd. Ali	1-7-1981
31. Shri Gauri Shankar	15-9-1981
32. Shri Manakchand	15-9-1981

[No. L-41012/20/83-DH(B)]

नई विल्ली, 30 दिसम्बर, 1983

आदेश

का॰आ॰ 860.—केस्प्रीय सरकार की यह राय है कि इससे उपावद्व अनुसूची में विनिर्विष्ट विषय के बारे में महाप्रबन्धक, पश्चिमी रेल, बम्बई के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है; भीर केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्याय निर्मयन के लिए निर्देशित करना बोछनीय समझती हैं ;

भतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और घारा 10 की उप-धारा (1)के खण्ड (व) धारा प्रदेश्व पास्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठांसीन, अधिकारी श्री जीव्यम् बरोत होंगे, जिनका मुख्यालय अहमदबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्याय-निर्णयन के लिए निर्वेशित करती है।

अनुसूची

"क्या रेल प्रशासन की, सी ० एस० आई० अआभेर के अधीन हैल्पर श्री अनवर अली को मंडल रेल प्रबन्धक के पिश्वा रेल पत्र संख्या एम/एस आई जी-1130/6 पार्ट 10 तारीख 19-12-80 द्वारा परिकल्पित व्यवसाय परीक्षा में बैठने के लिए न बुलाने की कार्यवाही व्यायोचित है? यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुतोच का हकदार है"?

[संख्या एल-41012/7/83-क्षी II (की)]

ORDER

New Delhi, the 30th December, 1983

S.O. 860.—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of The General Manager, Western Railway, Bombay and their workmen in respect of the matter specified in the schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri G. S. Barot shall be the Presiding Officer, with headquarters at Ahmedabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the Railway Administration in not calling Shri Anwar Ali, Helper under CSI. Ajmer, to appear in Trade Test envisaged vide Divisional Railway Manager's W. Railway, Ajmer letter No. M/Sig-1130/6 Part X dated 19-12-80 is justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

[No. L-41012(7)/83-D.H(B)]

आवेश

का० आ० 8:61: - केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ईससे उपायस अनुसूची में विनिर्विष्ट विषय के बारे में पिक्सी रेलवे प्रशासन के प्रशन्सक से संबंधित एक भौद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वाळनीय समझती है;

अतः केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनिर्धम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और घारा 10 की उप-धारा (i) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त मक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकरणे श्री महेन्द्रभूषण सम्म होंगे जिनका मुख्यालय जयपुर में होगा और उक्त विवाद को उक्त स्थिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निदेशित करती है।

अमृसूची

क्या महल रेसचे प्रयन्धक, पश्चिमी रेलवे कीटा की, श्री जसवन्त सिंह, टी०टी०ई० कीटा की चेतन को न बढ़ाने तथा उसे उसके कनिष्ठों सर्वर्क्षः केव्एनव आचार्य, पीवपीव पांडे तथा सुभाष मेहरा, टीव्टीवर्षः के बेतन के समतुत्य न करने को कार्यकाही न्यायावित है? यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?

"क्या मंडल रेलवे प्रबन्धक, कोटा की, श्री एस०के० मेहरा टी०टी०ई० कोटा के बेतन की बड़ा कर उनके कनिष्टों के समतुल्य न करने तथा उसके बकाया का संदाय न करने की कार्यवाही न्यापोचित है? यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुताय का हकदार है?

[संस्या एल-41011(5)/83-शी-2(सी)]

ORDER

S.O. 861.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Western Railway Administration and their workmen in respect of the matter specified in the schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri Mahendra Bhushan Sharma shall be the Presiding Officer with headquarters at Jaipur and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the Divisional Railway Manager Western Railway, Kota in not stepping up the pay of Shri Jaswant Singh, TTE Kota and make it equuivalent to that of his juniors S/Shri K. N. Acharya, P. P. Pandey and Subash Mehra TTEs is justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

"Whether the action of Divisional Railway Manager, Kota for not stepping up the pay of Shri S. K. Mehra TTE Kota equivalent to that of his juniors and not paying the arrears thereof is justified? If not to what relief the workman is entitled?"

[No. L-41011(5)/83-D,II(B)]

आवेश

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 1984

का० आ० 862:— केन्द्रीय सरकार की राथ है कि इससे उपावड़ अनुसूची में विनिर्विष्ट विषय के बारे में पश्चिमी रेलवे, राजकोट के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान हैं.

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद की न्यायनिर्णयन के लिए निदेशित करना बांछनीय समझती है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की भारा 7-क और धारा 10 की उपयारा (i) के बंह (घ) द्वारा प्रदत्त शिन्तयों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री जीवण्यव रोत होंगे, जिनका मुख्यालय अहमदाबाद में होंगा और उनत विवाद को उनत अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्वेशित करती है।

अनुसूची

"क्या , आई० झो० इब्ल्यू (एम जी) साबरमती पश्चिमी रेलवे की खलासी, श्री ए० गोपाल की 21-12-82 में सेवाएं समाप्त करने की कार्यवाहीं न्यायोजित हैं? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार सि अनुतोष का हकदार हैं?"

[मं० एल-41011/50/83-इ)-2(बी)]

ORDER

New Delhi, the 8th February, 1984

S.O. 862.—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the empleyers

in relation to the management of Western Railway, Rajkot and their workmen in respect of the matter specified in the schedule hereto annexed:

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri G. S. Barot shall be the Presiding Officer, with headquarters at Ahmedabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of IOW (M.G.) Sabarmati Western Railway in terminating the service of Shri A. Gopal, Khalasi w.e.f. 21-12-82 is justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled?".

[No.L-41011(50)/ 83-D. H(B)]

आहेग

का० आ० ६६3:—केन्द्रीय मरकार की राय है कि इससे उपावक अनुसूची मे विनिद्धिट विषय के बारे में उत्तरी रेखवे प्रणासन, बीकानेर डिबीजन के प्रबंधवान से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारो के वीच विद्यामान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्वेशित करना बांछनीय समझती हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उप-धारा (i) के खंड़ (घ) धारा प्रदत्त गक्तियों का प्रयोग करने हुए एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है। जिसके पीठासीन अधिकारी श्री महेन्द्र भूषण गर्मा होंगे, जिनका मुख्यालय जयपुर में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसुची

"क्या उत्सरी रेलवे प्रबन्धतल को अपने बीकानेर डिवीजन, बीकानेर से संबंधित नैमित्तक मेसन, श्री जेथु सिह् पृत्र श्री सुरेन्द्र मिह् को 260-400/रु० कवेतमान में मेसन के स्थायी संबर्ग में नियुक्त न करने की कार्यवाही न्यायोधित हैं? यदि नहीं तो वह किस अनुतोष का हकदार हैं ? [सं० एल-41012/30/83 डी-2 (बी)]

ORDER

S.O. 863.—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Northern Railway Administration, Bikaner Division and their workmen in respect of the matter specified in the schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Endustrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri Mahendra Bhushan Sharma shall be the Presiding Officer, with headquarters at Jaipur and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of Northern Railway Management in relation to their Bikaner Division, Bikaner in not appointing She? Jethu Singh S/o Shri Sunder Singh, Casual Mason in permanent cadre of Mason in the pay scale of Rs. 260—400 is justified? If not to what relief is he entitled?"

[No. L-41012(30)/83-D.JI(B)]

आवेश

नई दिल्ली. 13 फरवरी, 1984

का० आ० 864'—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इसने उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में पश्चिमी रेखवे, बम्बई, के प्रवर्तन से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है ;

और केस्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्वेशित करना वाक्तनीय समझती है;

अतः बेन्द्रीय संस्कार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (i) के खंड (भ) द्वारा प्रदन्न गविनयों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गिंठत करनी है जिसके पीठासीन अधिकारश्री जीव एसव बरोन होगे जिनका मुख्यालय अहमदाबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को स्थायनिर्णयन के लिए निक्षित करती है।

अनुसूची

"भया ए० ई० एन० नंबरबार और डी० ई० एन०, बम्बई सैंट्रल से संबंधित पश्चिमी रेलवे के प्रबन्धवत की 9-11-75 से श्री तुलसीराम रामवास की सेवाएं समाप्त करने की कार्यवाही त्यायांचित है? यदि नहीं, तो यह कर्मकार किस अनुसोष का हकदार है ?"

jसं॰ एल॰ 41012 /37 /83 -डी- 2(बी)]

ORDER

New Delhi, the 13th February, 1984

S.O. 864.—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Western Railway, Bombay and their workmen in respect of the matters specified in the schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7 A and clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri G. S. Barot shall be the President Officer, with headquarters at Ahmedabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of Western Railway, management in relation to AEN, Nandarbar and DEN Bombay Central in dismissing Shri Tulsiram Ramdas from service w.e.f. 9-11-75 is justified ? If not, to what relief is the workman entitled ?"

[No. L-41012(37)/83-D.II. (B)]

मादेण

का॰ आ॰ 865: — केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपावश्च अनुसूची में विनिर्दिष्ट विश्वय के बारे में पश्चिमी रेलवे, प्रशासन के प्रवेध-तंत्र से सम्बद्ध एक ग्रीद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है;

ग्रौर केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्धेशित करना वास्त्रनीय समझसी हैं:

मतः केन्द्रीय सरकार, प्रौद्योगिक विवाद प्रधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क प्रौर धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक घौद्योगिक प्रधिकरण गठिल करते है जिसके पीठासीन प्रधिकारी श्री महेन्द्र भूषण शर्मा होंगे, जिनका मुख्यालय जयपुर में होंगा घौर उक्त विवाद को उक्त प्रधिकरण को न्यायनिर्णयम के लिए निर्देशित करती है।

भनुसूची

"न्या विभागीय रेलवे प्रवन्धक, पश्चिमी रेलवे कोटा से संवं-धित पश्चिमी रेलवे प्रवंधतंत्र की श्री मानक चंद को श्री राम किशन से पहले दरीयता देने की कार्यवाही न्यायोंचित है? यदि नहीं, तो श्री राम किशन किस धनुतीय का हकदार है?"

[सं॰ एल-41011/40/83-की-2 (बी)]

ORDER

S.O. 865.—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Western Railway. Administration and their workmen in respect of the matter specified in the schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7 A and clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri Mahendra Bhushan Sharma shall be the Presiding Officer, with headquarters at Jaipur and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the Western Railway Management in relation to the Divisional Railway Manager, Western Railway Kota in giving seniority to Shri Manak Chand over Shri Ram Kishan is justified? If not, to what relief Shri Ram Kishan is entitled?"

[No. L-41011(40)/83-D.II(B)]

पादेश

का॰ प्रा॰ 866.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध भनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में एयर इंडिया, मद्रास के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध एक भौधोगिक विवाद मियोजकों भीर उनके कर्मकारों के बीच विषयमान हैं;

भौर केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयम के लिए निर्दे-शित करना वांछनीय समझती हैं;

मतः, केन्द्रीय सरकार, भौबोगिक विवाद प्रधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क भीर धारा 10 की उप धारा (1) के खंड (ब) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक भौद्योगिक प्रधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन भधिकारी श्री टी प्रघलराज होंगे, जिनका मुख्यालय महास में होगा भौर उक्त विवाद को उक्त मधिकरण को न्यायनिर्णयक के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या मद्रास में एयर इंडिया प्रतिष्ठानों के स्पोर्ट कियोजन भीर इंजीनियरिंग विभाग में कार्यरत नैमित्तिक कर्मकारों द्वारा सेवा में 3 वर्ष पूरे करने पर स्थायी पद के लिए मांग करना व्यायोचिन है ? यिव हां, तो संबंधित कर्मकार किस मनुतोष के हकदार हैं ?"

[सं॰ एल-11011/3/82-की-2 (बी)]

ORDER

S.O. 866.—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Air India, Madras and their workmen in respect of the matter specified in the schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7 A and clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of

the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T. Arulraj shall be the Presiding Officer, with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the demand of the casual workmen working in the Support Division and the Engineering Department of the Air India establishments at Madras for permanent status on completion of 3 years of service is justified? If so, to what relief the workmen concerned are entitled?"

[No. L-11011(3)/82 D.JI (B)]

त्रादेश

कार्ण्यार 867.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध झनु-सूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में दूरदर्णन केन्द्र, गुलबर्गा के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध एक भौधोगिक विवाद नियोजकों भौर उनके कर्मकारों के बीच विश्वमान हैं;

श्रौर केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती हैं;

श्रतः, केन्द्रीय सरकार, ग्रौश्रोगिक विवाद ग्रिश्चित्यम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क ग्रौर धारा 10 की उपश्वारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त ग्राह्मितयों का प्रयोग करते हुए, एक ग्रौश्रोगिक ग्रिधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन प्रधिकारी श्री बी०एच० उपाध्याय होंगे, जिनका मुख्यालय बंगलीर मे होगा ग्रौर उक्त विवाद को उक्त ग्रश्चिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

धनुसूची

"क्या दूरवर्णन केन्द्र, गुलबर्गा की श्री मातरेप्पा को 15-10-82 से निरन्तर नियोजन देने से मना करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नही, तो यह कर्मकार किस धनुतीय का हकदार है ?"

[सं० एल-42012/15/83-शी-2 (बी)]

ORDER

S.O. 867.—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Doordarshan Kendra, Gulbarga and their workman in respect of the matter specified in the schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7 A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri V. H. Upadhaya shall be the Presiding Officer, with headquarters at Bangalore and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of Doordarshan Kendra, Gulbarga in denying continuous employment from 15-10-82 to Shri Shantreppa is justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

[No. L-42012 (15)/83-D. II (B)]

भावेश

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 1984

का॰ प्रा॰ 868.— केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपायक प्रतुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में कर्मचारी राज्य बीमा निगम, प्रहमदाबाद के प्रवंत्रतंत्र से सम्बद्ध एक बीधोगिक विवाद नियोजकों बौर उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है;

ग्रीर केन्द्रीय सरकार उपत विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्वेणित करना बांछनीय समझक्षी हैं;

म्रतः, केन्द्रांय सरकार, मौद्योगिक विवाद प्रधिनयम, 1947 (1947 का 14) को धारा 7-क भीर धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रवत्त शक्तियां का प्रयोग करते हुए, एक भौद्योगिक प्रधिकरण गठित करती है जिसके गीठामीन प्रधिकारी श्री जी०एम० बरोस होंगे, जिनका मुख्यालय प्रहमवाबाद में होंगा और उक्त विवाद को उक्त श्रीक करण को स्थायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

प्रनुसुची

"क्या क्षेत्रीय निर्देशक, ६०एस०आई०सी०, श्रह्मदाबाद की ई० एस०आई०सी० कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को स्थानान्तरण कराने, और पदीक्षति देने मे इंकार करने सथा युनियन के महामंत्री को आरोपपत्र देने की कार्यवाह्यी उनके ट्रेड यूनियन कार्य-कलापों के उत्पीड़न के समान है? यदि हां, तो कर्मकार किस अनुतोष के हकवार है?"

[सं॰ एल-15011/2/83-शी-2 (बी)]

New Delhi, the 18th February, 1984

ORDER

S.O. 868.—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of ESIC Ahmedabad and their workmen in respect of the matter specified in the schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government consideres it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri G. S. Barot shall be the Presiding Officer, with headquarters at Ahmedabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of Regional Director, ESIC, Ahmedabad in transferring the President, Vice President of ESIC staff Union and refusing promotion and chargesheeting the General Secretary of the union tantamounts to victimisation for their trade union activities? If so, to what relief the workmen are entitled?"

[No. L-15011(2)/83-D,IJ,B]

नई दिल्लो, 24 फरवरो, 1984

भादेश

का॰ धा॰ 863:—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इसमे उपाबद्ध ध्रनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में खावी भौर ग्राम उद्योग ग्राधोग, बम्बई, के प्रवन्धतंत्र से सम्बद्ध एक भौद्योगिक विवाद नियोजकों भौर उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान हैं;

श्रीर केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्वेणिस करना बांछनीय समझती है;

प्रतः कंन्द्रीय सरकार, श्रीयोगिक विवाद श्रिधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क भीर धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदक्ष णिक्तयों का प्रयोग करते हुए, एक भौदोगिक श्रिष्ठकरण गठित करती है जिसके पीठास न श्रिष्ठकारी श्री महेन्द्र भूषण धार्म होगे, जिनका मुख्यालय जयपुर में होगा और उक्त विवाद को उक्त श्रिष्ठकरण को न्याय-निर्णयन के लिए निर्वेशित करती है।

प्रतृसूची

"क्या खादी और प्राप्त उद्योग श्रायोग, अस्त्रई द्वारा कर्म-चारियों का 1-4-1976 से पहाड़ी घीर सीमा क्षेत्र भक्ता बन्द करना स्यायोजित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार है ?

"क्या खादी और ग्राम उद्योग भ्रायोग द्वारा पहाड़ी भीर मीमा-वर्ती क्षेत्र में कर्मचारियो की जूतों नथा चश्मों की सप्लाई में कभी करना न्यायोजित है? यदि नहीं, तो पहाड़ी तथा सीमावर्ती क्षेत्र के कर्मचारी किस भनतोष के हकवार हैं?"

[संख्या एल-42011/19/83-डी-2 (बी)]

New Delhi, the 24th February, 1984

ORDER

S.O. 869.—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Khadi and Village Industries Commission, Bombay and their workmen in respect of the matter specified in the schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Indusrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri Mahendra Bhushan Sharma shall be the Presiding Officer, with headquarters at Jaipur and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

"Whether the Khadi & Village Industries Commission, Bombay is justifled in discontinuing the Hill and Border Area Allowance to its employees with effect from 1-4-1976? If not, to what relief they are entitl-'ed?'

"Whether the Khadi & Village Industries Commission, Bombay is justified in curtailing the facility of supply of shoes and goggles to its employees in Hill and Border Areas? If not, to what relief the Hill and Border Area Employees are entitled?"

[No. L-42011/19/83-D. II (B)]

मावेश

का॰ मा॰ 870:—एयर इण्डिया के प्रबंधतंत्र और उनके कर्मकारों, जिनका प्रतिनिधित्व इन्डियन पाइलटस गिल्ड, बस्बई, इंडियन प्लाइट नेवीरोटसें गिल्ड, बस्बई, एयर कारपोरंशन एम्पलाईज यूनियन, बस्बई, इण्डियन एयरकाप्ट टेक्नीशियन एसोसियेशन, बस्बई, प्राप्त इंण्डिया एयरकाप्ट इंजीनियसें एसोसियेशन, बस्बई, एयर इंडिया एस्पलाईज गिल्ड, बस्बई, इण्डियन प्लाइट डिस्पैंचर्स प्राप्त क्षाइट इंजीनियसें एसोसिएशन बस्बई, इंडियन एलाइट डिस्पैंचर्स यूनियम, बस्बई तथा एयर इण्डिया केंबिन न्यू एसोसिएशन, बस्बई करती है, ने संयुक्त क्य से श्रीद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (2) के प्रधीन केन्द्रीय सरकार को प्रावेदन किया है कि उनके बीच विद्यमान भौकोगिक विवाद को, जो उनके प्रावेदन किया है कि उनके बीच विद्यमान भौकोगिक विवाद को, जो उनके प्रावेदन में उठाए गए मामलों से संबंधित है और जिन्हें इससे उपाबद्ध अनुसूची में विया गया है, श्रीद्योगिक प्रधिकरण को भैजा जाए;

श्रीर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि श्रावेदन करने वाले व्यक्ति प्रत्येक पक्ष की बहुसंख्या का प्रतिनिधिस्व करने हैं।

श्रतः श्रव, केन्द्रीय सरकार, भौद्योगिक विवाद श्रिक्षितियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (2) द्वारा प्रदक्त शिक्तयों का प्रयोग करते छुए उक्त विवाद को उक्त श्रिष्ठित्यम की धारा 7क के श्रिष्ठीन गठित केन्द्रीय सरकार भौद्योगिक श्रीकरण नम्बर 2, बस्बई को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अन्सूमी

 नया एयर इन्डिया के प्रबन्धरांत्र ने सभी एमोणियेशनों/यूनियनों/गिल्डो/ कर्मचारियों के साथ प्रतिरिक्त महत्रगांई भन्ता, ग्रौर पश्चिती महत्रगाई भन्ते A term of the terms of the term

के सम्बन्ध में किए करारों/समझौतो/त्रधनवद्भता की शतों के अनुसार 1-4-75 से प्रभावी होने वाले अतिरिक्त मंहगाई मत्ते और परिवर्ती भरते की अदा-अमी कर दी है? यदि नहीं, तो कर्मचारी किस अनुतोष के दकरात हैं और परिदा, तो किस अवधि के लिए?

2. क्या उपर्युक्त खंड 1 में विनिधिष्ट करार, समक्षाने, वचर बहुता का परिनिधिरण, जहां तक प्रतिविधिरण महनाई मत्ता और गरिवनों महनाई मत्ता का संबंध है, इस विषय में सरकार द्वारा एयर इन्डिया को जारी की गई स्वीकृति/निर्देण परिपत के प्रमुख्य किया गया था? यथि नहीं तो कर्मचारियों को परिणामिक हानि क्या हुई? वे किया प्रमुतोष के हकदार है प्रोर किस तारीख से?

[एल०/11025/3/84-डी-2(बी)] टी. बी. संतारमन, ग्रवर मणिव

ORDER

S.O. 870.—Whereas the employers in relation to the management of Air India and their workmen represented by the Indian Pilots' Guild, Bombay, Indian Flight Navigators' Indian Guild Bombay, Air Corporation Employees' Union, Bombay Aircraft Technicians Association, Bombay, All India Aircraft Engineering Association, Bombay, Air India Employees' Guild Bombay, Indian Flight Engineers' Association Bombay, Indian Flight Despatchers Union Bombay and Air India Cabin Crew Association, Bombay have jointly applied to the Central Government under sub-section (2) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) for reference of an industrial dispute the exists between them to an Industrial Tribunal in respect of the matters set forth in the said application and reproduced in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government is satisfied that the persons applying represent the majority of each party;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby refers the siad dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal No. 2 Bombay constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

- I. Whether the Management of Air India has paid the employees the Addl. D. A. and variable D. A. effective 1, 4, 1975 and thereafter in accordance with the terms of agreements/understandings commitments made with all the Association/Unions/Guild/Employees relating to the payment of A.D.A., and V.D.A.? If not, to what relief are the employees entitled and if so for what period?
- II. Whether the agreement commitments, understanding referred to in Clause I above in so far as they relate to A.D.A. and V.D.A. were arrived at in conformity with the Government approval/directive/circular on the subject issued to Air India? If not what has been the resultant long to the employees? To what relief are they entitled and from what date?

[No. L-11025(3)/84-D,H(B')] T. B. SITARAMAN, Under Secv.

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 1984

आदेश

का० आ० 871---केन्द्रीय सरकार की राध है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में मैसर्स सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड रामागुंडम डिजीजन JI डाकघर गोयावरी खानी, जिला करीमनगर (बान्ध प्रवेश के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध एक श्रीधोगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है;

भौर केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्वेशित करना वोछनीय समझती हैं; धतः केन्द्रीय सर्काँन, भौशोगिक विवाद प्रधिनियम, 1947 (1974 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त सिक्तयों का प्रयोग करते हुए, एक श्रीद्योगिक प्रधिकरण गठित करती है जिनके पीठसीन प्रधिकारी श्री एम० श्रीनियास राष्ट्र होंगे, जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा भीर उक्त विवाद को उक्त प्रधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्वेशित करती है।

अनुसुषाः

"स्या मैनर्क निगरेनो कालिनरीज कम्यनी निमिटेड, रामागृंडम किबी-जन-गि, डाकघर गांवाबरीखाणी, जिला करीमनगर (प्रान्झप्रदेश) के प्रवत्यतंत्र द्वारा गोंदाबरीखानी 6ए इन्कलाईन के कोल फिलर, श्री समुद्रला लिगेया की 17-8-1982 से सेवाए समाप्त करने की कार्यवाही स्थायोचित है? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस प्रानुसंघ का हकदार है?"

[संख्या एल- 22011/7/83 डी०3 (बी)]

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION New Delhi, the 10th February, 1984

ORDER

S.O. 871.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Singareni Collieries Company Ltd., Ramagundam Div. II, Post Office Godavarishani District Karimnagar (Andhra Pradesh) and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to rofer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7 A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act. 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri M. Srinivasa Rao shall be the Presiding Officer with headquarters at Hyderabad and refer the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Messrs Singareni Colleries Co. Ltd., Ramagundam Div. II, P.O. Godavarikhani District Karimnagar (A.P.), in dismissing from service with effect from 17-8-1982 Shri Samudrala Lingaiah, Coal Filler, Godavarikhani 6A Incline is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?"

[No. L-22011/7/83-D. III (B)]

का॰ अ१० ४७.२ - इससे उपाश्व अनुसूची में विनिष्टि मामलों के संबंध में मैसमें ल्ंगथड़ा मिनन्त्र प्राहेंबेट लिमिटेड के प्रवत्थलंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के जीन विद्यमान औद्योगिक विदाद को अम और गुनर्हाण मंत्रालय (अम और रोजगार विभाग) के आदेण मंख्या 29011/40/73 एस॰ और॰ IVतारीख 29-9-73 द्वारा न्यायनिर्णयन के लिए औद्योगिक अधिकरण के पास क्षेत्रा गवा था, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री बी॰ एन॰ जयादेवप्या होंगे और जिनका मुख्यालय बंगलौर में होगा;

बंगलौर में कर्ताटक के उच्च न्यायालय मे मैंसर्स तुंगभद्रा भिनररून प्राईवेट लिमिटेड हारा दायर रिट याचिका में इस मामले की वैद्यता को चुनौती दी गई है, रिट याचिका को ऑणिक रूप से स्वीकार कर निया गया और इस मामले के उक्त आदेश को रद्द कर दिया गया, जहां तक कि इस की अमिकों की छंटनी से संबंधित प्रथम प्रश्न का संबंध है;

श्री बी॰ एन॰ जयादेवच्या काफी पक्ष्मे सेया ने निवृत्त हो गये और उनकी सेयाएं अब उपलब्ध नही है;

केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे जपायस अनुसूची मे विनिर्दिष्ट विषय के बारे में मैसर्स तुगभन्ना मिनरलस प्राईवेट, लिभिटेड के प्रबन्धसंत्रं से संस्वत्र निर्याजकों और उनके कर्मकारों के बीच औद्योगिक धियाद विद्यमान है: और केम्ब्रीय सरकार जक्त विवाद को न्याय-निर्णयन के लिए निर्देशित करना वाळनीय समक्षती है;

अतः केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7 क और धारा 10 की उपधारा (i) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त सक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री बी० एक० उपाध्याय होंगे, जिनका मुख्यालय बंगलौर में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

- 1. क्या सभी कमें जारी लेखा वर्ष 1971-72 और 1972-73 के लिए बोनस के हकदार है और बोनस की माक्षा क्या है, जिसके लिए वे हकदार है?
- 2. क्या श्री सी० के० भास्कर, कम्प्रैसर आपरेटर के ग्रेड-II में निर्धारण की पुनरीक्षा करने और विचार विमर्ग करने की आवश्यकता है? यवि हो, तो वह किस अनुतोष का हकवार है और किस सारीख से ?

[संख्या एल- 29011 /40/73- एल॰ आर॰/डी॰ III (वी)]

S.O. 872.—Whereas an industrial dispute existing between the employers in relation to management of Messrs Tunga-bhadra Minerals Pvt. Ltd., and their workmen was referred for adjudication vide Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) Order No. L-29011/40/73-LR. IV dated 29-9-73 to the Industrial Tribunal Tribunal Shin B.N. Jayadevappa as Presiding Officer with head-quarters at Bangalore in respect of the matters specified in the schedule annexed thereto;

Whereas on a writ petition filed by Messrs Tungabhadra Minerals Pvt. Ltd. in the High Court of Karnataka at Banglore questioning the legality of the reference, the writ petition was allowed in part and the order of reference was set aside in so far as it relate to the first question pertaining to the retrenchment of workmen:

Whereas Shri B.N. Jayadevappa retired from service long back and his services are no longer available.

Whereas the Central Government is of the opinion that industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Tungabhadra Minerals Pvt. Ltd. and their workmen in respect of the matters specified in the schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7 A and clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Shri V.H. Upadhyaya as Presiding Officer with headquarters at Bangalore and refers the said dispute for adjudication to the said Industrial Tribunal.

SCHEDULE

- (1) Whether all the employees are entitled to bonus for the accounting years 1971-72 and 1972-73 and what is the quantum of bonus they are entitled to?
- (2) Whether the fixation of Shri C.K. Bhaskar, Compresser' Operator, in Grade II needs review and consideration? If so, to what relief is he entitled and from what date?"

[No. L-29011/40/73-LR IV|D. III(B)]

नई विल्ली, 5 मार्च, 1984

क ब्लाब 873.— मैंसर्स गोगटे मिनरस्स रेडी के प्रवन्धतंत्र से सम्बन्ध नियोज कों और उनके कर्मकारों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व रेडी कामगार संगठन करती है, एक औधोगिक विवास विद्यमान है; 1515 GI/83—6 और उस्त नियोजकों और कर्मकारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (I) के उपबन्धों के अनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को माध्यस्यम् के लिए निवेशित करने का करार कर लिया है और उस्त अधिनियम की धारा 10-क की उप-धारा के अधीन उक्त माध्यस्यम करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है।

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (3) की उपबन्धों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थम करार को एतवृद्धारा प्रकाशित करती है।

(करार)

(आधोगिक विवाद अधिनियम, 1947 की घारा 10-क के अधीन) पक्षकारों के नाम:

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले

- श्री डी॰ एस॰ राव, एजेन्ट, मैंसर्स गोगटे मिनरल्स, डाकधर रेडी, जिल्ला सिल्ब्युर्ग, महाराष्ट्र
- श्री बी० एस० माथुर, जान प्रबन्धक, मैससे गोगटे मिनरस्स, डाकचर रेडी, जिला सिन्युवुगें
- श्री एस० पी० गोखले,कार्मिक अधिकारी

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने बाले

- श्री आर० बी० तिबारेकर, उपा-ध्यक्ष, रेडी कामगार संगठन डाकवर रेडी, जिला सिन्युदुर्ग
- श्री पी० लक्ष्मीनारायण, सेंश्रेटरी, रेबी कामगार संगठन।
- श्री एस० एस० भौसले, आल इन्डिया पोर्ट एड डाक वर्कर्स फेडरेशन को प्रतिनिधि

पक्षकारों के बीच निम्मलिखित औद्योगिक विवाद को श्री एवं औं भावे, उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई विल्ली 11001 के माध्यस्थम के लिए निर्देशित करने का करार किया गया है।

- 1. विनिर्विष्ट विवाद ग्रस्त विवय:
- (1) 1-1-1983 से 15-3-1983 तक 67 कर्मकारों की अभिकषित अवैध जबरी छुटटी और कानूनी तौर पर देय राशियों का भुगतान किए वगैर 16-3-1983 से 249 कर्मकारों की अवैध छंटनी।
- (2) विवाद के पक्षकारों का विवरण 1. मैससं गोगटे मिनरस्स प्राईवेट जिसमें अंतर्कतित स्थापना या उपक्रम लिमिटेड, डाकघर रेडी, जिला का नाम और पताभी सम्मिलत है। सिन्दुपूर्ग, महाराष्ट्र।
- (3) यदि कोई संघप्रकारत कर्मकारों रेडी कामगार संगठन, डाकघर रेडी, का प्रतिनिधित्व करना हो ती जिला सिन्दुवुर्गे। उसका नाम
- (4) प्रभावित उपक्रम में नियोजित 310 कर्मकारों की कूल संख्या

हम यह करार भी करते हैं कि मध्यस्य का विनिश्चय हम पर आवद्य होगा।

हम यह भी करार करते हैं कि पंचाट देने के लिए 6-1-1984 से आगे छह मास की अवधि बढ़ाई जाय! मध्यस्थ अपना पंचाट छह मास की बढ़ाई अवधि के भीतर देगा। यदि पूर्व वर्णिस कालावधि के भीतर पचाट तही दिया जाता तो माध्यस्थम के लिए निर्देश स्वतः रह हो जाएगा और हुम नए माध्यस्थम के लिए बातचीत वरने को स्वतन्त होगे।

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने कमें का प्रतिनिधित्व करने वाले के हस्ताक्षर के हस्ताक्षर के हस्ताक्षर के हस्ताक्षर हैं। इंग्लें के हिस्ताक्षर हैं। इंग्लें के हिस्ताक हैं। इंग्लें

माक्षी

- ा 'त्रिं भी किं एोजन, सहायकं श्रमायुक्त (वेन्द्रीय) वे आंशुलिपिक
- 2 ह०/-(अपठनीय) अवर श्रेणी लिपिक एव, खजाची मार्फत सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय) बास्कोडिगामा है। उन्हें के जनवरी, 1984

[सं० एल० 29012/35 /83 डी०-3 (बी)]

ORDER

Naw Delhi, the 5th March, 1984

S.O. 873.—Whereas an industrial dispute exists between the management of M/s. Gogte Minerals, Reddi and their workman represented by Redi Kamgar Sanghatana.

And where is the said employers and their workmen have by a written agreement under sub-section (1) of Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), agreed to refer the said dispute to "A bitration and have for warded to the Central" Government under sub-section (3) of Section 10-A of the said Act, a copy of the said arbitration agreement.

"Now, therefore, in pursuance of sub-section (3) of section 10-A of the said Act, the Central Government hereby publishes, the paid agreement;

AGREEMENT

(Under Sec. 10-A of the Industrial Disputes Act, 1947)

BETWEEN

NAMES OF THE PARTIES

REPRÉSENTING EMPLOYER

- 1. Shri D.S. Rao,
 Agent,
 M/s. Gogte Minerals,
 P.O. Redi,
 Distt: Sindudurga,
 Maharashtra.
- 2. Shri V.S. Mathur, Mines Manager, M/s. Gogte Minerals, P.Q. Redi. Distt. Sindudurga.
- 3. Shri S.P. Gokhale, Personnel Officer.

REPRESENTING WORKMEN

- Shri R.V. Tiv ekar Vice-President, Redi Kamgar Sanghatana, P.O. Redi, Dist. Sindudurga.
- 2. Shri P. Laxminarayan, Secretary, Redi Kamgar Sanghatana.

3. Shri S.S. Bhonsle, Representative of All India Por: & Dock Workers Federation.

It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of Shri H.G. Bhave, Deputy Chief Labour Commissioner (Contral). Minist y of Labour, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi- 10001.

- (i) Specific matters in dispute: Alleged illegal lay off of 67 workmen from 1-1-1983 to 15-3-1983 and illegal retrenchment of 249 workmen from 16-3-1983 without payment of legal dues.
- (ii) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment: M/s. Gogte Minerals Pvt. Ltd. P.O. Redi, Dist: Sindudurga, Maharashtra State.
- (iii) Name of the Union representing the workmen: Refi Kamgar Sanghtana, P.O. Redi, Dist: Sindudurga.
- (iv) Total No. of workmen employed in the undertaking effected: 310

We further agree that the final decision of the arbitration be binding on us.

We further agree to extend the period of further six months to make award from this day the 6th January. 1984. The arbitrary shall make his award within further extended period of SIX MONTHS. In case, the award is not made within the period atorementioned, the reference to arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

,	
SIGNATURE OF	SIGNATURE OF
RÉPRESENTATIVES OF	REPRESENTATIVES OF
EMPLOYER	workmen/union.
Sd_{ℓ}	Sd/
(D.S. Rao)	(R.V Tivrekar)
Sd/	S J/
(V.S. Mathur)	(P. Laxminarayan)
Sd/	SJ/
(S.P. Gokhale)	(S.S. Bhonsle)
WITNESSES	
1. Sd/	2. \$d/
(V.K. Rajan)	(filegible)
Steno to the ALC (C),	LDC-CUM-CASHIFR.
Vasco-da-Gama.	C/o A.L.C. (C), Vasco.
Dated, 6th January, 1984	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

[No. L-29012/35/83-D.JII.

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1984

ग्रादेश

का० आ० 874. वेस्टर्न कोल फेल्ड्स लिमिटेड, प्रथिकेडा एरिया, जिला बेतुल, (मध्य प्रदेश) के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजको और उन्नके कर्मकार श्री पी० आर० वसमारे, भूतपूर्व सेमी कर्क, वेस्टर्न कोक फील्ड्स लिमिटेड, प्रथिकेडा एरिया के बीच एक ओहोगिक विवाद विद्यमार्ग हैं.

अौद्धा जनत नियोजकों और कर्मकारों ने अौद्योगिक विवाद प्रधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की जपधारा (1) के जपबन्धों के अनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करते का वारार कर लिया है और अक्त सिधिनियम् की विवास की का वारार कर लिया है और अक्त सिधिनियम् की विवास की जिससा 10क की जप-धारा (3) के अधीन उक्त माध्यस्थ्यम् करार की एका अनिता के केनी गर्ध

ग्रत, ग्रब, ग्रीद्यागिक विवाद प्रधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपश्रीरा (3) ने 'उपबन्धी के ग्रनुसरण मे, नेन्द्रीय सरकार उवत माध्यस्थमं करार का एतद्द्वारा प्रकाणित करती है।

(करार)

(ग्रौद्याभिक विवाद प्रधिनियम, 1947 की धारा 10-क के प्रधीन)

जिनयाजका का प्रांतिनिधित्व करने वाले

श्री एस० बीं कटियाड, उप-मुख्य कार्मिक प्रबन्धंक, वेस्ट कोल फील्डस लिमिटेड, पथ-खेडा एरिया जिला वेत्रल (सध्य प्रदेश)

वमकारो का प्रतिनिधित्व करने वाच

ा श्री पी० श्रार० बघमेरा, भूत-पूर्व सेमी क्लर्क, ग्रेड-3, पथखेडा कॉल माइन्स.

> मार्फर्त थी बे॰ एल॰ पगडीयाजी, कोठी बाजार बेतुल (मध्य प्रदेश)

पु सभावकर्र) क बीच निम्नलिखित ग्राद्यागिकः विवाद का मुख्य श्रमायुक्त (किन्द्रीय) 'वीर्यलिय, नई दिल्ली में उप मुख्य श्रमायुक्त श्री एच० जी० भाजे के माध्यस्थम के लिए निर्देशित करने का करार किया गया है।

,।।। ब्रिनिनिया विशास सम्म निसंस

- (1) "क्या वेस्टर्न मील फील्डस् लिमिट्रेड, पथखेडा एरिया, वेतुल (मध्य प्रदिश) की श्री पी , श्रारं बयमारे, भूतपूर्व सेमी-बुलर्क, ग्रेंड-3 पर्यखेडा कोल माइत्स, मार्फत श्री जे० एल० संगात पूर्णांडयाजी, काठी बाजार, बेतुल, मध्य प्रदेश की 11-2-1980 में सेवा से हटाने की कार्रवाई न्यायाचित है ? यदि नहीं, तो न्क्त क्रमेंकार विस अन्ताप का हक्दार हे ? '
 - ्विवरण, जिसमे इन्तव-्राहेनित् स्थापन या इपकम ना नाम ग्रीर पता भी सम्मि-वित है।

(11) विवाद के पक्षकार का 1 श्री पी० ग्रार० बघमारे ग्रात्मज श्री जागाजी, पथ्खडा काल माइन्स, जिला बेतुल, सर्फत पगडीयाजी, श्री जे० एउ० कोठी बाजार, बेतुल, प्रदेश ।

वनाम

1 परियाजना अधिकारी, पथ-खेडा परियाजना प्थखेडा एरिया कालफील्डम लिमिटेड जिला बेतुल ू (मध्य प्रदश)

(111) कमकार

श्री पी० ग्रार० वघमारे, ग्रात्मज श्री जागाजी द्वय ही।

- (AV) प्रभावित उपक्रम म नि-योक्तित कमवारो की कुल
 - , 4500 लगभग
- (v) विवाद द्वारा प्रभाविल या सम्भाव्यत प्रभावित होने वाले कुर्मकारो को , प्राक्वनित रेग्रा

हम यह बागर अभि 'फॉरन' र पि मध्यस्थ वर विनिष्नम हम पर श्रावद्धकर होगा

मध्यस्य। अपनाः पंचाटः छहः सासः कीः कालाक्ष्यः , ब्राः । हतने त्र्योरः समय े के भीतर, जो हमारे बीचे पारस्परिक सिंखित् कूरीर प्रिति बढ़ाया जाय, देगा । यदि पूर्व वर्णित कालाविधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता तो माध्यस्थम के लिए निदेश स्वर्तः रहे हो जाएगा और हम नए माध्यस्थम के लिए बातचीत करने की स्वतंत्र होंगे।

पक्षकारों के हस्ताक्षर, nematiow (iii) नियोजको का प्रतिनिधित्व करने वाले कर्मकारों का प्रतिनिधित्कि करने वाले

श्रात्

हरेंसि 🗓

(एस०बी० कतियाड़) उप मुख्य कार्मिक प्रवत्स्वक, वैस्ट्रेन कोल फील्डस लिमिट्रेड

भतपूर्व प्**यक्षेत्र** कोल पूल ० ांहर <u>क्लाइ</u>ज़ हेतुल्ह

मध्य प्रदेश

मःसी

लिमिटेड, पंथखेडा 🗓

,2. हु०/- अष्ठक्तीय

सं एलं 22013/4/83-डी-3(बा)] नन्द लाल, ग्रवर सचिव

ORDER"

New Delhi, the 7th March, 1984 antho mask

S.O. 874: Whereas an industrial dispute exists between the mahagement of Western Coalfields Limited, Pathakhera Area, Disti. Betul (M.P.) and their workman Shri P. R. Baghmare, Exisemi Clerk, WCL, Pathakhera area of WCL.

And whereas, the said employers and their workman have by a written agreement under sub-section (1) of Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), agreed to refer the said dispute to Arbitration and have forwarded to the Central Government under sub-section (3) of Section 10A of the said Act, a copy of the said arbitration agreement.

Now therefore, in puisuance of sub-section (3) of section 10A of the said Act, the Central Government hereby publishes the said agreement;

AGREEMENT

(Under Section 10-A of the Industrial Disputes Act, 1947) BETWEEN

NAME OF PARTIES

Representing Employers Shri S. B. Katiyarı Dr. Chief Personnel Manager, W.C. Limited, Pathakhera Area., Distt. Beul (M.P.).

Representing Workman—Shri P. R. Baghmare, Ex-Seni Clerk, Gr. III, Pathakhera Coal Mines C/o Shri I. L. Pagariyay, Kothi Bazar, Betul (M.P.)

office of the Chief Labour Commissioner (Central). INsw असकः महास्यि ४ पर १ र १ १ १

- (11) Details of parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved.

(1) Shri P. R. Baghmare S/o Shri Jagoji, Ex-Semi Clerk, Gr. III, Pathakhera Coal Mines, Distt. Betul, C/o Shri J. L. Pagariyaji, Kothi Bazar, Betul (M.P.)

VERSUS

- (1) Project Officer, Pathakhera Project, Pathakhera Area, W.C. Limited, Distt. Betul (M.P.)
- (iii) Workman Shri P. R Baghmare S/o Shri Jagoji himself.
- (iv) Total number of workmen employed in the undertaking affected: 4500 appx.
- (v) Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the dispute; One

We further agree that the decisions of the arbitrator will be binding on us.

The arbitrator shall make his award within a period of six months or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case the award is not made within the period aforementioned, the reference to arbitrator shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh agreement(s).

Signtures of the parties

Representing Employers:

Sd/-(S. B. KATIYAR), Dy. Chief Personnel Manager, WCL

Representing Workman .

Sd/(P. R. BAGHMARE),
Ex-Semi Clerk, Gr. III,
Pathakhera Coal Mines,
C/o Shri J. L. Pagariyaji,
Kothi Bazar, Betul (M.P.)

Witnesses:

Sd/-(P. UNNIKRISHNAN). UDC, WCL Pathakhera Sd/- (Illegible)

INO. L-22013/4/83-D.JIJ.B]

NAND LAL, Under Secy.

नई फिल्मी, 2 फरवरो, 1984

आवेश

का॰भा॰ 875.—-केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद धनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में मैससे हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड की बादमारी कापर प्रोजेक्ट के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध एक भौद्योगिक विवाद नियोजकों भौर उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान हैं,

भीर केन्द्रीय संरकार उक्त विवाद को स्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती हैं,

भ्रतः, केन्द्रीय सरकार, भौद्योगिक विवाद मिधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क भीर धारा 10 की उप धारा (i) के खण्ड (ब) इसरी प्रदस्त सिन्तियों का प्रयोग करते हुए एक भौद्योगिक भ्रधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन मिधिकारी श्री महेन्द्र भूषण शर्मा होंने, जनका मुख्यालय जयपुर में होगा भीर उक्त विवाद को उक्त मिधिकरण को न्यायनिणयम के लिए निर्वेशित करती है।

अनुसूची

"क्या मैसर्स हिन्दुस्तान कापर लि॰ के चावमारी कापर प्रोजेक्ट के प्रवन्त्रतंत्र का निम्नलिखित तीन कर्मचारियों की निलम्बन प्रविध, जिसे बाद में इ्यूटी पर उपस्थिति के रूप माना गया, के लिए प्रजित छूट्टी मंजूर न करना त्यायोजित हैं? यदि बही तो वे किस धनुतोष के हकवार है?

निलम्बन अवधि

- 1. श्री जय सिंह 12-1-1980 से 23-8-80 तक
- श्री महेन्द्रर कुमार 18-10-1980 से 1-1-81 तक
- 3. श्री **६श्वरराम** 18-10-1980 से 1-1-1981 तक

[सं० एल- 43012/2/83-की -3 (बी)]

New Delhi, the 2nd February, 1984

ORDER

S.O. 875.—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Chandmari Copper Project of M/s. Hindustan Copper Limited and their workman in respect of the matter specified in the schedule hereto annexed:

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and caluse (d) of subsection (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitute an Industrial Tribunal of which Shri Mahendra Bhushan Sharma shall be Presiding Officer, with headquarters at Jaipur and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the management of Chandmari Copper Project, Khetri Nagar of M/s. Hindustan Copper Ltd. are justified in not granting the earned leave for the suspension period, which was subsequently treated 'as on duty' to the following three employees? If not, to what relief they are entitled?"

Suspension Period

- 1. Shri Jai Singh 12-1-1980 to 23-8-80
- 2. Shri Mahendra Kumar 18-10-80 to 1-1-81
- 3. Shri Ishwar Ram 18-10-1980 to 1-1-1981.

[No. L-43012/2/83-D.III(B)]

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 1984

भावेश

का० घा० 876, — केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपावद्ध घनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में भारतीय जीवन बीमा निगम मछलीपत्तनम के प्रवंघतंत्र से सम्बद्ध एक भौद्योगिक विधाव नियोजकों भौर उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है,

भौर केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्वेशिक्त करना बांछनीय समझती हैं,

भतः केन्द्रीय सरकार, भ्रौयोगिक विवाद धिवियम, 1947 (1947 का 14) की आरा 7-क भौर धारा 10 की उपधारा (i) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक भौधोगिक श्रिधकरण गठित करती है जिसके पीठासीन प्रधिकारी श्री एम० श्रीनिवास राव होंगे, जिनका मुख्यालय हैकराबाद में होगा भीर उक्त विवाद को उक्त प्रधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्वेशित करती है ।

अनुभूची(

"क्या भारतीय जीवन बीमा निगम, मछलीपत्तनम के प्रबन्धतंत्र की गल्दुर जिलें में स्थित भपने भाष्मा कार्यालय नरसैरोपत में कार्यरत भौकीवार, श्री डी० जिला रसुलु की 5-2-1983 से सेवाएं समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोजित है? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस धनुतोष का हकदार है।

सिं**०** एस-17012/11/83 औ -4ए]

New Delhi, the 6th February, 1984

ORDER

S.O. 876.—Whoreas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in

relation to the management of Life Insurance Corporation of India, Machilipatnam, and their workman in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

An whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A, and clause (d) of subsection (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Indusrial Tribunal, of which Shri M. Srinivasa Rao shall be the Presiding Officer with headquarters at Hyderabad, and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Life Insurance Corporation of India, Machilipatnam in relation to their Branch Office, Narasaraopet, Guntur District in termination the service of Shri D. China Ramulu, Watchman with effect from 5-2-1983 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?"

[No. L-17012(11) /83-D.IV(A)]

आदेश

का०आ० 877.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाधक अमुसूची में विनिदिष्ट विषय के बारे में वैंक आफ बढ़ीवा के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान हैं, ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विचाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना बांछनीय समझती है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की घारा 7-क और धारा 10 की उप-धारा (i) के खंड (घ) द्वारा प्रवत्त ; क्षित्रयों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गिटत करती है जिसके वांठासीन अधिकारी श्री महेन्द्र भूषण वार्मा होंगे जिनका मुख्यालय जयपुर में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"यम बैंक आफ बड़ीया, जयपुर के प्रबन्धतंत्र की बैंक की शाखा जोहरी बाजार, जयपुर में कार्यरत श्री राम सिंह, चपरासी की 24-6-76 से सिंवाएं समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है? यदि मही, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोप का हकदार है?"

[सं॰ एल-12012/221/83-को-2(ए)]

ORDER

S.O. 877.—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Bank of Baroda and their workmen in respect of the matter specified in the schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri Mahendra Bhushan Sharma shall be the Presiding Officer, with headquarters at Jaipur and refers the gaid dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Bank of Baroda, Jaipur in relation to their Johari Bazar Branch, Jaipur in terminating the services of Shri Ram Singh, Peon with effect from 24-6-76 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entit-

[No. L-12012/221/83-D. II(A)]

आवेश

काल्यां 878 — केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिविष्ट विषय के बारे में यूनाइटिड वैंक आफ इंडिया के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकां और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है,

अतः केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उन धारा (i) के खंड (घ) द्वारा प्रवेत समितयों का प्रयोग करने हुए, एक ओद्योगिक अधिनरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री जीवण्सव बरोन होंगे, जिनका मुख्यालय अहमवाबाव में हांगा और उन्त विवाद को उन्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्वेशित करती है।

अनुसूची

"क्या यूनाइटिड बैंक आफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय, पविश्वनी क्षेत्र, बम्बई के प्रवन्यतंत्र की अपनी शाखा न्यू कराय माफिट, अर्भदावाद में कार्यरस अधीनस्य कार्यकारी, श्री एम०वी० पिशा का आश्रम रोड एएखा, अहमदाबाद में तैनात करने से इंकार करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यवि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोय का हकवार है ?"

[सं॰ एल-12012/218/83-झी-2(ए)]

ORDER

S.O. 878.—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of United Bank of India, and their workman in respect of the matter specified in the schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7-A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri G. S. Baret shall be the Presiding Officer, with headquarters at Ahmedabad and refers the said dispute for adjection to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of United Bank of India, Regional Office, Western Region, Bombay In denying posting to Shri S.V. Mishra, Sub-staff from its New Cloth Market branch, Ahmedabad to Ashram Road branch, Ahmedabad is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?"

[No. L-12012/218/83-D. II(A)] .

आदेश

नर्ष दिल्ली, 7 फरवरी, 1984

का०आ० 879.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपावक्ष अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में विका आफ बड़ोदा के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान हैं;

और केन्द्रीय सरकार उसत विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना बांछमीय समझती है: अंत, "कैन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947(1947 का 11) की धारा 7 न आर धारा 10 की उप-धारा (i) के खण्ड (घ) इंग्रेंग प्रदक्त सक्तियों का प्रयाग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीऽासीन अधिकारी थी हिन्द्र भूपण सर्मा होगे, जिनका मुखालय जपपुर मे होगा और उका विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्वेषित करती है।

अनुस ची

"वया बैक आफ बटोदा, जयपुर की शहर शाखा जिला सवाईमाधोपुर से सर्वाधत प्रवन्धतत्व द्वारा श्री एन०एल० बैरवा, अधीनस्य कर्मचारी, की 23-6-81 से सेवाए समाप्त करने की रार्धवाही न्याग्रीचित ह ? यदि नही, तो सब्धित कर्मकार किय अनुनोष का हकदार है?

[सङ एल-12012/257/83-डी-2(ए)] एन०के० वर्मा, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th February, 1984.

ORDER

S.O. 879.—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the manageme. ... P. ... P. and their workman in respect of the receive an execution in the contract of the receive annexed;

And whereas the Central Covernment considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7 A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby consitutes an Industrial Tribunal of which Shri Mahendra Bhushan Sharma shall be the Presiding Officer. With headquarters at Jaipur and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

When the action of the northern's of Bank of Brend, In put in claim, of 1.7 but an Branch, 1.4 a. rawannadion to be 1. a. rawa

[No. L-12012/257/83-D. II (A)]

N. K. VERMA, Desk Officer

New Delpt. the 1st March, 1984

S.O. 880.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes: 1, 1927 (i.t. of 1947), the Central Government by the publicle, the new York award of the Central Government Industrial Tribunal. New Delhi, in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of Pikaner and Jaipur, Kanpurland their workmen, which was received by the Central Government on the 21-2-84.

BEFORE SHRI O. P. SINGLA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL, GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I. D. No. 92 of 1983

In the marter of dispute between

Shri Khema Nand Joshi, C/o The Assistant General Secretary, UP. Bank Employees Union, 36/1, Kailash Mandir. Kanpur.

٧s

The Manager.
State Bank of Bikaner and Jupus.
Birhana Road,
Kanpur

APILARANCLS:

Miss Mithlesh—for the Management. None for the Workman.

AWARD

The Central Government, Ministry of Labour, vide Order No. L-12012 '212/81-D.H(A) dided 19th March, 1982 referred the following dispute to this ribbural for a hadic not to-

Whener the exten of the management of Sate Bank of Bikarer and Unpur Detelation to their Birhana Road Baren, kenger in sof prood their ployment of all kenne same Joshi. Clerk allet 8-3-79 and terminent in his services is justified. If no to what only is an everymon concerned entitled.

2. Shi Harmangal Parsad Assistant General Secretary, U.F. Ben Frepleyce, Unon, Kanpur, filed the statement of clarg. It was pleated that khemr Nand Joshi joined the services of State Bank of Branei and Jaipir, Bahana Road, Kanpur or 19-12-1978 as a Clerk, and his services were terraneted on 8-2-1979 the was not issued any appointment letter nor letter of termatation. The appointment was the to be manifest from the post after 80 days. There was said to, be violation of Section, 25-H of the TD Act 1947 Reinstatement in service with full back wages was claimed

The manager of the test the claim and asserted that the appointment of the services was only in a temporary capacity and be was not appointed on permanent post and his service, and he has the vas appointed. The termination of his service was said to be not rettenchment because he did not work for 240 days in a period of 12 calendar months. He was not appointed in a regularly by undergoing the recruitment procedure and is as a potential to seek permanent employment in the prescribe procedure. His permanent appointment would violate provisions of 112 and 15 of the Constitution of India masmuch as verkman would get a march over other candidates the seek emission of contact the prescribed procedure and would be denial of and appointment for public employment guaranteed to an employment part and has never appointed to fill a permanent part the fill has never appointed to fill a permanent part the fill has never appointed to fill a permanent part the fill has never appointed to fill a permanent part the fill has never appointed at fill apported at part of the fill has never appointed at fill has a fill fill apported at part of the fill and the case of State Raik at Bikener and larger Vs. Workman reported at part of the fill appointed at part of the color of the case of State Raik at Bikener and larger Vs. Workman reported at part of the fill approved the action of the fill of the fill of the fill approved the action of the fill of the fill

4 Mr. V V Mangalvedhekar, who appeared for the workman earlier, did not appear to pursue the case

5 No relief can be given to this workman. The provisions of Section 25-7 of the I.D Act, 1947 are not attracted in this case. He dd not work for 24 days in a period of 12 calendar months. He was not appointed in a permanent vacancy and was given only 80 days' employment temporarily. He cannot be allowed permanent employment over ica hing the claims of other Indian Citizens for permanent public employment in Bank service. The action of the nating entitled and justified. Mr. Khema Nand Joshi 1, not entitled to any tellef

The award is made in the term aforesaid.

Further codered flot the requisite number of copies of the article to warded to the Central Government for necessary action at their end

O. P. SINGLA, Presiding Officer [No. L-12012/212/81-D H(A)]

Dated February 13, 1984.

SO 881—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Acr. 1947 (14 of 1947), the Central Government letters of Section 1948, the New Delhi in the ministed dispute between 1948 of love in the letter to the State Back of fiften and their wormen, which was received to the Central Government of the 21281.

The part of the pa

BEFORE SHRIPOLIP SINGLA, PRINDING OFFICER, CENTRALIPOGOVERNMENT INCLUDE CRIBUNAL NEW Delia

I D No 52 of 1983

In the matter of Aspute between

Sha Mukesh Chandra and others
C/o The Assistant General Secretary
UP Bank Employees Union
36/1, Klybish Mindir,
Kanpui

V٩

The Branch Minager
Stare Bux of Flare and Lappur
Billing Local
Kanpur

API 'ARANCÉS

Miss 1

М.

AWARD

The Central Government Manistry of Labour ade Order No 14-12012(350)/61 D II(A) dated to y 19c., referred the following dispute to this fibrial for adjudication —

- But the action to the management of State Bank in Bushest and lateral Kan in relation to the management of the managemen
- 2 The claim statement was filed by Shri Garm and Pravady Assistant General Secretary. UP Rank Employees Unions, Kanper It was pleaded that the eight workmen System M.C. Sir ista. Ashok Kumar, Gares I and Misia Kin Beena Misia Ashok Kumar, Gares I and I inaderia, Shyam Kishore Aggarwal, Dine to those sources in and C. Shukla were appointed by the Minimizer of State Bank of Bikaner and Jaipu in permaner, vacancies but orbitor a specific period, of 80 day, in he year, 1976 to 1981, and they actually worked as under
- M C Stivastava, Km Beena Mista Astok Kumar, D C Stiva tava and C C Shikla worked for 80 two each Ashok Mista worked for 87 tays upto 30.431 G S Phatoria worked for 105 days upto 31.12.50 and Mi S K Aggarwal worked for 227 days upto 5.5.76
- 3 The workmen plea is that the were entitled to notice of termination and the action of the minarement was against paras 496 and 522 of S sty Award and also para 20.7 and 20.8 of the Bi-Partite settlement. It was said to be an unfail labour practice to make appointment in this manner against perminent vacancies. They claimed themstate entitled service with full back wages and continuty of service.
- 4 The management concisted the classification of the management concesses of permanent in the control of the district of the work of the management in the control of the management of the control of the management of the managem
- 5 Mr. V V Matte lec'hêku cho pacarel for the workmen earlier dal not appear for the workmen
- 6 The manas ments case appears to 1 come: The appointments were not for permanent employment and

other Indian citizens did not get a chance to emply for these the which river was available to at local Currens ender code to be the constitution of the local Currens ender voice for the constitution of the local cannot avail off the pied of thotal on of Section 2010 of the LD Act., 1947. Their appointments were only in leave vacuumes. They are not entitled to permanent employment in least service and cannot get an relief the action of the minagement is least and positive.

The second secon

Luther out realth the required divide of copies of this award to remeded the control tovernment for necessary action at their case.

Dated: February 13, 1984

O 7. SINGLA. Presiding Officer 4No. L₁12012/350/81-D-MOAH

New De'hi, the 8th Match 1984

SO 882.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14% o 1947) the Council concernent, hereby publishes the following ment of the Council Council ment Industrial Trainful New Pello in the industrial cispute between the employer, in Edwor to the State Bank of Bikaner and Jorda and them we man, which was received by the Central Government on the 21st behing y, 1984.

BÉFORE SHRI O, P. SINGI A, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL FRIBUNAL, NEW DELFIE

I.D. No 19101 1981

In the matter of distante between

Shi And Kumar Kue C, o The Assistant General Secretary, U.P. Bank Employees Union, 36/1, Kaulash Mandir, Kaunur.

۷s.

The Manager, State Bank of Bikaner & Jappir., 58,445, Bithana Road, Fanpur.

APPEARANCE.

Msis Mithlesh—for the Month rivel. None—for the Wilkin Y

AWARD

The Central Government, Ministry of Labour, vide Order No. L-12012/175/81 O.li(A) dated 10th December, 1981, made a reference of the following dispute to this Tribunal for adjudication:—

- Whether the action of the management of State Bark Bikaner & Jepur, Birhana Road, Kanpur in not providing employment to Shi And Kumar Khine. Clerk after the 31st December, 1960 (A.N.) and ferminating his services is justified. If not, to what relief is the workman concerned entitled.
- 2. The claim statement via filed by Shri Harmangal Piaiad. Assistant General Secretary. U.P. Bank Employees Union, Kanpul M. A. K. Khure worked for 80 days from 13-10-80 to 31.12.80 with the State Bink of Bikanet end appr. Birchant Role Kanpur. The claim made is the ingwas entitled to permanent absorption, and het fresh tend were appointed again for a period of 80 days after strantpating his services. They were sell to be violation of pseas-195 and 522 of Satry Avar I. A. K. Khare was congult to be got ein fated in Bank survey with full back wages as a permanent employee.
- 3. The Bink in informing contested the claim and ascept ed that the appointment was in abunely temporary opposity and came to an end into the the expension of the 80 days, period for which the expension. The mass said to have no legal model to the open indicated the was not appointed after undergoing the requirement provided. His normanement playment was said to be against the period of trules as well as the Constitution expensions pratoming conducts for a nublic employment to all Cityths of today. Similar pariod of the provided at the

- 4. Mr. V. V. Mangalvedhekar, who appeared for the work-man earlier, did not appear later.
- 5. The management has filed copies of the apopintment orders, dated 13-10-80, 12-11-80 and 26-11-80, and the appointments are specifically for 30, 30 and 20 days respectively. The appointments are not against permanent posts. The appointments are purely temporary. The workman does not swim into harbour of Section 25-F of the I.D. Act, 1947, on account of non-completion of 240 days service in 12 calendar months. He cannot be allowed permanent employment in Bank service by violating the equality clauses of the Constitution Article 14 and 16 which guarantee equal opertunity for public employment under the State to all citizens of India. When he was employed other citizens of India did not get opportunity for this job.
- 6. The action of the management of the Bank is iustified and legal and does not require any interference. The workman is not entitled to any relief.

Further ordered that the requisite number of copies of this award be forwarded to the Central Govt. for necessary action at their end.

O. P. SINGLA, Presiding Officer

Dated: February 13, 1984

No. L-12012/175/81-D.II (A)]
N. K. VERMA, Desk Officer

नई दिल्लो, 1 मार्च, 1984

का॰ प्रातः 883.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि भैसर्स वसु टैक्सटाईल्स, यु॰एम॰ मिस्त्री कम्पाउण्ड, नियर इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, क्षापु नगर, श्रहमदाबाद-23 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक भीर कर्म-चारियों की बहुसंख्या इस बात पर सह्मत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि भौर प्रकीण उपबंध प्रक्षिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध द्वार मण्यान हो लाग हिए करने चालिए.

श्रक्त केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा श्रदक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त श्रश्निनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं॰ एस-35019(43)/84/पी॰एफ॰-II)]

New Delhi, the 1st March, 1984

S.O. 883.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the etsabilshiment known as Messrs Vasu Textiles, U.M. Mistry Compound, Near Industrial Estate, Bapunagar, Ahmedabad-23 have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. L-12012/175/81-D.II(A)]

का०मा० 884.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसरी काण किशोर पाती, डी/एल-167, बसन्ती कालोनी, रुरकेला-769012, जिला सुन्वरगढ़, उड़ीमा लामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक भीर कर्म-वारियों की बहुसंख्या हस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि भीर प्रकीण उपवन्ध प्रधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपवंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

े ब्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त ब्रिधिनियम की धारा 1 का उपधारा (4) द्वारा प्रदक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त श्रीधिनियम के उपयन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं॰ एस-35019(33)/84/पी एफ-2]

S.O. 884.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Braja Kishore

Pati, D/L-167, Basanti Colony, Rourkela-769012, District Sundargarh, Orissa have agreed that the provisions of the amployees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of he powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(33)/84-PF.II]

काश्याः 885.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मिना वक्स 6, कुशतिया रोड, कलका-39 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक भीर कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भथिष्य निधि भीर प्रकीर्ण उपवन्ध भधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपवन्ध उक्त स्थापन की लागू किए जाने श्वाहिए,

चतः केन्द्रीय सरकार, उक्त मिंधिनियम की धारा 1 की उपमारा (4) द्वारा प्रदत्त मिंतियों का प्रयोग करते हुए उक्त मिंधिनियम के उप-बंध उक्त स्थापन की लागू करती है।

[सं॰ एस-35017(9)/84-पी एक:II]

S.O. 885.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Mittra Works, 6, Kustia Road, Calcutta-39, have agreed that the provisions of the Employees' Provident, Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-secion (4) of Section I of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(9)/84-PF.II]

का० मा० 886.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स वैपरफेज, 43 ए इन्डस्ट्रियल इस्टेंट गोजिन्दपुरा, भोपाल-462 023 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक भीर कर्मचारिय्में की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि छौर प्रकीर्ण उपबंध छिन्वम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

श्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त श्रिधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन की लागू करती है।

[सं॰ एस-35019(47)/84/पी एफ-II]

S.O. 886.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Vapourphase, 43/A, Industrial Estate Govindpura, Bhopal-462023 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(47)/84-PF,II]

का श्रीत 887 - केन्द्रीय सरकार की यह प्रतीत होता है कि मैससँ इन्टरनेशनल इन्डिस्ट्रियल डेबलपमेंट कर्म्मलटेटस (प्रा॰) लि॰ ज्योति पहली मंजिल, 66-नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 और रिज॰ प्राफिम 310-डिक्टर हाउस 14-पोदार रोड, बम्बई में न्यित नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मबारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मबारी शिंबच्य निधि और प्रकीर्ण उपवन्ध प्रधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपवन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने बाहिए,

श्रतः केन्द्रीय सरकार, उन्त श्रधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त श्रिक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त श्रधिनियम के उप-श्रंध उक्त स्थापन की लागू करती है।

[सं० एस-35019(46)/84-भी एक-2]

S.O. 887.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs International Industrial Development Consultants (Private) Limited. Jyoti 1st Floor, 66-Nehru Place, New Delhi 110009 and its Regd. Office at 310-Doctor House, 14-Peddar Road, Bombay have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment

[No. S-35019(46)]/84-PF.II]

का॰ आ॰ 888.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स लुमक्स विपरस एण्ड स्वीचस प्राइवेट कि 223/1, इन्डिस्ट्रियल एरिया, नंगली सकरवती, नजकगढ़ रोड, नई दिल्ली-110043 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मकारियों की बहुसंख्या इस बान पर सहमत हो गई है कि कर्मनारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपवन्ध गधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपवन्ध उक्त रशयन को लागू किए जाने चाहिए,

श्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रिधिनियम की क्षारा । की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त प्रक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त श्रिधिनियम के उप-बंध उक्त स्थापन को लाग करती है।

[सं॰ एस-35019(45)/84-पी एफ-II]

S.O. 888.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Lumax Wipers and Switches Private Limited, 223/1, Industrial Area, Nangli, Sakravati, Najaf Garh Road, New Delhi110043, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(45)/84-PF.11]

काण्या 889.— केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैंगर्स महेशवरी यांनी सप्लाई एजेंसीज, 532, कटरा तील, चांदती चींक, दिल्ली-110006 और इसकी यांचा पुरानी कोतवाली, जौड़ा बाजार, लृधियांना नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक धूँदर कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि थौर प्रकीर्ण उपबंध यिक्षित्मम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागृ किए जाने चाहिए,

ग्रतः केन्द्रीय सरकार, जक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रवक्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करनी है।

[मं॰ एम-35019(44)/84-पी एफ-II]

S.O. 889.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Maheshwari Yarn Supply Agencies, 532, Katra Neel, Chandni Chowk, Delhi 110006 including its Branch at Purani Kotwali, Chora Bazar, Ludhiana, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment; 1515 GI/83—7

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019 (44)/84-PF. II]

कारुबार 890.—केन्द्रीय गरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स यलाइड कैमिकल्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, बाबूजी का बाग स्टेसन रोड, जयपुर-6, राजस्थान तथा देश बल्धु गुरहा रोड, नई विल्ली-55 थिल इसके पंजीवृत कार्यालय तथा 612, कार्मर्स हाउम, 140, निगन्दास मास्टर रोड, बस्बई-23 इसके स्थित बेतन कार्यालय सहित नामक स्थापन के गम्बद्ध नियोजक भीर कर्मचारियों की बंहुतंत्र्या इस बात पर गतमत हो गई है कि कर्मचारी भिष्ठप्य निधि श्रीर प्रकीर्ण उपबंध श्रीविन्यम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने नाहिए,

ब्रून केन्द्रीय संस्थार, उक्त श्रधिनियम की धारा 1 की उपध्वस (4) द्वारा प्रवत्त शक्षित्यं। का प्रयोग करने हुए उक्त श्रधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[मं॰एम-35019(35)/84-पी एफ-[1]

S.O. 890.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as messrs Allied Chemicals & Pharmaceuticals Private Limited, Babuji Ka Bagh. Station Road, Jaipur-6, Rajasthan including its Registered Office at Desh Bandhu Gupta Road, New Delhi-55 and Pay Office at 612, Commerce House, 140, Nagindas Master Road, Bombay-23 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellancous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment,

INo. S-35019(35)/84-PF.III

कां श्रां 891.— केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पर्सनेल सर्विसेज सी-43, महाबीर मार्ग, सी स्कीम, ज्यपुर-1, राजस्थान नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक ध्रौर कर्मचारियों की बहुमंख्या इस बान पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि ध्रौर प्रकीर्ण उपबंध प्रिक्षित्यम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए.

श्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रिधिनियम की धारा 1 की उपधारा (1) द्वारा प्रदन्त प्रिनियम के उपधिष्ठ करते हुए उक्त श्रिधिनियम के उपधिष्ठ उक्त स्थापन की लाग करती है।

[र्स॰ एस-35019(32)/84-पी एफ-II]

S.O. 891.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Personnel Services, C-43, Mahaveer Marg, C-Scheme, Jaipur-1, Rajasthan have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(32)/84-PF.II]

कार्थ्या 892--केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स फाउन टाकीज, पोस्ट बाक्स नं 49, काकीनाडा-1, ध्रान्ध्र प्रदेश नामक रथापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध **नियम**, 1952 (1952 को 19)_] के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

श्रतः केत्म्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदन्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त श्रधितियम के उपजन्ध उक्त स्थापन को लाग करती है।

[सं॰ एस॰ 35019(31)/8 1-पी एफ-II]

S.O. 892.—Whereas it: ppears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Crown Talkies, Post Box No. 49, Kakinada-1 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019 (31) /84-PF. II]

का० प्रात 893.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतील होता है कि मैसर्स रेडीएस्ट इण्डस्ट्रीअ, बी-7, आई डी ए जीडीसेतला, हैंदराबाद-500854, आन्ध्र प्रदेश, तासक स्थापन के सस्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपवन्ध्र द्राधिनियम, 1952 (1952का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन की लाग किए जाने चाहिएं,

श्रमः केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रिधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रवत्त णिक्तयों का प्रयोग करने क्रुए उक्त श्रिधिनियम के उपबंध उका स्थापन की लागू करती है।

सिंव्यम-35019(34)/84 पीव्यक्त-H}

S.O. 893.—Whoreas it appears to the Central Government that the employers and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Radiant Industries, B-7, I. D. A. Jecdimetla, Hyderabad-500854, Andhra Pradesh have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. 35019 (34)/84-PF, II]

कार्जार 894.—नेन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सरत जन्द्र मोहापाला, ई 1, एन ए सी रटाफ क्वार्टर्स; शक्ति नगर, रूरकेला-769018, जिला मुन्दरगढ़, उडीमा नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मेजारियों की यहूसंख्या इस यात पर महमत हो गई है कि कर्मजारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध शिधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं,

श्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रिधिनियम की धारा । की उपद्याना (4) द्वारा प्रकल शक्तियों का प्रयोग करते उक्त दृष्, श्रिधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लाग करतः है।

[सं० एम०-35019(37)/84 पी०एफ०-II]

S.O. 894.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to

the establishment known as Messrs Sarat Chandra Mohapatra, E/1, N.A.C. Staff Quarters, Shakti Nagar, Rourkela-769018, Sundergarh District, Orrissa have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment,

[No. S-35019(34)]84-PF. II]

का०था० 89.5. — केश्रीय वरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसमें श्री लीला महल , पी. बी. नं० 309, तिकंधमपट विजयवाड़ा- 520002 धान्ध्र प्रवेण नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक कर्मचारियों की बहुंसंख्या की इस बात पर सडमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि धीर प्रकीण उपबंध प्रधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उत्तर स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं,

चतः केन्द्रीय मरकार, उक्त ध्रिक्षियम की धारा 1 की उपधारा (४) इत्तरा प्रदस्त मक्तियों का प्रधीन केरण हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन की लागु करती है।

[र्सं० एस-35019(36)/84/पी० एक०-II]

S.O. 895.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messs Sri Leela Mahal, P.B. No. 309, Buckinghapet, Vijayawada-520002, Andhra Pradesh have agreed that the provisions of he Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(36)/84-PF. II]

का०आ० 896. — केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता हैं। कि मेसर्स बी० एण्ड पी० स्विचरोग्नर, 49 आई० डी० ए० बालानगर हैंदरानाद-500037 आस्थ्र प्रदेश नामक स्थापन के लस्बद्ध नियोजक और उत्मेचारियों की शहुंमच्या इस बात पर सहमत हो गई हैं कि कर्माचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952(1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन की लागू किए जाने चाहिए,

भ्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की (उपधारा 4) द्वारा प्रवस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागु करती है।

[सं एस-35019(30)/84/पी० एक०-11]

S.O. 896.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs B & P Switchgear, 49, I.D.A. Balanagar, Hyderabad-500037, Andhra Pradesh have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therfore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said. Act to the said establishment,

[No. S-35019(30)/84-PF. II]

नई दिल्ली, 5 मार्च, 1984

का. अा. 897.—मैंसर्स कुमोदाम, 151, पुरासावलकम हाई रोड, मद्रास-600010 (तिमल नाड्र्-/3513). (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उकत स्थापन वो कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामु-हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके एक्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अन्हें अनुक्रिय हैं;

अतः केन्द्रीय गरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिध्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन की तीग वर्ष की अविध के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

- 1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त तिमलनाड को ऐसी विदरिणयां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरिणयों का प्रस्तृत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामृहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अचुवाद, स्थापन के सूचना-गट्ट पर प्रदिश्चित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त िकसी स्थापन की भिष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियो- जित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बावत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदस्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं, तो नियोजक साम्हिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में सम्चित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए साम्हिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदें उन

फायदो से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

- 7. सामूहिक वीमा स्कीम मं किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यू पर इस स्कीम के अधीन संदेय रक्षम उस रक्षम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निदेशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रक्षमों के अन्तर के बराबर रक्षम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहिक वीमा स्कींस के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, किमलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्रचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने स पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यिकत-पृक्त अदसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीवा विगम की उन सामृहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस रकीम के अधीन कर्मचारियों की प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश, निजोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को न्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निदेशितयों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उकत स्क्रीम के अन्दर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस त्कीम कें अधीन आने वाले किसी सर्वस्य की मृत्य होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितयों/विधिक वारिसों को वीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दक्षा में भारतीय जीवन बीमा निगम से वीमाकृत रकप प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/32/84-पी एफ-2]

New Delhi, the 5th March, 1984

S.O. 897.—Whereas Messrs Kumodam, 151, Purasawalkam High Road, Madras-600010 (TN/3513) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (here nafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the imployees Deposit-Linked Insurance Scheme. 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to

the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payments of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nomince of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the merest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any roason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance S heme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibilities for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of de-cased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

· [No. S. 35014(32)/84-PF. II]

का. आ. १९८. — मैं र्म्स पार्गदर्शी चिट फण्ड प्राईवेट लिमि-टेड, अधिड सेन्टर, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश/3527), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के, अधीन छूट दिए जाने के. लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का रामाधान हो गया है कि जकत निर्माणन के कर्षचारी, दिल्मी पृथक अदिद्धान या प्रीमियम का निर्मय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निर्मय की सामू- हिंद्र वीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिस इसमें इसके परुचात उक्त स्कीम कहा गया है) के उपीन उन्हें अनुजोय हैं;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शिंधतयों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपावस अनुसूची में विनिविष्ट शतों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अविध के लिए उक्त स्थीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुस्ची

- 1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोषक प्रादेशिक भीवष्य निधि आयुक्त, आंध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजींग और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो कन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. साम्हिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विधरणियों का प्रस्तृत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहुन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. निर्मोण क, केन्स्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक भीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें मंशोधन किया जाए, तब उस मंशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुमंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन बी भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित

किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक स्कीम के सदस्य के रूप मे उसका नाम तुरत्त दर्ज करेगा और उसकी वाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को मंदत्त करेगा ।

- 6. यदि स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समूचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामू- हिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्स स्कीम के अधीन अनुकूल हों, जो उक्स स्कीम के अधीन अनुकूल हों,
- 7. सामृहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी,
 यिव किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय
 रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय
 होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक
 कर्मचारी के विधिक बारिस/नाम निर्देशित को प्रतिकर
 के एय में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय
 करेगा।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भिवष्य निधि आयुक्त, आंध्र प्रदेश के पूर्व अनुमौदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्भचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भिवष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तिण्यक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामृहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना जुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले कायवे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रदद की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीय के भीतर, जो भारतीय जीवन बीगा निगम नियत करें, प्रीमियम् का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिदेंशितियों या विधिक वारिमों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उकत स्कीम के अन्तर्गत होतं, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदाधित्व नियोजक पर होगा ।
- 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यू होने पर उसके हकदार नाम नियेपितियों/विधिक बारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तराता से और प्रत्यंक दक्षा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिध्चित करेगा।

[सं. एस.-35014 (36)/84-पीएफ-2]

S.O. 898.—Whereas Messrs Margadarsi Chit Fund Private Limited, Abid Centre, Hyderabad (AP/3527) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment arc, without making any

separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to legal heir|nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal helps of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014/36/84-P. F. II]

का. आ. 899.—मैंसर्य उत्तर बांगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बंगचत्रा रोड, डाकघर पी. एस. एण्ड ज़िला कोचलेहार, एिइनमी बंगाल (पिइनमी बंगाल/16506), (जिसे इसमें इसके पइनात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपवंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पइनात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपभारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

अरेर केन्द्रीय गरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संवाय किए बिना हो, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहगद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुक्षेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाध्य अनुसूची में विभिन्निकेट शतीं के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अविध के लिए उक्त स्कीम के सभी उपाध्यों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

- 1. जकत स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रावेशिक भिविष्य निधि बायुवत, पिन्चसी बंगाल की ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए सुविधाए प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्विष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम की समाप्ति हो 15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय गरकार, उक्त अधिनियम की भारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. साम्हिक तीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना जिन्दणियों द्या प्रम्तुत किया जाना, शीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक नीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मधारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य नातों का अनुवाद, स्थापन के सुधन-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- यदि कोई ऐसा कर्मचारी, औं कर्मचारी भविष्य निधि का या तवन अधिनियम के अपीन छट भाषा किसी स्थापन की

- भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक, नाम्हिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आव-स्यक प्रीसियम भारतीय जीवन बीमा निषम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि उन्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फाउदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामृहिक बीका स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समृचित रूप से वृद्धि की जाने की ध्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकृत हों, जो उदत्त स्कीम के अधीन अनुक्रेय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में िकसी बात के होते हुए भी, यदि िकसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दक्षा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मबारी के विधिक वारिम/नाम-निदंधिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के नराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. नामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त परिचम बंगाल के पूर्व अनुमोदन है बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्म-चारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां, प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवक, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामृहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने बाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवहा, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा मकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी ज्यितिकम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम-निवेधितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती को उकत स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायवों के संदाय का उत्तर-दायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उधत स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यू होने पर उसके हकदार नाम-निदेशिशातियों/विश्विक वारिसों को नीमाकृत 'रकम का मंदाय सत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन नीमा निगम से नीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिद्यित करेगा।

[सं. एस-35014(37)/84-पीएफ-2]

S.O. 899.—Whereas Messrs Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, Bangchatra Road, P.O. P.S. and district Cochlehar West Bengal (WB/16506) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bangal, Maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc, within the due date, as fixed by the Life

Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(37)/84-P.F. II]

का. आ. 900. — मैंसर्स श्री गोपालकृष्ण मिल्म (यूनिट-3) पो. बाक्स नं. 2052, गणपति पोस्ट, कोयम्बतूर-641006 (तिमल नाडुं/12420). (जिसे इसमें इसके पहचात् उक्त स्थापन कहा है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पहचात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का नदाय किए बिना हो, भारतीय जीवन बीमा निगम की साम्हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फयदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1978 (जिसे इसमें इगडे पहचात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुक्रेय है

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रवत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अभीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन धर्ष की अविध के लिए उक्त स्कीम के सभी उपाबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

जनसची

- उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रावेशिक भविष्य िविध आयुक्त निमाननाष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी स्विधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 2. निर्माजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समारित के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार. उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्विष्ट करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरिणयों का प्रस्तृत किया जाना, वीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहुन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।
- 4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित साम्-हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें मंशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बानों का अनुवाद, स्थापन के मुचना-पट्ट पर प्रविश्वित करेगा।

- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भिष्ठिय निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भिष्ठिय निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियो-जित किया जाता है तो, नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के राटस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा स्थिगम को मंदत्त बरेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समूचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अग्कुल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुजये हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में िकसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नोम निवेधिती को प्रतिकर के रूप में दोने रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. साम्हिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तिमलनाडू के पूर्व अनुमोवन के यिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संगावना हो वहीं, प्रावेशिक भविष्य रिधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दिष्टकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।
- 9. यदि किसी कारणवदा, स्थापन के कर्मधानी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामृहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना ध्का है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मधारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं; तो यह रदद की जा सकती है।
- 10. यदि किमी कारणवश, नियोजक उम नियत तारील के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा नियम नियत करे, प्रीमि-यम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यापसत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रदद की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी क्यतिक्रम की दक्षा में, उन मृत स्दस्यों के नामनिदेशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तर-दायित्य नियोजक पर होगा ।
- 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यू होने पर उसके हकदार नामिनिदें चितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता में और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सृनिध्चित करेगा।

[संख्या एस-35014(40)/84-पी. एफ . -2]

S.O. 900.—Whereas Messrs Sri Gopalakrishna Mills (Unit. III) P.B. No. 2052, Ganapathy Post, Coimbatore-641006 (TN/12420) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) for section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscollaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees, of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of Indla in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenace of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount navable under this scheme be less than the amount that would be pavable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Instance. Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner Tamit Nedu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable apportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lanse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer +1 payment of premium the responsibility for payment 6'

assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure promot payment of the sum assured to the nominee/legul heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life insurance Corporation of India.

[No. \$-35014(40)|84-PF. II]

का अग ० १० 1. मीसर्स हिंद फिल्टर प्राइवेट लिं प्लाट मं १ए/८ए. इण्डस्ट्रीयल एरिया, आगरा, सम्बई रोड, देवदास, मध्य प्रदेश (जिसे इसमें इमके परनात् उकत स्थापन कहा गया है) ने कमेंनारी भिवष्य विधि और प्रकीण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसमें परनात् उकत अधिनियम कहा गया है) की घारा 17 की उपधारा (2क) के अधीक छूट विए जाने के लिए अवियन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उन्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, मारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में कायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकृत हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबक्ष बीमा स्कीम 1976 (जिल्ले इसमें इसके पश्चात उन्त स्वकीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुक्षेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रवत्त सक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपायद्व अनुसूची में विनिर्विष्ट मतौं के अधंन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुगूची

- गः उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भाविष्य निधि अध्युक्त, मध्य प्रवेश को ऐसी विवरिणयां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा सथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्विष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 विन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समयसमय पर निर्दिष्ट करे।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायगा ।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कशी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचान्थिं की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सुखना पट पर प्रदणित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी मिवष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन सृष्ट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सबस्य हैं, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक, सामृहिक बीमा स्कीम के सबस्य के रूप में उसका नाम चुनल दर्ज करेगा और उसकी बाबन आवण्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संबद्ध करेगा।

- 6. यदि उनत स्कीम के अधीन कर्मवारियों को उपलब्ध पायदे वहाये जाते हैं तो, नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मवारियों को उपलब्ध फायबों में, समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मवारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो, जो उनत स्काम के अधीन अनुकेष हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दक्षा में संदेय होती, जब बहु उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस,नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनो रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामृहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संगोधन, प्रावेशिक भिष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संगोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना वृष्टिकोण स्पष्ट करने का पृक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मैचारी, भारतीय जीवन कीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मवारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं. तो यह रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत सारीख के भीनर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का सदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययपगत हो जाने विया जाता है तो छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी ब्यतिकम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विश्विक बासिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, नीमा फायदों के संवाय का उस्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सबस्य की भृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/ विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सास दिन के भीतर सुनिध्यत करेगा।

[संख्या एस-35014/67/80-पी०एफ० 2]

S.O. 901.—Whereas Messrs Hind Filter Private Limited, Plot No. 1A/8A, Industrial Area, Agra Bombay Road, Dewas, Madhya Pradesh (hereinafter referred to as the said establ shment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme):

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto,

the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner. Madhya Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[Ne S. 35014(67)/80-PF. III

का. अ. 9902. — मैसर्स स्टैप्डर बारगानिक्स लिमिटेड, 6-3-348, ''सलोपिया, द्वारूकापूरी कोलोनी, हैदराबाद-500004 (बांध्र प्रदेश/12862), (डिंबर इसमें इसके परचात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मधारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपन्ध्र अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके परचात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उनत स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभवाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन नीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन नीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये में फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी मिक्षेप सहस्द्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके परचात् उन्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुहोय हैं;

भतः भेन्द्रीय सर्थनार, उत्तत अधिनियम की घारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रवेश प्राप्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपासक्ष अनुसूची में विभिविष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापक को सीम वर्ष की अधीन रहते हुए, उक्त स्थापक को सीम वर्ष की अधीन है।

अनुसूची

- 1. उक्त स्थापम के संबंध में नियोजक प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्र प्रवेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा र खेगा तथा निरोक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रवास करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निविष्ट करें।
- 2. नियोजन, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 विम के भीतर संवाय करेगा जो केस्क्रीम सरकार, उकत अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्विष्ट करे।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासक में, जिसके अन्तगत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जामा बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने बाले सभी व्ययों का बहुत नियोजक द्वारा किया जायेगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए सब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बासों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रवित्ति करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या जन्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सबस्य है, उसके स्थापन में नियाजित किया जाता है तो, नियोजक; सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम जुश्नत दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा कियम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि उनत स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ायें जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से सृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारीयों के लिए सामूहिक योगा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुनेय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्तीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अशीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस देशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक बादिस/नामनिर्देशिती

का प्रतिसद के इन्हें में दोनों एउपों के अन्तर के बराबर एकम का संवाय करेगा।

- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उत्पन्धों में कोई भी संगोधन प्रादेशिक भविष्य निश्चि आयुक्त, आन्द्र प्रवेश के पूर्व अनुमादन के बिना नहीं किया आएना और जहां कियों। संशाधन से कर्मवारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने का संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दुष्टिकाण स्पष्ट करने का मृतितयुक्त अयमर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवा, स्थापन के कर्मवारों, भारतीय जीवन सीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्वीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन महीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मवारियों की प्राप्त हीने वाले फायदे किसी रोति से कम हो जाते हैं; तो यह रह की जा सकी है।
- 10. यदि किसी कारणवश नियाजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवम बीमा निगम नियत करे, प्रोमियम का संवाय करने में असकल रहता है, और पालिसी को स्थपनत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियाजक द्वारा प्रीमिथम के सवाय में किए गए किसी व्यक्तिक की वसा में, उन मृत सहस्यों के नामनिर्देशितियों या विभिक्त वारिसों को जा यदि यह छूट में वी गई होती सो उन्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संवाय का उत्तरवाशिक नियोजक पर होगा।
- 12. उनत स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने बात किसी सदस्य की मृत्यू होने पर उसके हकदार भागिवर्षीयितयों/ विधिक वारिसों को बीमाक्षत रकम का संवाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा जिल्ल से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात विन के भीतर मुनिधिवत करेगा।

सिं० एस०-35014/20/84-पा॰ एफ॰-2]

S.O. 902.—Whereas Messrs Standard Organics Limited, 6-3-348, "Salopia, Dwrukapuri Colony, Hyderabad-500004 (AP/12862) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Incurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of

- accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of In ha as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer falls to ray the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of decessed members who would have been covered under the aid Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(20)/84-PF.II]

का. आ. 903.—मैंसर्स जेट एयर ट्रांसपोर्ट शन प्रा. लि., 199, जि. टाटा रोड, चर्चगेट, अध्यई-400020 (महाराष्ट्र/19769). (जिसे इसमें इसके पर्जात उक्त स्थानन कहा गया है) ने कर्मचारी अधिकार निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पर्चात उक्त अधिनियम, कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के बधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय शरकार का समाधाल ही गया है कि उक्त स्थापन के कर्मेचारी, किसी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का संवाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन भीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे उस फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहसद दीमा स्काम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उसत स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुजेय हैं;

अतः केन्द्रांस सरकार, उक्त अधिक्यम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त मांभतयों का प्रयोग करते हुए और इससे उपावद्य अनुसूची में विकिदिष्ट मतौं के अधीर रहते हुए, उक्त स्थापन की तीन वर्ष की अर्थाध के लिए उक्त स्कीम के सभी उपवन्धों के प्रवर्तन से छूट देता है।

अनुसूची

- उसत स्थापन के संबंध में नियोजक प्रावेशिक सविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र का ऐसी विवरणिया भेजेगा और ऐसा संख्या रखेगा सथा निराक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा को केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करें।
- 2. नियंजिक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रश्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भातर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उनते अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (अक) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निविद्य करे।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रणासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवर्णियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय लेखाओं का अन्तरण, निरोक्षण प्रभारों का संवाय आवि भी है, होने बाल सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियंजिक, केन्द्राय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमां स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मबारियों की बहुर्सब्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सुबना पेट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यांच काई ऐसा कर्मकारी, जो कर्मकारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनयम के अधीन छूट भाष किसी स्थापन को भविष्य निधि का वहने ही सबस्य है, उसके स्थापन में नियाजित किया जाता है तो, नियाजिक, सामूहिक बीमा स्कीम के सबस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा भाषा को संबक्त करेगा।
- 6. याद उक्त स्काम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो लियांजरु तामृहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुक्षेय हैं।
- 7. सामृष्टिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय एकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्वेशिसी की प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के वरावर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संगोधन, प्रादेशिक मिवल्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाए गा और अहां किसी संशोधन से कर्मनारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की स्मायना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मनारियों को अपना वृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- यदि किसी कारणवण, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन शीमा निगम की उस सामृहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहुले भ्रपना

- चुका है, ग्राधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के ग्राधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने घाले फायदे किसी रीतिसे कम हो जाते हैं; तो यह एक्ट की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवण, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में मसफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रह की जा सकती है।
- 11. िमयोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी व्यक्तिकम की वंशा में, उन मृत सवस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न वी गई होती तो उक्त स्कीम के प्रन्तर्गत होते, बीमा फायवों के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12 उन्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के श्रधीन धाने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकुत रकम का संवाय सत्परता से भौर प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/22/84-पी एफ-2]

S.O. 903.—Whereas Messrs Jet-Air Transportation Private Limited, 199, J. Tata Road, Churchgate, Bombay-400020 (MH/19769) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of Iudia in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corportion of India.

- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nomince of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc, within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer,
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(22)/84-PF, II]

का. आ. 904. — मैंसर्स मानेकलाल हरीलाल मिल्स लिमि-टेड, सारसपुर, अहमदाबाद-380018 (गुजरात/308), (जिसे इसमें इसके एडचात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके परचात् उक्त ऑधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

भौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक भिन्दाय या प्रीपृत्तिम्म का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के भ्रधीन जीवन बीमा के रूप में फायरे उठा एड़े हैं भीर ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायरे उन फायरों से अधिक भ्रनुकृत हैं जो कर्मचारी निक्षेप महस्रक धीमा स्कीम, 1976 (जिमे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के भ्रधीन उन्हें भ्रनुक्रय हैं;

श्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्तं भिधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रवत्त सक्तियों का प्रयोग करते हुए भीर इससे उपावद्ध मनुसूची में विनिधिष्ट सतीं के सधीन रहते हुए, उक्त स्थापन की तीन क्यें की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती हैं।

धनुसूची

 उनत स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भिष्य निधि ग्रायुक्त, गुजरात को ऐसी विवर्णियां भेजेगा ग्रीर ऐसे लेखा रखेगा

- तथा निरोक्षण के लिए ऐसी सुविद्याएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 विन के भीतर संबाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के प्रधीन समय-समय पर निविष्ट करे।
- 3. मामूहिक बीमा स्कीम के प्रणासन में, जिसके प्रन्तर्गत लेखायों का रखा जाना विवर्णियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखायों का प्रन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय प्रादि भी है, होने बाले सभी व्ययों का बहुन नियोजक द्वारा किया जायगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा ध्रनुमोदिन सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, भीर जब कभी उनमें संगोधन किया जाए, सब उस संगोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के मुखना पट्ट पर प्रविशत करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के प्रधीन कर्मवारियों को उपलब्ध फायवे बढ़ाये जाते हैं, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायवों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन उपलब्ध फायवे उन फायवों से प्रधिक धनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के प्रधीन धनुजेय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृह्यू पर इस स्कीम के प्रधीन संदेग रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उकत स्कीम के प्रधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिस/नामनिर्वेशिसी को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के प्रस्तर के बराबर रकम का संवाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त, गुजरात के पूर्व श्रनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृष प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रावेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त, श्रपना श्रनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को श्रपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त श्रवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवण, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अश्रीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है; तो यह रह की जा सकती हैं।
- 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियन तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियन करे, प्रीमियम का संदाय करने में ग्रसफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है, तो छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी व्यक्तित्रम की दणा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्वेणितियों या विधिक नारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के ग्रन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायिख नियोजक पर होगा।
- 12. उसत स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के झधीन धाने वाले किसी सबस्य की मृत्यू होने पर असके हकदार नामनिर्देशितियों/

विधिक वारिसों को बीमाइन्त रकम का संदाय करता है सत्परता से भीर प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाइन्त_रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिधिचत करेगा।

[संस्था एस-35014(21)/84-पी. एक. 2]

S.O. 904.—Whereas Messrs Mancklal Harilal Mills Limited, Saraspur, Ahmedabad-380018 (GJ/308) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat

- and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shalf before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. 5. 35014(21) /84-PF-II]

का. आ. 905.— मैंसर्स अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संध लिमिटेड, अजमेर, (राजस्थान/1788) (जिसे इसमें इसके प्रचात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निश्चि और प्रकीर्ण उपनन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके परचात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट विए जाने के लिए आबेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पथक अभिवायी या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामृहिक बीमा स्कीम के बधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्म-चारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1978 (जिसे इसमें इसके पहचात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

जतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2क) द्वारा प्रवत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शती के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अविधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उप-वन्धों के प्रवर्तन से सूट देती हैं ए

अन्स्ची

- 1. उक्त स्थापन को संबंध में नियोजक प्रावेशिक भाविष्य निधि बायुक्त, राजस्थान को ऐसी बिवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाएं प्रवान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निविध्य करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय गरकार, उक्त दिश्शिनयम की धारा 17 की उपधारा (3क) के सण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- साम्हिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लैकाओं का रका जामा विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय, लेकाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का

संदाय आदि भी है, होने बाले सभी ध्ययों का वहन नियोजक इतरा किया जाएगा।

- 4. नियोजक, केन्द्रींय सरकार द्वारा अनुमोदित सामृहिक स्कीम के नियमों की एक प्रति, जौर षब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मृख्य बातों का बनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उनत अधिनियम के कधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है सो, नियोजिक, सामृहिक बीमा स्कीम के संवाय के रूप में उसका नाम तुरन्त वर्ज करेगा और उसकी बाबत आवस्यक प्रीमियम मारनीय जीवन बीमा नियम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि उस्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ायं जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समूचित रूप से बृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिस सेकि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुकोय हैं।
- 7. सामृहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यू पर इस स्कीम के अधीन संदेय रक्षम उस रक्षम से कम है जो कर्मचारी को उस दहा में संदेय होती, जल वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक धारिस/नामनिवे किती को प्रतिकर के रूप में बोनों रक्षमों के बन्तर के बराबर रक्षम का संदाय करेगा।
- 8. सामृहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हिल पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो नहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना वृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी क'रणवहा, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा ितगम की उस सामृहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना खुका है अभीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रदद की जा सकती है।
- 10. यांध किसी कारणवहा, नियोजक उस नियस तारीस के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियस करे, प्रीमियम का संदीय करने में अगफल रहता है, और पालिसी को व्यवस्थत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रदद की जा सकती है।
- 11. नियोजक ब्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिकाम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिवे शितायों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उकत स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संवाय का उत्तर-दायित्व नियोजक पर होगा ।
- 12. उका स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यू होने पर उसके हकवार नामनिदेशितयों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संवाय सत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा

निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात विन के भीतर सर्भिष्टियत करेगा ।

[संख्या एस-35014(23)/84-पी.एफ. 2]

S.O. 905.—Whereas Mcssrs Ajmer Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Limited, Ajmer, (RJ/1788) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2Λ) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Comm scionar, Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the in-

interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(23)/84-PF-II]

का. आ. 906. — मैंसर्स टैक्सटूल कम्पनी लिमिटेड, गणपती, कोयम्बसूर-641006 (तिमलनाडू/77) जिसे इसमें इसके परचात् उक्त स्थापन कहा गया हैं) में कर्मचारी शिवच्य जिन्नि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके परचात् उक्त अधिनियम कहा गया हैं) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया हैं;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मधारी, किसी पृथंक अभिवाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मधारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मधारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिस इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनक्तेय हैं;

अत: केन्द्रीय सरकार, जुक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदस्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्धिष्ट शतों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अन सम्बी:

- 1. उक्त स्थापन के मंबंध में नियोजक प्रादेशिक भिष्ठिय निधि आयुक्त, तिमल गाड को ऐसी विवरणिया भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सृविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय मरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो कंन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तृत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण

प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

- 4. नियोजक, कंन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामृहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संघोधन किया जाए, तब उस संघोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मृख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदिश्वित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सवस्य है, जसके स्थापन में नियोजिक किया जाता है तो, नियोजिक, सामृहिक बीगा स्कीम के सवस्य के रूप में उसका गाम तुरता दर्ज करेगा और उसकी बाबत आदश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ायं जाते हैं तो, नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समृचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकृत हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुक्रेय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जग वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिस/नामिवदेशिती को प्रतिक्षर के रूप में दोगों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीवा क्लीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रावेशिक सिविष्य तिथि अयुक्त सामिल नाडू के पूर्व अनुमोदन के जिना कहीं किया जाएगा और कहां किसी संशोधन से कमंचारियों के हिन पर प्रतिकूल प्रभाव पढ़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य गिशि आयुक्त, अपना अनुमोदक देने से पूर्व कमंचा श्यों को अपना दृष्टिकोण स्पब्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवार, स्थापन के कर्मचारी भारतिय जिह्न वीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना भुका है अधीन नही रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों की प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं; तो यह रह की जा सकसी है।
- 10. यदि किसी कारणवर्षा नियातक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संवाय करने में असकल रहता है और पालिसी को व्ययनत हो जाने दिया जाता है, तो छूट रह की जा सकती है।
- 11. त्रियोगक हारा प्रोमियम के संवाय में किए गए किसी व्यक्तिक की दथा में उन मृत सबस्यों के नामानर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न वी गई होती सो उनत स्कीम के अन्तर्गत होते, दिश्मा फायुदों के संवाय का उत्तरवायित्य नियोजक पर होगा।
- 12. उमत स्थापन के संबंध में नियां तक इस स्कीम के अधीक आने याले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उन्नके हक्षदार नामानर्देशितियों विधिक वाश्मिं की बीमाकृत एकम का संवाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारताथ जीवन बीमा नियम से बीमाकृत एकम प्राप्त होने के सात विन के भीतर मुनिध्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/25/84-पी ०एफ० 2]

S.O. 906.—Whereas Messis Textool Company Limited, Ganapathy, Colmbatore-641006 (TN/77) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner. Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view. 1515 GI/83—9

- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(254)]84-PF-II]

का आ. 907 — मैसर्स भीलवाड़ा सैन्थेटिक्स लिमि-टेड, भीलवाड़ा (राजस्थान/1681) (जिसे इसमें इसके एरचात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके परचात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आदेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का ममाधान हो गया है कि उकत स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए विभा ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा निगम की सामृहिक बीमा स्कीम के रूप में कायदे उठा रहे हैं ऐसे कर्मचारियों के लिए ये कायदे उन कायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निश्चेष भहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुक्षेय हैं;

अतः कैन्द्रीय सरकार उन्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रवल शक्तियों का प्रयोग करने हुए और इससे उपावक अनुमूकी में विभिविष्ट शहीं के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अधि के लिए उन्त स्कीम के सभी उपपंत्रों के प्रवर्तन से छूट देसी है।

अनुसूची

- 1. उक्त स्थापन के त्संबंध में नियोजक प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान को ऐसी वियरिणयां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रिय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 2. नियोजक ऐसे मिरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उकत अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निविष्ट करे।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बोमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों सेंदाय आदि भी है होते वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

- 4. लियाजक केन्द्रीय राष्ट्रकार अग्रुपादित सामूहिक बीता रक्षाम के लियमा और एक प्रति और जब कभी उपम संशोधन किया आए तथ उस संशोधन की प्रति तथा कर्मणास्थि की बहुसंख्या के भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुबुद्ध स्थापन के सुधना-यह पर प्रविशत करेगा।
- 5. यदि : कांद्र ऐसा कमेवारी वो कर्मधारी भविष्य निधि का या उन्त अधिनिथम के अधीन छुट प्राप्त किसो स्थापम को भविष्य निधि का पहले ही स्थरस्य है उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक वीमा स्कीम के मदस्य के रूप में उसका माम तुरत्व दर्भ करेगा। और उसकी बावत आयश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा नियम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि उदत स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध फायर वहायें जाते हैं तो नियोजय सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मधारियों को उपलब्ध फायरों में संमुखित रूप में बृद्धिकी जाने की व्यवस्था करेंगा जिनसे कि कर्मधारियों के लिए सामृहिक बीमा रकीम की अर्धान उपलब्ध फायरें उन फायरों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अमुलेय है।
- 7. सामूहित भीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी वर्मचारी की मृत्यु पर इस रकोम के अधीत संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दबा में संदेय होती जब यह उकत स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिस का नियोंशिकों का प्रतिकर के रूप में योगी रकमीं के अन्तर के बगबर रकम का मंद्राय करेगा।
- स. सामृहिक बीमा स्कीम के उपकंशों में तोई मं। संगोधन प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त तामिलनाडू के पूर्व अनुमोदन के विमा मही किया जाएगा और जहां किसी संगीधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना ही यहां प्रावेशिक भविष्य निधि अयुक्त अपना अनुमीदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवगर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवण, स्थापन के कर्मचारी, मास्तीय जीवन बीमा निगम की उस नामूहिक बीमा स्काम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहां रह जाते हैं, या इस स्काम के अधीन कर्मचा स्थों का प्राप्त हार्द बाल फायदे किसी रीति में कम हो जाते हैं; सो यह रह की जासवति? है।
- 10 यदि किमी कारणवण, नियोजक उस नियत तारोख के भीतर, जो भारतीय जीवम बीमा मिगम नियत करे, प्रीमियम का संदाद करने में अंगफल, इहना है, और पालिसी को व्यपगम हो जाने दिया जाता है तो छूट रहे की जा सकती है।
- 11. क्षेयोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में बिए गए कियो व्यक्तिप्रम की दशा में उन मृत छदस्यों के नामिविशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दो गई होतो तो उनत स्काम के अन्तर्गत होतें श्रीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्य नियोजक पर होगा।
- 12. उनन स्थापम के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अक्षीम आने बालें किसी भदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार मामनिर्देणितियों/विधिक बारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता ने और प्रत्येक यणा में भारतीय जीवन भीमा नियम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिष्चित करेगा।

[मॅठपा एस- 15 014:27/84-पी अपकार हो

S.O. 907.—Whereas Messis Bhilwara Synthetics Lamifed, Bhilwara (RJ/1681) (thereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A), of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHFDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, Submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be home by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Lite Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nomince/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(27)/84-PF-II]

, का. आ. 908. — मैंसर्म राजम्थान लिण्ड डेबलेपमेण्ट फापों-रेशन', 3-खेतक मार्ग, जयप्र (राजम्थान/2487) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहां गया है) ने कर्मचारी शिष्टिण निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनिष्यम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनिष्यम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

बौर केस्त्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीम। निगम की मामृहिक बीम। स्कीम के अधीम जीवन बीमा के रूप में फीयबे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे जन फायदों में अधिक अनुकूल हैं जो कर्मच्येरी निक्षेप सहग्रह दीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पण्वात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुक्य है;

अतः केन्द्रीय संस्कार, उक्त अधिनियम की धारी 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपावख अनुसूची में धिनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देनी है।

अनुसूची

- उन्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्राविशक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान को ऐसी विवरणिया भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुविद्याएं प्रवान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निरिष्ट करे।
- 3. मामृहिक बीमा स्कीम के प्रणासन में, जिसके अन्तर्गत नेश्वाओं का रखा जाना विवर्गणयों का प्रस्तुन किया जाना, वींमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहुन नियोगक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोगक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामृहिक बीसा स्क्रीम के नियमो की एक प्रति और जब कभी उनमें मंगोधन किया जाए तव' उस संगोधन की प्रति तथी गर्मचारियों की यहसंख्या की भाषा में उसकी मृख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रविशत करेगा।
- 5. यदि काई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की अधिष्य निधि का पहले ही, सदम्य है, उसके स्थापन में निधौजिन किया जाता है तो, नियोजक, सामृहिक बीमा स्कीम के नदस्य के रूप में उसका नाम नुरुत्त दर्ज करेगा और उसकी बाबन आविष्यक प्रीस्थिम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यवि उत्तन स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे वकाय जाते हैं तो, नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में सम्चित रूप में वृद्धि की जाने की अवस्था करेगा जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकृत हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अपूजिय हैं।
- 7. सामहित बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यू पर इस स्कीम के अधीन सन्त्य रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दणा में संदेथ होती, जब यह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियाजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामिन-विशिती को प्रतिकर के रूप में दानों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संवाय करेगा।
- 8. सामृहिक वीम। स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संबोधन, प्रावेणिक प्रावित्य निधि आधुक्त, राजस्थान दिल्ली के पूर्व अनुसोदन के बिना नहीं किया आएगा और जहां किसी संबोधन से कर्मचारियों के हिंत पर प्रतिकत

प्रभाव पड़ने की संनावना हो बतां, प्रावेशिक भविष्य निश्चि आयुक्त, अपना अनुभोवत देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना वृष्टिकांण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

- 9. यदि किसी कारणवण, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन वीमा निगम की उस सामूहिक वीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहुं अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इम स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं; तो यह रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश, नियाजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, खुट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिक की दशा में, उन मूत्तसदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों की श्री यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, श्रीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने काले किसी सदस्य की मृत्य हीचे पर ज्याके हुकवार नामनिर्देशितियों/विधिक बारिसों भी बीमाक्रत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय किया निका किया में भारतीय किया निका किया के सीमाक्रत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सनिष्यम करेगा !

[संस्वा एस 35014(28)/84-पी० एफ०·2]

ए०के० भट्टराई, अवर सचिव

S.O. 908.—Whereas Messts Rajasthan Land Development Corporation, 3 Chetak Marg, Jaipur (RJ/2487) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme):

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall may such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of

accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affect 'adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India

[No. S-35014 (28)/84-PF II]

A. K. BHATTARAI, Under Sccy.

नई दिल्ली, 5 माची, 1984

का. आ 909 — मैसर्स कृष्णा इंजीनियरिंग कंपनी प्रा लि., डी.आई.भेल, एन्सिलरी इण्डेस्ट्रियल एस्टेट, त्रिजी (तिमल नाड्र / 8268), (जिसे इसमें इसके पहचात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमे इसके पहचात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

जीर कंन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं, और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकृत हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुजेय हैं ;

इत: केन्द्रीय मरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिधिष्ट शती के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अविध के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनसची

- 1. जक्त स्थापन के संबंध मे नियोजक प्रावेशिक भविष्य निधि आयक्त, तिमलनाड को ऐसी विवरणियों भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी स्विधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निध्दिष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम की मगाप्ति के 15 दिन को भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के लण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तृत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संवाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का बहुन नियोजक बारा किया जाएगा ।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार ब्वारा अनुमोदित साम-हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधने किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सुचना-पट्ट पर प्रदिश्ति करेगा ।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भृद्रिष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भिविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक सामृहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी वाबत कावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा नियम को संदत्त करेगा ।
- 6. यदि उक्त रक्षीम के अधीन कर्मचारियों की उपक्रव्य फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के

- अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायवों में समूचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदें ये अधिक अनुकुल हो, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुकुल हो,
- 7. गामूहिक बीमा स्कीम में िकसी बात के होते हुए भी, यदि िकसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब दह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिस/नामनिदेशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों से अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त तिमल नाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां िकसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना वृष्टिकोण स्पष्ट करने का युवितयुक्त अवसर देगा ।
- 9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायवे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिकास की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिवें शितियों या विधिक वारिसों को जो., यदि यह छूट न दी गई होती तो उकत स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के मंदाय का उत्सरवायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यू होने पर उसके हकदार नामिन्दें शिनियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता में और प्रत्येक दक्षा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर गिनिश्चित करेगा ।

[सूर्क्या एस-35014/29/84-पी एफ. 2]

New Delhi, the 5th March, 1984

S.O. 909.—Whereas Messys Krishna Engineering Company Private Limited, D.I. BHEL, Ancillary Industrial Estate, Trichy, (TN/8268) (hereinnfter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952, (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act. within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of account, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the empoyees.
- 5. Whereas employe, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner. Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for rayment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for erant of this exemption, shall be that of the employer
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment

shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(29)/84-PF.II]

का. आ. 910 — मैसर्स डिन्डीगृल पोलीथीन कर्कस इण्ड-स्ट्रियल को-आपरेटिव सोसायदी लिमिटेड, (तिमिल बाड्र/6354), (जिसे इसमें इसके परचात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्म-चारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनयम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके परचात् उक्स अधिनयम कहा गया है) की धार 17 की उपधारा (११क) के अधीन छूट दिए जाने के किए आहेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का ममाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्रचारी, किसी पथक अभिदाय या प्रीमियमा का संदाय किए विना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सम्मूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं, और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक वनुक्त है जो करणारी निक्षेप महबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्वीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अग्रांय हैं;

जिल्लीय प्रकार, उभा अधिनियम की भारा 17 की उपधारा (2क) देवारा प्रदेश शिक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अन्सूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपवन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अन्स्चा

जबत स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भीवष्य निधि आणुक्त, तिमल नाडु को ऐसी विवरिणयां भेजेंगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं श्रादान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उकत अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. साम्हिक बीसा मकीम के प्रशासन में, जिसक अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्त्त किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों मंदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, बन्द्रीय संरकार द्वारा अन्मोदित साम्-हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संद्रोधन किया जन्म, तब उमा संद्रोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की कर्नेक्या की भागा में उनकी मुख्य बन्तों का अन्याद स्थापन के सचनानहरू एक निर्वाद होगा।
- पिंद दोई ऐसा दार्मच्यी, जो कर्मचारी भिष्टम निधि का पा उनत अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भिष्टम निधि का पहले ही बदस्य है, उसके स्थापम में निधो-जित किया जाता है तो, नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के मनाय के मण भें उसका लाग तप्त दर्ज करेगा और उसकी पावन पायस्थल प्रीमियम शास्तीय जीवन बीमा निग्न को संदत करेगा।

- 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलन्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, निगोचक सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समृचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अमुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अन्ज्य है।
- 7. साम्ब्रीहक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय रक्षम उस रक्षम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्क स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिदेशियों को प्रतिकर के एप में दोतों रक्षमों के अन्तर के बराबर रक्षम का संदेय करेगा।
- 8. सामृहिक बीमा स्कीम के उपत्न्थों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भाविष्य निर्मि आयुक्त तिमल न्नाड़ के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां िकसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव्य एड़ने की संभावन्ता हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निर्मि आयुक्त, अपना उन्गोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने को गविन्तप्रका अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवशः, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सम्मित्ति बीमा रकीम के, जिसे स्था-पन पहले अपना चका है अधीन नहीं रह जाते हैं, बा इस स्क्रीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कर हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीय के भीतर, जो भारतीय जीवन नीमा निगम नियत करे, श्रीमियस का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यवगत हो जाने दिया-जाना है तो छूट रद्द की जा मकती है :
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में िकए गए किसी व्यतिक्रम की द्वा में उन मत सदस्यों के नामनिदेशिकातियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उकत स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदीं के मंदाय का उत्तरदायिक नियोजक पर होगा।
- 12. उस्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीस के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्य होने पर उनके हकदार नामनिवें-शितियों/विधिक बारिसों को बीमाकृत रक्षम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से वीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर गुनिश्चित करेंगा।

[सं. एस-35014/31/84-पी.एफ. 2]

S.O. 910.—Whereas Messrs Dindigual Polythene Workers Industrial Co-operative Society Limited, (IN/6354) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscelaneous Provisions Act. 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of ludia in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Dorosit-Linked Insurance Scheme, 1976 (berain offer referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the \$chedule annexed hereto, the

Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of recounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, along with a translation of the salient features thereof, in the Innuage of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Funds or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6.The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. No withstanding anything contained in the Group Incurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable apportunity to the employees to exclain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reducd in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nonfines or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs emitted for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014 (31) /84-PF, II]

का. आ. 911.— गैंसर्स श्री शिक्त टैक्सटाईल्स लिप्पिटेड, मिल प्रेमेसेंस, कोयम्बतूर रोड, पो. इक्स नं. 36, पोलाची-642001 (तिमल नाडा/1167), (जिसे इसमें इसके परचाता उक्षारधापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपनस्थ अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके परचाता उक्ष्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदार किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं, और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकृत हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहस्त्व बीमा स्कीम, 1876 (जिसे इसमें इसके परचात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुक्रोय हैं;

क्षतः केन्द्रीय सरकार, उकत अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदल्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबक्त अनुसूची में विनिदिष्ट शतों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अविध के लिए उक्त स्थीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

- 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रावेशिक भविष्य निधि आपुष्त, तिमल नाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाए प्रवान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्विष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की ममाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उकत अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामृहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरिणयों का प्रस्तृत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का मंदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक बारा किया जाएगा ।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय मरकार द्वारा यथा अनुमोदित साम्-हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संसोधन किया जाए, तथ उस मंग्नोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी म्ख्य बातों का अन्दाद स्थापन के मुचना-पट्ट पर प्रविधान करेगा ।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियो-जित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्वीम के सदस्य के रूप में उसका शाम त्रल दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक ,प्रीमियम भारतीय जीवग बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समृचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के

िलाए माम्हिक बीमा रकीय के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुक्रय है।

- 7. गामृहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दक्षा में से देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो निष्पोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिदेशिती को प्रतिकर वे रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संबोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तिमल नाड़ के एवं अन्मोधन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां िकसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक अधिष्य निधि आयुक्त, अपना बन्मोधन देने से पूर्व कर्मचर्रियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामृहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रदद की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवर्ग, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रदद की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमिणम के संदाय में किए गए किमी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सबस्यों के नामनिवें शितियों पा विधिक वारिमों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।
- 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन जाने वाले किसी सदस्य की मृत्य होने पर उसके हकदार नामिनदें शितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर मनिष्टिचत करेगा।

[सं. एस-35014/30/84-पी.फ.2]

S.O. 911.—Whereas Messrs Sri Sakthi Textiles Limited, Mill Premises, Coimbatore Road, P.B. No. 36, Pollachi-642001 (TN/1167) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellangeous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees deposit-linked Insurace Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme):

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Funds Com-

missioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner. Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(6)]/84-PF.III

का. आ. 912.—गौमर्ग रन्तोकवा दर्लभजी मिमोरियल हास्पीटल, भवानी सिंह मार्ग, जयप्र (राजस्थान/1806), (जिसे हमके हमके प्रताता उदल स्थापन क्षता गया है) ने कर्मचारी भविष्य 1515 GI/83—10

निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके परचात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के निए अवेदन किया है;

और केन्द्रीय मरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामृहिष्ठ बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में कायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकृत हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके परचात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुजोय है;

अतः केन्द्रीय मरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2क) द्वारा प्रदत्त- शिक्तयों का प्रयोग करते हुए और हमसे उपाबज अनुमूची में विनिर्दिष्ट हातीं के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अयिध के लिए उक्त स्कीम के मभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसुची

- 1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रावेशिक भिष्ण निधि आयुक्त राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे नेका रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सृविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निदिष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे भिरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की भारा 17 की उप-भारा (3-क) के खण्ड (क) के अभीन गमय-समय पर निर्विष्ट करें।
- 3. सामृहिक बीमा स्कीम के प्रशासन मे. जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रसा जाना, विवरणियों का प्रस्तूस किया जाना, बीमा शीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारो का मंदाय आदि भी है, होने ताले सभी व्ययों का बहुन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित साम्हिक वीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मशारियों की बहुसंख्या की भाषा भे उसकी मख्य बागों का अनुबाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदिक्त करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा दार्मचारी, जो कर्मचारी भविषय निधि का या उक्त अधिनियम के उधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सबस्य है, उसके स्थापन में नियो- जिल किया जाता है तो, नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के स्वस्य के रूप में उसका नाम तरना दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम हो संदत्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बहाए जाते हैं तो, नियोजक सामाहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामहिक वीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनक्ल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनक्षेट हैं।
- 7. सामृहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मत्यू पर इस स्कीम के अधीन संदेश

रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियाजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिदेशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के यरावर रकम का संदाय करेगा।

- 8. सामृहिक बीमा स्कीम के उपवन्धों में कोई भी संबोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संबोधन से कर्म-चारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आय्क्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का य्वितप्रकत अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणविष्ठा, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामृहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रदद की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।
- 11. कियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिदें शितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि वह छूट न दी गई होती तो उदात स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन जाने वाले किसी सदस्य की मृत्यू होने पर उसके हकदार नाम-निदेशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से वौर प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीगा निर्म से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिव्धित करेगा।

[संख्या . एस . -35014/6/84-पी . एफ . -2]

S.O. 912.—Whereas Messrs Santokba Durlabhji Memorial Hospital, Bhawani Singh Marg, Jaipur (RJ/1806) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the sa'd Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-secion (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner. Raiasthan, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submiss on of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme/are reduced in any manner, the exemption shell be l'able to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to nay the premium etc, within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer may payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee Teal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

INo. S. 35014(6)/84-PF.III

का. आ. 913.—मैसर्स आईबेर गडआर्थ निमिटेड, 9 स्थानमा इण्डिप्टिय एरिएा, अलंडर, (राजस्थान/1890), (जिसे इसमें इसके परचात् जक्य स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी अविकाम निधि और एर्कीण उपजन्म अभिनिष्टम, 1952 (1952 का 19) (जिसे उरुपों इसके एक्सान जन्म अभिनिष्टम बहा गया है) की धारा 17 की उपभारा (१क) के अधीन कुट दिए जाने के किए अनेवन किया है; और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का संवाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक धीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फयदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अन्कृल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहवद्ध बीमा स्कीम 1975 (जिसे इसमें इसके पृष्ट्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुजेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपावद्ध अनुसूची में धिनिर्दिष्ट करों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अविध के लिए उक्त स्कीय के सभी उपबंधों के प्रदर्तन से छूट देती हैं।

अनुस्ची

- 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भीष्ठिय निधि आयुक्त, तिमल नाड को ऐसी विषरिणयां भेजेंगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी स्विधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निविध्ट करें।
- 2. रियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 विन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की जारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिस्के अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तत किया जाना, धीमा प्रीमियम का संदाण, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय संस्कार द्वारा उन्मोदित सामृहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन धन किया जाए, तब उम संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मूख्य बातों का अन्वाद, स्थापन के सचना-पटट पर प्रदर्शित करेगा ।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मधारी, जो कर्मधारी शिवय्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भिष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन माँ नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक, सामृहिक वीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम त्रांत्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत बावश्यक प्रीमिष्यम भारतीय जीवन बीमा निमम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि उदल स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायचे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समृचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक उनुक्ल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुन्नेय हैं।
- 7. सामृहिंक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उसे रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारीस/नाम निदेशिती को प्रतिकर के रूप में बोनों रकमों के असर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविषय निधि आयुक्त राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएना और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रशिक्त प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविषय निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियूक्त ववसंर देना ।
- 9. यदि किसी कारणवकः, स्थागन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामृहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्था-पन पहले अपना जुका है अधीन नहीं रह जातें हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायवे किसी रीति से कम हो जाते हैं; तो यह रख्व की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियस तारीस के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का सदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी व्यक्तिकम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निदेशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फाण्यों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।
- 12. उन्तर स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्य होने पर उसके हकदार नामनिवेधितयों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संवाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सूनिधिवत करेगा।

[संस्था एस.-35014/7/84-पी.एफ.-2]

S.O. 913.—Whereas Messrs Eicher Goodearth Limited, 9 Matsya Industrial Area, Alwar, (RJ/1890) (herematter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal helrs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(7)/84-PF.II]

का. आ. 914. — मीसर्म लिखटी इन्टरप्राईजेज सेण्ट्रल हाउम, करनाल (पंजाब/58880), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीण उप-बन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पहचात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

नौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उन्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए चिना ही, भारतीय जीवन निगम की सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायवे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अन्कूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम की 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की भारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त कवित्तयों का प्रयोग करतें हुए और इससे उपाबव्ध अनुसूची में विनिर्विष्ट धतों के अभीग रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की कविध के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

- उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रावेशिक भिक्य निधि आयुक्त पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो कंन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 3. सामृहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिस्के अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरिणयों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामृहिक बीमा स्कीग के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य वातों का अनुवाद, स्थापन के सुचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मधारी, जो कर्मचारी शविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियो- जित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तूरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदल्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपनब्ध फायदों में समृचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकृत हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुक्तय हैं।
- 7. सामृहिक बीमा स्कीम में िकमी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यू पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिसा/नाम निवेशिकों को प्रतिकर के रूप में दोनों रक्तमों के अन्तर के बराबर रक्षम का संदाय करेगा।
- 8. साम्हिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त पंजाब के पूर्व बनुमोबन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों

के हित पर प्रितिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भिवष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

- 9. यदि किसी कारणदश, स्थान के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीम स्कीम के, जिसे स्था-पन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह आते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं; तो यह रद्द की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उम नियत तारीखं के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रखद की जा सकती हैं।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी क्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निवेधितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो अक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।
- 12. उक्त स्थापन के राम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने बाले किसी सदस्य की मृत्यू होने पर उगके हकदार नामनिदें शितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्प'रता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निषम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिध्चित करेगा।

[सं. एस-35014/17/84-पी.एफ.2]

S.O. 914.—Whereas Messrs Liberty Enterprises Central House, Karnal, (PN/5880) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under subsection (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Funds Commissioner, Punjab, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal hers of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee//legal heirs entiled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(17)/84-PF.II]

का. आ. 915 — मैंसर्स राठी एलायस एण्ड स्टील अवसं निमिटेड, मात्स्या इण्डस्ट्रीयल एरिया, अनवर (राजस्थान/ 1790), (जिसे इसमें इसके पहचात जिस्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पदचात जबत अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए अबेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्द्य बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुत्रोय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम को धारा 17 की उप-धारा (2क) व्यारा प्रवत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिद्धिट शर्ती के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अविध के लिए उक्त स्थीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

- 1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान को ऐसी विवरणिया भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी स्विधाएं प्रवान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्विष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की भारा 17 की उप-भारा (3-क) के खण्ड (क) के अभीन समय-समय पर निविष्ट करे।
- 3. सामृहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने धाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामृहिक कीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया आए, तब उस संशोधन की प्रति सथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मूख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के मुखना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सबस्य है, उसके स्थापन में नियो- जित किया जाता है तो, नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के सबस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी भावत आवष्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संबन्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मणारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मणारियों को उपलब्ध फायदों में सम्कित रूप से बृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मणारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुक्रय है।
- ग. सामूहिक बीमा स्कीम मं निस्ती बात कं होते हुए भी, यिद किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिस/नामनिवें शिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रावेशिक भविष्य निधि अध्युक्त राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्म जारियों के हित पर प्रतिकृष प्रभाव पड़ने की संभायना हो, वहां प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युवितयुक्त अवसर देगा।

- 9. यदि किसी कारणवंश, स्थापन के कमें जारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्काम के, जिस स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कमचारियों को प्राप्त होने वाले फायवे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रखद की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संवाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को ध्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रहुद की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सबस्यों के नाम निर्दिशितियां या विशिष्ठ वारिसों को जो, यदि वह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तगत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12: उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस क्लीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यू होने पर उसके हकदार नाम निदेशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भरातीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चिल करेंगा।

[संख्या एस-35014/18/84-पी.एफ.2]

S.O. 915.—Whereas Messrs Rathi Alloys and Steel Works Limited, Matsya Industrial Area, Alwar (RJ/1790) (herematter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter reterred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India m the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Funds Commissioner, Rajasthan, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as aproved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(18)/84-PF.II]

का. आ. 916. — मैर्स यनिवर्गन रेडिणटर्ग निमिटेड, कोण्म्बत्र, मैत्यपालयम रोड, कोणम्बत्र-43 (तिमल नाड-/3131), (जिसे इममें इसके प्रकात अक्त स्थापन कहा गया है) ने वर्णकारी स्विष्ण गिधि और प्रकीण उपवन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके प्रकान उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन कृट दिए जाने के लिए आयेदन किया है;

और केन्द्रीय मरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदास या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फाउदे उठा रहें हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदा में अधिक अन्यक्त हैं जो कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदा में अधिक अन्यक्त हैं जो कर्मचारी निक्षेण सहयस्थ बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके परजात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनक्षेय हैं;

अतः केंग्रीय सरकार, उक्त अभिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2क) द्वारा प्रस्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिदिष्ट शार्ति के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अविध के लिए उक्त स्थीपन के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

- 1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त तिमल नाड को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी स्थिधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण, प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की भारा 17 की उप-धारा (3-क) के सण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्सर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तूत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहुन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामृष्टिक कीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सुचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविषय निधि का या उन्नत अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहुले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियो-जित किया जाता है तो, नियोजक साम्हिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम त्रन्त दर्ज करेगा और उसकी बागत आधरयक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक साम्हिक बीगा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में सम्चित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सागृहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकुल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुभ्रेण है।
- 7. सामृहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मधारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय रक्षम उस रक्षम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मधारी के विधिक बारिस/नामनिदेशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रक्षमों के असार के बराबर रक्षम का संदाय करेगा।
- 8. साम हिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी गं होधन, प्रादेशिक श्विष्य निधि आयुक्त तिमल नाडा के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी मंशोधन से कर्म- चारियों के हित पर प्रतिकृल प्रभाव पड़ने की संशाधना हो, बहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना कुणना कृष्टिकोण स्पष्ट करने का स्विक्तस्वन अवसर देगा।

- 0. यदि वि.सी कारणवश, स्थापन के कर्मजारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चूका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मजारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किमी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छुट रदद की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिकम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक दारिसों को जो, यदि बहु छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होतो, बीमा फायदों के मंदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निदेशितियों/विधिक धारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दक्षा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर मुनिध्चित करेगा ।

[सं. एस-35014/26/84-पी.एफ.2]

S.O. 916.—Whereas Messrs Universal Radiators Limited, Coimbatore, Metyupalayam Road, Coimbatore-43 (TN/3131) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act. 1952 (19 of 1952), (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner. Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and

- when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- .9 Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc, within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(26)/84-PF.II]

का. आ. 917. — मैसर्स सलेम सेन्ट्रल को-आपरेटिट बैंक लिमिटेड, सलेम-63001 और इसकी शाखाएं, (जिसे इसमें इसके परचात् उट्टा स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भिविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके परचाता उट्टा अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पथका अभिदाय या प्रीमियम का गंदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की साम्-हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनक्ल हैं जो कर्मचारी निक्षंप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीस कहा गंगा है) के अधीन उन्हें अनक्षय हैं। अतः, केंग्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त किन्तयों का प्रयोग करते हुए और इससे उपावक अनुसूची में विनिर्दिष्ट शिंसी के बधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अविध के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अभूसूची

- 1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजित प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तीमल नाढ़ को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो कंन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रक्षा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संवाय आवि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय मरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामू-हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की एक प्रति तथा कर्म-चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मूख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सुचना-पट्ट पर प्रदक्षित करेगा।
- 5. यदि ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भिंषण्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भिवष्य निधि का पहले ही सबस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्त वर्ज करेगा और उसकी बाबत बाबरयक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदस्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समिचत रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिमसे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से बिधक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुक्षय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम-निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रक्षमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामृहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त तिमलनाड़ के पर्व अनुमोदन के बिना नहीं िकया जाएगा और जहां िकसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की मभावना हो, वहां प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना वृष्टिकोण स्एब्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

- 9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामृहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणबहा, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमि-यम का संद्राय करने में असफल रहता है, और पालिसी की व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रदद की जा सकती है।
- 1). नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सबस्यों के नाम-निवेधितियों या विधिक/वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अनार्गत होते, बीमा फायदों के संवाय का उत्तर-दायिल्व नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सबस्य की मृत्य होने पर उसके हकदार नाम निवेशितयों/विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीधन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर मृनिष्टिद्द करेगा।

[संख्या एस-35014/8/84-पी एफ 2]

- S.O. 917.—Whereas Messrs The Salem Central Co-operative Bank Limited, Salem-636001 and its branches, (TN/4147) (hereinafter referred to as the said establi hment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);
- S.O. 917.—Whereas Messrs The Salem Central Co-opertive employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);
- Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed, in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Cornoration of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and is any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(8)/84-PF.II]

का. आ. 918. मैसर् काडिसा अन्सस्टेन्सी सर्विसेस, 244, धोदासार, मणिनगर, अहमदाबाद-38008 (गुजरात/1357-बी). (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) से कर्म-भविष्य निभि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए बावेदन किया हैं;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पथक़ अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की साम्-हिक बीमा स्कीम के उधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुजेय हैं।

अत:, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त गिक्तयों का प्रयोग करते हुए और इससे उपायन अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतीं के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अविध के लिए उक्त स्कीम के सभी उपनन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अन्स्ची

- उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रावेशिक अधिष्ठ निधि आयुक्त गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, तक्त अधिनियम की भारा 17 की उप-भारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-गमय पर निर्दिष्ट करे।
- 3. सामृहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का मंदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का गंदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार ब्रारा यथा अन्मोदित सामू-हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संबोधन किया जाए, तब उस संबोधन की एक प्रति तथा कर्म-चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदक्षित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम को अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक सामृहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका बाम तुरन्त दर्ज करेगा बौर उसकी बाबत जावस्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदस्य करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समृचित रूप से बृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुक्रोय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यू पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिस/नाम-निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के जन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशो-भन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना वृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अदसर देगा।
- विव किसी कारणविश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामृहिक बीमा स्कीम के, जिसे

स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

- 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीस के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा नियम नियत करें, प्रीमि-यम का स्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी ब्यतिक्रम की वशा में उन मृत सवस्यों के नाम-निवेशितियों या विश्वक/नारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्क्रीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदी के संदाय का उत्तर-दारित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्य होने पर उसके हकदार नाम निदे शितियों/विधिक दारिनों की बीमाकृत रकम का गंदाय तत्परता से और प्रत्येक दहा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर स्निध्वत करेगा।

[सं. एस- 35014/9/84-पी.एफ.2]

S.O. 918.—Whereas Messrs Cadila Consultancy Services, 244, Ghodasar, Maninagar, Ahmedabad-380008 (GJ/1357-B) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme):

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Funds Commissioner, Gujarat, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act. Within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an

establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything cotnained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is l'kely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any ease within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(9)/84-PF.II]

का. बा. 919. पीसर्स नगर अरबन को-आपरेटिय बैंक लि., अहमदाबाद (महाराष्ट्र/7148) और इसकी शासाएं, (जिसे इसमें इसके पर्वात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निध्य और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पर्वात् उक्त अधिनियम क्रहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए विना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामू-हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में कायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये कायदे उन कायदों से अधिक अनकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पृथ्वात् उक्त स्कीम कहा गया है) के बधीन उन्हें अनुशेष हैं।

अत:, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की छप-धारा (2-क) द्वारा प्रदक्त सक्तिगों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अविध के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट वेती है।

अमुसूची

- 1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजित प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र की ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सृविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्विष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन को भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्विष्ट करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तूत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामू-हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संबोधन किया जाए, तब उस संबोधन की एक प्रति तथा कर्म-चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कम्चारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उनके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक सामृहिक बीमा स्कीम के सदस्य के छूप में उसका नाम तुरन्त वर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्तक करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कींम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समूचित रूप से वृद्धि की जामे की ज्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकृत हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुक्रेय हैं।
- 7. सामृहिक बीमा स्कीम में किसी बाद के होते हुए भी, होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्म- चारी के विधिक बारिस/नाम-निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामृहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भीवष्य निधि आयुक्त दिल्ली के पूर्व अनमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और उन्हों किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रक्रिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भीवष्य निधि कायुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना वृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- यदि किसी कारणविश्वा, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामृष्टिक बीमा स्कीम के, जिसे स्था-

- पन पहले अपना चका है अधीन नहीं रहु जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रदद की जा सकसी है।
- 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीस के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रहव की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिदेशितियों या विधिक बारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्क्रीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।
- 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीमं के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यू होंमें पर उसके हकदार नामनिदें- शितियों/विधिक बारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता सं और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिध्चित करेगा ।

[संख्या एम-35014/10/84-थी. एफ. 2]

S.O. 919.—Whereas Messrs Nagar Urban Co-operative Bank Limited, Ahmedanagar (MH/7148) and its branches (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDUE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month,
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Funds or the Provident Fund of an

establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be lible to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(10) /84PF.II]

का. आ. 920 .— मैंसर्स जै. के. अक्रलिक्स, जय-केय नगर कोटा राज ./3568 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निर्धि और प्रकीर्ण उप-बन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गणा है की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उयत स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की साम्हिक बीमा स्वीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उटा रहे हैं, और ऐसे क्रमचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकृष है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (फिस इसमें ६८६ गरुचात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुक्षेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (२क) व्याग प्रदेश की कार्योग करते हुए और इससे उपाबद्ध अवृस्ची में विधिष्ट शतों के अधीन रहते हुए, उकत स्थापन को तीन वर्ष की अविध के लिए उक्त स्वीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसुची

- 1. जक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान को ऐसी विधरीणयां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी ग्विधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्धिष्ट करे ।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपभारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरिणयों का प्रस्तूत किया जाना, बीमा शिभियम का संवाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारो का संवाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जःएगा ।
- 4. तिरोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित साम्-हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-षट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उन्न अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सहस्य है, उनके स्थापन में नियो-जित किया जाता है तो, नियंजिक साम्हिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तूरना दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समृचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिमसे कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अगुक्षेय हैं।
- 7. सामू हिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्म बारी की मृत्यू पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्म बारी को उस दका में से देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्म बारी के विधिक वारिस/नामनिदे शिती को प्रतिकर के क्य में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।
- 8. साम्हिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजग्शान के पूर्व अनुमोदन के जिना नहीं किया आएगा और अहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व दार्श पारिकृतें को अपना वृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।
- 9. यदि किसी कारणविश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्क्रीम के, जिसे स्था-पन पहले अपना चका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्क्रोम

के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जातें हैं, तो यह छूट रदद की जा सकती है।

- 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारील के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों क नामनिदेशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।
- 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोज्क इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यू होने पर उसके हकदार नामनिदे- शितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से वीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर स्निश्चित करेगा ।

[सं. 85014/15/04-ति.णुः.2] ए. के. भटटराई, अवर सचिव

S.O. 920.—Whereas Messrs J. K. Acrylics, Jay-Kay Nagar, Kota, (RJ/3568) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And Whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance, the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(19)/84-PF. II] A. K. BHATTARAI, Under Secv.